राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

फोर्ब्स की सूची में सिंधू सर्वाधिक कमाई वाली इकलौती भारतीय महिला

>> 12

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 59

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 8 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए तैयार किए खास परिधान

रोहतक : इस विशेष फैब्रिक 'रेजा' से बने कपड़ों की खूबी यह है कि इनसे किसी तरह

की एलर्जी नहीं हो सकती है। गर्मी और बारिश के मौसम में भी यह तापमान को 5 डिग्री तक कम रखता है। एक खूबी यह भी कि यह परिधान एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए भी माकूल है। (पेज-13)

एक नई **आजादी...**

अप्रासंगिक-असामयिक हो चले नियमों-प्रावधानों और उपबंधों से मुक्ति दिलाने वाले संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए जनोपयोगी अधिनियमों पर विशेष सीरीज। आज पढ़ें मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के विशेष प्रावधान। पेज 3

यह दोनों भी देश के काम आ गए तो मुझे दुख नहीं गर्व होगा

राजौरी : एक लाड़ला देश पर गंवाया तो मां ने वतन के नाम कर दिए दो और बेटे। शौर्य चक्र विजेता शहीद औरंगजेब के कश्मीर स्थित गांव सलानी से प्रेरक रिपोर्ट। ● पेज 13

ताकत वतन की हमसे है...

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

मीसाबंदियों को कमलनाथ सरकार देगी पेंशन

भोपाल : इसे राजनीति कह लीजिए या समय का फेर, केंद्र की कांग्रेस सरकार का विरोध करने पर जेल जाने वाले मीसाबंदियों को मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार पेंशन देगी। इनके भौतिक सत्यापन के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भोपाल जिले के 13 मीसाबंदियों को पेंशन देगी। हालांकि, इनके भौतिक सत्यापन में सात महीने का वक्त लग गया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ही निष्प्रभावी हुआ अनुच्छेद 370

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा कर दी है। संसद के दोनों सदनों से इससे संबंधित संकल्प पारित होने के बाद यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही अब जम्मू-कश्मीर में यह अनुच्छेद निष्प्रभावी हो गया है।

आरबीआइ ने घटाया रेपो रेट, ऑटो और होम लोन होंगे सस्ते

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने सुस्त पड़ती अर्थव्यस्था में नया जोश भरने के लिए बुधवार को उम्मीद के मुताबिक कर्ज की दर में 0.35 फीसद की कटौती का फैसला किया। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो रेट (वह रेट जिससे होम लोन, ऑटो लोन जैसे अल्पकालिक कर्ज की दरें प्रभावित होती हैं) को 5.75 फीसद से घटाकर 5.40 फीसद कर दिया है। यह पिछले नौ वर्षों का न्यूनतम रेपो रेट है। इस कटौती के बाद बैंकों के लिए होम लोन और ऑटो लोन को सस्ता करना आसान हो जाएगा। मौद्रिक नीति में ऐसे उपाय भी किए गए हैं जिनसे बैंकों की तरफ से कर्ज का प्रवाह बढ़ सके। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआइ ने सभी तरह के कर्ज की दरों को 0.15 फीसद घटा भी दिया है।

इस वर्ष अब तक रेपो दर 1.10 फीसद नीचे आ चुकी है। इस कटौती के साथ ही दास ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सामने आई चुनौतियों का भी जिक्र किया है। खासतौर पर वैश्विक स्तर पर कारोबार को लेकर बढ़ते तनाव से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसका खामियाजा अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अर्थव्यवस्था का विकास दर अनुमान सात फीसद से घटाकर 6.9 फीसद कर दिया है और आगे इसमें कटौती के संकेत दिए हैं। दास के मुताबिक, 'घरेलू स्तर पर मानसून की स्थिति कमोबेश सही है, लेकिन मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात की स्थिति ठीक नहीं है। शहरी और ग्रामीण मांग कमजोर बनी हुई है।

- रेपो दर में की 0.35 फीसद की गैर-पारंपरिक कमी
- प्रायोरिटी सेक्टर को ज्यादा कर्ज के किए उपाय
- एसबीआइ ने सभी तरह के कर्ज की दरों को 0.15 फीसद घटा भी दिया है

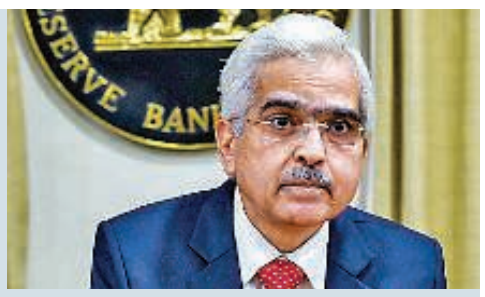

मुंबई में बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास। एएफपी

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हालात को देख कर ही जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को घटाया गया है। हालांकि वित्त वर्ष की चौथी तिमाही से तेजी से हालात सुधरेंगे।'

दास अब तक चार बार मौद्रिक नीति की समीक्षा कर चुके हैं और हर बार उन्होंने रेपो रेट में कटौती की है। दास ने कहा कि मौद्रिक नीति तय करने के लिए गठित समिति (एमपीसी) का इस बार मानना था कि 25 आधार अंकों की कटौती कम है लेकिन 50 आधार अंकों की कटौती कुछ ज्यादा ही होती। इसलिए 35 आधार अंकों पर सहमति बनी है। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि इस वर्ष जून के दौरान रेपो रेट में 0.75 फीसद की कटौती किए जाने के बावजूद बैंकों ने कर्ज की दरों में सिर्फ 0.29 फीसद की औसतन कटौती की है। इस बयान के फौरन बाद एसबीआइ ने कर्ज की अपनी सभी दरों को 0.15 फीसद सस्ता करने का एलान कर दिया। ब्याज दरों में कटौती एक साथ रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, लोहा, उपभोक्ता सामान उद्योग में मांग बढ़ाने में मदद कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की पहल से मांग में बढ़ोतरी तय पेज>>10

मौद्रिक नीति समीक्षा की प्रमुख बातें

- आर्थिक विकास दर के अनुमान को सात फीसद से घटाकर 6.9 फीसद किया
- इस वर्ष चार बार में हुई कुल 1.10 फीसद की कटौती
- मौद्रिक नीति समिति के सभी छह सदस्य रेपो रेट घटाने के पक्ष में, चाहते थे 0.25 फीसद से ज्यादा की कमी
- बैंक अब एनबीएफसी, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र को देंगे ज्यादा कर्ज

बौखलाहट ▶ कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर भारत के फैसले पर पड़ोसी देश ने निकाली भड़ास

पाक ने भारतीय उच्चायुक्त को निकाला

इमरान खान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में लिया फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार के फैसले के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ गई है। पाकिस्तान ने हालात पर विचार के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और उसमें भारत के राजनयिक दर्जे को कम करने का फैसला किया। साथ ही इस्लामाबाद से भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को वापस भेजने का निर्णय लिया।

खिसियाए पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय कारोबार को पूरी तरह से स्थगित करने और सभी द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की समीक्षा का फैसला भी किया है। इस बैठक में पाक के स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त को कश्मीरियों के साथ सौहार्द दिवस के तौर पर और भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का भी फैसला किया गया। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, शिक्षा मंत्री, मानवाधिकार मंत्री, कानून मंत्री, वित्त सलाहकार, सभी सेनाओं के प्रमुख, आइएसआइ के डीजी, विदेश सचिव समेत कुछ अन्य अधिकारी शामिल थे। बैठक में पीएम इमरान खान ने अपनी सेना को चाक चौबंद रहने का भी निर्देश दिया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ नौ हवाई रूट में से तीन को बंद करने की बात भी कही है।

बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 'हम हमारे उच्चायुक्त नई दिल्ली में नहीं रखेंगे और ना ही भारत के उच्चायुक्त हमारे देश में रहेंगे।' पाकिस्तान के इस फैसले के बाद दोनों देशों को एक दूसरे के यहां स्थित उच्चायोग से अपने कर्मचारियों की संख्या भी घटानी होगी। इससे वीजा देने से लेकर दूतावास के अन्य सभी सामान्य कार्यों पर असर होगा। इससे दोनों देशों के बीच करतारपुर कॉरिडोर शुरू करने के लिए हो रही बातचीत पर भी असर पड़ने के आसार हैं।

हास्यास्पद है पाक का फैसला : भारत में जानकारों का कहना है कि पीएम इमरान खान का यह फैसला बहुत हद तक वहां अपनी सरकार की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए है। द्विपक्षीय कारोबार को बंद करने का फैसला तो हास्यास्पद है क्योंकि पुलवामा हमले के बाद भारत ने अपनी तरफ से ही पाकिस्तान से आयात को बंद करने का निर्णय किया था। इसी तरह से भारत के आजादी दिवस को काला दिवस के तौर पर मनाने का उनका फैसला भी झुंझलाहट दिखाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान को अदूरदर्शी बताया और कहा कि इससे भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

खटखटाएगा चीन का दरवाजा : कुरैशी ने इस मुद्दे को लेकर चीन जाने की बात भी कही है। पाकिस्तान ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाने की बात भी कही है। इसके अलावा पाक के पीएम इमरान खान ने सऊदी प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान और ब्रिटेन के पीएम से भी इस बारे में चर्चा की है।

पहले भी टूटे हैं रिश्ते : भारत-पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों का दर्जा कम करने या पूरी तरह तोड़ने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। 1965 और 1971 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध पूरी तरह खत्म हो गए थे। दोनों देशों ने अपने उच्चायोग बंद कर अधिकारियों को वापस बुला लिया था। इसी तरह, 1999 और 2002 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों का दर्जा कम कर लिया था।

पाकिस्तान का आत्मघाती कदम पेज>>11

जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बुधवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें भारत के राजनयिक दर्जे को कम करने का फैसला लिया गया। एएफपी

तनाव घटाने के लिए तुरंत बातचीत की जरूरत : अमेरिका

वाशिंगटन, प्रेट्र : पाकिस्तान की ओर से भारतीय उच्चायुक्त को वापस भेजने और भारत के साथ कूटनीतिक संबंध के दर्जे को घटाने के कुछ घंटों बाद अमेरिका ने दक्षिण एशिया में तनाव घटाने और सैन्य जमावड़ा रोकने के लिए सभी पक्षों के बीच तुरंत बातचीत पर जोर दिया। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों का स्वागत करेगा। हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के लिए माहौल तैयार करने और तनाव घटाने के प्रयासों में मदद जारी रखेंगे।'

आस्था है सबसे बड़ा सुबूत

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या की पुकार

- रामलला की दलील, कोर्ट अयोध्या को घोषित करे भगवान राम का जन्मस्थान
- कहा, भगवान राम ही हैं विवादित 2.77 एकड़ जमीन के मालिक

लाखों भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास यह साबित करने के लिए काफी है कि अयोध्या में विवादित स्थल ही भगवान राम का जन्मस्थान है। अदालत पूरी जन्मभूमि को भगवान राम की जमीन घोषित करते हुए रामलला को उसका कब्जा भी दे दे। सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें भगवान रामलला विराजमान की ओर से राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक का दावा पेश करते हुए दी गईं। बुधवार को कोर्ट ने पक्षकारों के वकीलों से अपना-अपना दावा साबित करने को लेकर कई सवाल किए और सुबूत मांगे। गुरुवार को भी मामले में बहस जारी रहेगी।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर नियमित सुनवाई कर रही है। पीठ के अन्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर हैं। पीठ के समक्ष बुधवार को हिंदू पक्ष निर्मोही अखाड़ा और भगवान राम विराजमान की ओर से दलीलें रखी गईं।

रामायण में है जन्मभूमि का जिक्र : रामलला की ओर से वरिष्ठ वकील के परासरन ने कहा कि वाल्मीकि रामायण में तीन जगह जिक्र है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 1776 में भारत आए यात्री के वर्णन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पूरी जन्मभूमि भगवान राम की है। परासरन ने कहा कि इतने लंबे समय के बाद इस बात का सुबूत देना मुश्किल होगा कि भगवान राम ने यहां जन्म लिया था, लेकिन हिंदुओं की इस स्थान पर अटूट आस्था और विश्वास यह साबित करने के लिए काफी है कि यह राम जन्मभूमि है।

क्या कभी धार्मिक व्यक्तित्व के जन्मस्थान पर सवाल उठा है : संविधान पीठ ने परासरन से सवाल किया कि क्या पहले कभी किसी धार्मिक व्यक्तित्व जैसे पैगंबर मुहम्मद या ईसा मसीह के जन्म को लेकर ऐसा सवाल उठा है। क्या कभी ईसा मसीह के बेथलेहम में जन्म लेने का सवाल कोर्ट में रहा है। परासरन ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है वह पता करके बताएंगे।

कोर्ट ने परासरन से पूछा कि क्या भगवान की मूर्ति का कालखंड परखने के लिए उसकी कार्बन डेटिंग हुई है। परासरन ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, वह उस दौरान रिसीवर की रिपोर्ट का हवाला कोर्ट को दे रहे थे। उसी समय कोर्ट ने अयोध्या में 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात मूर्तियां रखने से संबंधित सवाल पूछने शुरू किए। कोर्ट ने पूछा कि क्या मूर्तियां रखना गलत नहीं था और वह गलती लगातार जारी नहीं रही। परासरन ने कहा कि ऐसा करना गलत था कि नहीं यह इस पर निर्भर करता है कि वह ढांचा (जो ढह गया है) मंदिर था या मस्जिद। उन्होंने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि ऐसा होना लगातार चलने वाली गलती थी तो भी कोर्ट ने उसमे दखल देकर और वहां रिसीवर नियुक्त करके उस गलती को रोक दिया था। इस बीच जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा की कि मूर्तियां पहले चबूतरे पर रखी थीं जिन्हें उठाकर अंदर रखा गया था। (पेज-3 भी देखें)

जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर हैं। बुधवार को अजीत डोभाल ने स्थिति का निरीक्षण करते हुए शोपियां जिले में स्थानीय लोगों के साथ खाना खाया और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने लोगों से पूछा कि कैसा लग रहा है? लोगों ने कहा, हमें माहौल अच्छा चाहिए, तो डोभाल ने कहा, सब लोग आराम से रहें, ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। आपकी सलामती, आपकी हिफाजत ही हमारा फर्ज है। डोभाल ने मंगलवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की थी। एएनआइ (विस्तृत खबर-पेज 6)

राहुल के खिलाफ हिसार में धरने पर बैठे कांग्रेसी

जासं, हिसार : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में आए कांग्रेस के निर्वतमान अध्यक्ष राहुल गांधी का उनकी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। हिसार के राजगढ़ रोड स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस जिला महासचिव वीरेंद्र हुड्डा ने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया और धारा 370 के विरोध को देशहित के खिलाफ बताया। इसके साथ ही, हुड्डा ने राहुल को चेतावनी दी कि अगर देशहित के खिलाफ उन्होंने राजनीति जारी रखा तो वे दिल्ली स्थित उनके आवास के बाहर भी धरना देंगे। हुड्डा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाते हुए अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले से पूरा देश जश्न मना रहा है। इसके उलट राहुल गांधी के नेतृत्व में बिल का विरोध किया जा रहा है, जो कतई जायज नहीं है।

अनुच्छेद 370 पर थमा नहीं है कांग्रेस का घमासान पेज>>3

पंचतत्व में विलीन हुईं सुषमा स्वराज

नई दिल्ली में बुधवार को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए भाजपा मुख्यालय में रखा गया, जहां राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत विभिन्न नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को सैल्यूट करते उनके पति स्वराज कौशल और बेटी बांसुरी। प्रेट्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पीएम सहित कई राज्यों के सीएम अंतिम संस्कार में हुए शामिल
- अंतिम दर्शन को आवास से श्मशान तक जुटा रहा लोगों का हुजूम

भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गईं। लोधी रोड स्थित विद्युत शवदाह गृह में राजकीय सम्मानपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुत्री बांसुरी स्वराज ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके पति स्वराज कौशल और बेटी बांसुरी ने उन्हें सैल्यूट भी किया।

लोधी रोड पर सुषमा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे नेताओं की आंखें नम थीं। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ तमाम नेताओं ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और रो पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें सहारा देकर बैठाया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व देशभर के दिग्गज नेता अपनी प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचे। श्रद्धांजलि देने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। इस दौरान कई नेता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और फूट-फूटकर रो पड़े। सुषमा को उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उनकी पुत्री प्रतिभा आडवाणी, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला, बसपा सुप्रीमो मायावती, योग गुरु बाबा रामदेव, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी सहित देशभर के दिग्गज नेता शामिल हुए।

समय से घंटों पहले पहुंचे लोग पेज>>5

उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के सीएम मनोहरलाल, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा सहित तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद उनके अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहे।

घर पर सुबह से ही शुरू हो गया था श्रद्धांजलि देने का सिलसिला :

बेहतरीन

सदन में करीब 19 घंटे का व्यवधान भी आया, लेकिन सदन ने तय समय से ज्यादा बैठक करके करीब 28 घंटे ज्यादा काम करने का भी रिकॉर्ड बनाया

कामकाज में राज्यसभा ने तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पारित हुए 32 विधेयक, पिछले 14 साल में हुई सबसे ज्यादा 35 बैठकें
- इससे पहले वर्ष 2002 में पारित हुए थे 35 विधेयक

संसद का बजट सत्र रिकॉर्ड स्थापित कर गया। एक तरफ जहां लोकसभा में दो दशक का रिकॉर्ड टूटा, वहीं राज्यसभा में कामकाज के लिहाज से 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार 32 विधेयक पारित हुए हैं। इससे पहले 2002 में 35 विधेयक पारित हुए थे। इसके साथ ही सदन ने पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा 35 बैठकों का भी रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले वर्ष 2005 में 38 बैठकें हुई थीं।

राज्यसभा को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने से पहले सभापति वेंकैया नायडू ने बताया कि इस बार जो 32 विधेयक पारित हुए हैं उनमें तत्काल तीन तलाक, मोटरयान संशोधन विधेयक, आरटीआइ संशोधन, मेडिकल कमीशन और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सबसे अहम हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्र कामकाज के लिहाज से 104 फीसद उपयोगी रहा है जो पिछले 17 सत्रों में सबसे अधिक है। इससे पहले वर्ष 2014 के 232वें सत्र में 105 फीसद से ज्यादा कामकाज हुआ था। सदन में करीब 19 घंटे का व्यवधान भी आया, लेकिन सदन ने तय समय से ज्यादा बैठक करके करीब 28 घंटे ज्यादा काम करने का भी रिकॉर्ड बनाया। सभापति ने इस दौरान सदस्यों के व्यवहार को लेकर खुशी भी जताई और कहा इनमें बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपनी मातृभाषा में भी सवाल पूछे जो सबसे बड़ी खुशी की बात है। मालूम हो कि लोकसभा में भी इस सत्र में 35 विधेयक पारित हुए हैं।

वेंकैया नायडू फाइल फोटो

कांग्रेस के मुख्य सचेतक सहित पांच सदस्यों के इस्तीफों की रही चर्चा

राज्यसभा का बजट सत्र कामकाज के साथ-साथ कई और मामलों में भी उल्लेखनीय रहा। इसमें सबसे ज्यादा रोचक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश होने से ठीक पहले कांग्रेस के मुख्य सचेतक भुनेश्वर कालिता का इस्तीफा था। यह सुनकर कांग्रेसी सदस्य भी भौचक रह गए थे। इसके अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह सहित समाजवादी पार्टी के नीरज शेखर, संजय सेठ और सुरेंद्र सिंह नागर ने भी इसी सत्र में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। जिसे तुरंत स्वीकृत भी कर लिया गया। इनमें से संजय सिंह और नीरज शेखर भाजपा में शामिल हो गए हैं। तेदेपा के भी चार सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था।

1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे इस वर्ष के अंत तक लगाए जाएंगे राजधानी में। सभी कैमरे केंद्रीकृत सेंटर से जुड़े होंगे। यह जानकारी दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 अगस्त 2019

न्यूज गैलरी

एसएससी पेपर लीक मामले में आरोप पत्र दाखिल

नई दिल्ली : कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में सीबीआइ ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में संदीप माथुर, धर्मेंद्र और अक्षय कुमार मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि एसएससी ने 2018 में सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया था। इस परीक्षा के लिए नोएडा की एक आइटी कंपनी के साथ करार किया गया था। यह परीक्षा सफल नहीं हो सकी, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। सीबीआइ ने 22 मई 2018 को आइटी कंपनी, एसएससी के अज्ञात अधिकारियों और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि पेपर लीक करने वाले गिरोह का मुखिया अक्षय था। वह ही पेपर लीक करता था। (जासं)

यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए कार्यों का होगा भौतिक सत्यापन

ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस-वे पर आइआइटी के सुरक्षा उपायों को लागू कराने का पहला चरण पूरा हो गया है। प्राधिकरण के सीईओ शनिवार को ग्रेनो से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे का निरीक्षण कर जेपी इंफ्राटेक के पहले चरण का कार्य पूरा करने के दावे की हकीकत को जांचेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा निगरानी समिति के आदेश पर यमुना प्राधिकरण ने आइआइटी दिल्ली से एक्सप्रेस वे का सुरक्षा ऑडिट कराया था। आइआइटी दिल्ली की तरफ से दिए गए सुझावों को अलग-अलग चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण में एक्सप्रेस वे पर ब्रिज के ऊपर से गुजर रही सड़क के बीच वाले स्थानों पर क्रैश बीम बैरियर लगाने, तार फेंसिंग व किनारे लगे क्षतिग्रस्त क्रैश बीम बैरियर को दुरुस्त कराने के जेपी इंफ्राटेक को निर्देश दिए गए थे। कंपनी ने दावा किया है कि उसने क्रैश बीम बैरियर लगाने का कार्य पूरा कर लिया है। (जासं)

हेरोइन के साथ दो अफगानी नागरिक गिरफ्तार

नई दिल्ली : क्राइम ब्रांच ने दो अफगानी नागरिकों मसजिदी फेरोज और जबीउल्लाह रहीमी को छह सौ ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। एडिशनल कमिश्नर राजीव रंजन ने बताया कि दोनों अफगानी नागरिकों को गीता कॉलोनी से पकड़ा गया। उनके पास से 300-300 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ में मसजिदी ने बताया कि वह पांच वर्ष का था, उस समय भारत में आया था। यहां आने के बाद उसने हींग गोली, चूरन-चटनी और जड़ी-बूटी आदि बेचना शुरू किया था। इसी से वह अपना खर्च चला रहा था। करीब दो वर्ष पहले वह रहीमी से मिला। उसके साथ मिलकर उन्होंने हेरोइन की तस्करी शुरू कर दी। पूछताछ में रहीमी ने बताया कि वह पिछले दस वर्ष से हेरोइन की तस्करी कर रहा है। (जासं)

बैंकों से धोखाधड़ी करने वाले गिरफ्तार

शिकंजा ▶ एसटीएफ की जांच में हुआ गैंग का पर्दाफाश, लोन लेकर करते थे फर्जीवाड़ा

44 चेकबुक, 56 डेबिट-क्रेडिट कार्ड सहित अन्य दस्तावेज और सामान बरामद

जागरण संवाददाता, नोएडा

एसटीएफ की गिरफ्त में धोखाधड़ी के आरोपित। इनके पास से बड़ी संख्या में पैन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र बरामद हुए। फोटो : सौजन्य से एसटीएफ

फर्जी दस्तावेज पर कंपनियां खोल कर्मचारियों के नाम की सैलरी स्लिप तैयार कर 10 से अधिक बैंक व वित्तीय संस्थाओं से करोड़ों रुपये का पर्सनल व कार लोन लेकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित चार आरोपितों को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने बुधवार दोपहर सेक्टर 122 से गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान सेक्टर 82 निवासी मनोज कुमार ठाकुर, संजय कुमार ठाकुर, अनिमेष कुमार ठाकुर और सेक्टर-22 निवासी अजीत शर्मा के रूप में हुई। तीन आरोपित भाई हैं और सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं, जबकि चौथा मूलरूप से मुजफ्फरपुर का रहने वाला है।

आरोपितों की निशानदेही पर एसटीएफ ने 42 पैन कार्ड, 10 आधार कार्ड, 24 वोटर कार्ड, 21 सिम रैपर, 21 पासबुक, 44 चेकबुक, 56 डेबिट कार्ड, टेक डेटा नाम की कंपनी के 30 आइ कार्ड, 35 सैलरी स्लिप, तीन ड्राइविंग लाइसेंस, एक नेपाली पासपोर्ट, 17 मोहर, तीन लैपटॉप, 58 सौ रुपये की पुरानी भारतीय करेंसी, 60 हजार नेपाली करेंसी, 23 हजार नकदी, 25 मोबाइल, तीन कार व एक केटीएम बाइक सहित अन्य सामान बरामद किया है। कोतवाली फेज तीन ने आरोपितों को जेल भेज दिया है।

पिछले दिनों आइसीआइसीआइ बैंक के अधिकारियों ने एसटीएफ के आइजी व एसएसपी से फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी टेकडेटा कंपनी बना कर उसके सैलरी खाते बैंक में खुलवाने व उस पर पर्सनल लोन व क्रेडिट कार्ड लेकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के संबंध में शिकायत की थी। उस प्रकरण की जांच में संजय ठाकुर का नाम सामने आया। एसटीएफ ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसके बाद संजय ठाकुर की निशानदेही पर एसटीएफ ने बुधवार दोपहर सेक्टर 122 स्थित एक मकान पर छापेमारी की तो गैंग में शामिल तीन अन्य आरोपित पकड़े गए व मौके से सभी सामान व दस्तावेज बरामद हुए। 10वीं पास 38 वर्षीय मनोज ठाकुर इस गैंग का मास्टरमाइंड है, जो अपने भाइयों व एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर गैंग चला रहा था। एसटीएफ की जांच में अबतक इनके 56 बैंक अकाउंट का पता लगा है।

दो बैंक अकाउंट में मौजूद करीब 22 लाख रुपये फ्रीज कराए गए हैं। आरोपित अपनी फर्जी कंपनी के फर्जी कर्मचारी के नाम पर पर्सनल व कार लोन लेते थे और एक-दो किस्त देकर फरार हो जाते थे। अब तक की जांच में 10 से अधिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से कई करोड़ रुपये लोन लेकर गायब हो चुके थे। एसटीएफ इस प्रकरण की जांच कर रही है।

काले रंग की उबर टैक्सी से आया था आरोपित

जेएनयू छात्रा से दुष्कर्म

दिल्ली-एनसीआर के 3141 कैब चालकों से की जाएगी पूछताछ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पढ़ने वाली 21 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म मामले में मंदिर मार्ग पुलिस छात्रा द्वारा दिए गए बयान की जांच करने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि छात्रा अब तक अलग-अलग तरह की बात बता रही है। इसलिए पुलिस को जांच करने में दिक्कत आ रही है। छात्रा ने काले रंग की उबर से जेएनयू जाने के लिए बुक कराने की बात कही है। लिहाजा पुलिस द्वारा काली कैब की जानकारी मांगने पर दिल्ली-एनसीआर में ऐसी 3141 कैब पाई गई हैं। उक्त सभी के चालकों से पूछताछ की जाएगी।

पुलिस को यह भी शक है कि छात्रा कुछ बातें झूठ बोल रही है। लिहाजा सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। छात्रा ने बयान में कहा है कि शुक्रवार दो अगस्त की रात आठ-नौ के बीच में उसने किसी राहगीर की मदद से जेएनयू जाने के लिए कैब बुक करवाई थी। पंचकुइयां स्थित बौद्ध मंदिर के सामने छात्रा के पास काले रंग की कैब आई थी, जिससे वह जेएनयू के लिए निकली थी। नेल्सन मंडेला रोड पर एक बस स्टैंड के पास जाकर चालक ने उसे हवस का शिकार बनाया था। कैब पर लगे नंबर प्लेट के बारे में पूछने पर छात्रा ने बताया है कि अंत में 95 लिखा था। पुलिस ने जब शुक्रवार शाम साम बजे से रात नौ बजे तक पंचकुइयां रोड बौद्ध मंदिर के सामने से गुजरने वाली काली उबर कैब का डाटा खंगाला तब काले रंग की 43 कैब मिलीं, जो उस ओर से होकर गुजरीं। उक्त सभी के चालकों से मंदिर मार्ग थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि कैब का पता चलते ही चालक का पता लग जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली जिला पुलिस के 25 पुलिसकर्मियों को जांच में लगाया गया है। बौद्ध मंदिर में छात्रा के जाने की सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हो चुकी है। वहां उसका बैग चोरी हो गया था। छात्रा का कहना है कि शिकायत में बैग के बारे में इसलिए जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसमें अधिक पैसे नहीं थे। पुलिस को छात्रा का मोबाइल भी उसके छात्रावास से बरामद हो गया। वह स्मार्ट फोन का इस्तेमाल नहीं करती थी इसलिए जेएनयू से बाहर निकलने पर वह अपना फोन लेकर नहीं जाती थी। घटना के बाद से छात्रा अब तक सदमे में है। उस पर अब तक नशे का प्रभाव है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि कैब चालक ने छात्रा को आखिर कौन सा नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वह अब तक नॉर्मल नहीं हो पाई है।

अब नहीं बचा दिल्ली का कोई पूर्व मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछले एक महीने में ही दिल्ली ने अपने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को खो दिया

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से राजनीति के एक युग का अवसान हो गया। दुखद तथ्य यह है कि सुषमा के निधन के साथ ही अब दिल्ली का कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री जीवित नहीं बचा है। निराशाजनक यह भी है कि पिछले एक महीने में ही दिल्ली ने अपने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को खो दिया। यह भी संयोग ही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं दो महिलाओं का निधन करीब-करीब एक ही तरह से हुआ। सुषमा के निधन से ठीक 17 दिन पहले ही शीला दीक्षित का निधन हुआ था।

पहले दिल्ली विधानसभा अंतरिम हुआ करती थी। वर्ष 1952 से 1956 तक दो मुख्यमंत्री रहे। 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक दो साल 332 दिन तक चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद एक नवंबर 1956 तक एक साल 263 दिन तक गुरुमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री रहे। 1956 से वर्ष 1993 तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया।

इसके बाद साल 1993 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा की ओर से मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। वह दो दिसंबर 1993 से फरवरी 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद साहिब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। वह फरवरी 1996 से अक्टूबर 1998 तक दो साल तक मुख्यमंत्री रहे। वर्मा के बाद सुषमा स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाला। वह 12 अक्टूबर 1998 से तीन दिसंबर 1998 तक यानी करीब 52 दिन की मुख्यमंत्री रहीं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव सुषमा को हासिल हुआ।

इसके बाद हुए चुनाव में भाजपा की हार हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं। वह 1998 से 2013 तक लगातार तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। बीते साल अक्टूबर में मदन लाल खुराना का भी देहांत हो चुका है।

एफआइआर में उर्दू व फारसी के शब्दों के इस्तेमाल पर सीपी से जवाब तलब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : एफआइआर में उर्दू व फारसी के शब्दों का इस्तेमाल करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस आयुक्त (सीपी) से कहा कि वह बताएं कि ऐसा क्यों किया गया है, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि लोगों का समझना होता है कि एफआइआर में क्या लिखा है। ऐसे में इसमें सरल शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए न कि उच्च ध्वनि वाले शब्दों का। पुलिस बड़े पैमाने पर लोगों के लिए काम करती है न कि उनके लिए जिन्होंने उर्दू व फारसी में उपाधि ली है।

पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को इस पर विस्तृत व्याख्या करते हुए शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। मुख्य पीठ ने कहा कि पुलिस यह बताए कि उर्दू व फारसी शब्दों का इस्तेमाल शिकायतकर्ता ने शिकायत में किया था या फिर पुलिस ने जांच में किया है। गौरतलब है कि अधिवक्ता विशालाक्कषी गोयल की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से मांग की थी कि दिल्ली पुलिस को उर्दू व फारसी में एफआइआर दर्ज न करने के निर्देश दिए जाएं।

विशेष शिक्षक नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिव्यांगों के स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार व मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने दिल्ली सरकार व मुख्य सचिव से पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। पीठ ने पूछा कि आखिर अब तक दो जुलाई के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। याचिका पर अगली सुनवाई 16 मार्च 2020 को होगी।

हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने दो जुलाई को अपने आदेश में दिव्यांगों को शिक्षित करने वाले व उम्र सीमा पार कर चुके दो अभ्यर्थियों को विशेष शिक्षक के पद पर नियुक्त करने को कहा था। साथ ही सरकार से इस तरह के अभ्यर्थियों की कमी को देखते हुए उम्र सीमा पार चुके अभ्यर्थियों को भी शिक्षक के पद पर बहाल करने पर विचार करने को कहा था। पीठ ने चार सप्ताह के अंदर इस पर अमल करने को कहा था।

याचिकाकर्ता सैयद मेहदी ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर कर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अभी तक शिक्षकों की बहाली को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अवमानना याचिका में उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि दिव्यांगों के स्कूलों में शिक्षकों के एक हजार पद रिक्त हैं। इसके बावजूद सरकार उन पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है।

दमकल विभाग में रिक्त पदों को भरने के बारे में पूछा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दमकल विभाग में खाली पड़े पदों को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए। याचिका के अनुसार दमकल विभाग में 1500 से अधिक पद खाली हैं। दमकल विभाग ने मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष बताया कि फायर ऑपरेटर के तौर पर 500 लोगों को भर्ती किया गया है, जबकि इतने ही लोगों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त 706 कर्मियों की भर्ती शुरू करने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से अनुरोध करते हुए पत्र लिखा गया है। इस पर मुख्य पीठ ने दमकल विभाग से कहा कि वह शपथ पत्र दाखिल करके बताए कि रिक्त भर्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। गौरतलब हे कि उपहार सिनेमा के पीड़ितों की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहीं नीलम कृष्णमूर्ति ने दावा किया है कि त्रासदी के 21 साल बीत जाने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में दमकल विभाग में कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि यह आम लोगों के जीवन सुरक्षा से जुड़ा विषय है। 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में बार्डर फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। आग पास के ट्रांसफार्मर में लगी थी, जो कि इमारत के पास खड़ी कारों में फैल गई।

हाई कोर्ट ने दायर याचिका के अनुसार दिल्ली में दमकल विभाग में 1500 से अधिक पद खाली हैं। (फाइल फोटो)

बाइक बोट घोटाले से संबंधित ईडी का नोटिस पहुंचा दादरी

राजीव वशिष्ठ, दादरी

कोट गांव स्थित कंपनी कार्यालय पर धरना दे रहे कई निवेशकों को मिला नोटिस

प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने बाइक बोट कंपनी के पीड़ित निवेशकों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा है। बुधवार को दादरी के कोट गांव स्थित बाइक बोट कंपनी कार्यालय पर धरना दे रहे कई निवेशकों को ईडी के नोटिस मिले तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बताया कि जिन निवेशकों ने पहले एफआइआर दर्ज कराई थी, उसी क्रम में निवेशकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

ज्ञात हो कि एक जून से दादरी के कोट गांव स्थित बाइक बोट कंपनी के कार्यालय पर सैकड़ों निवेशक रकम वापसी व आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। पिछले दो माह में निवेशक दो बार भूख हड़ताल व जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग कर चुके हैं। बुधवार को ईडी का नोटिस मिलने से धरनारत निवेशकों में खुशी का लहर दौड़ गई। निवेशक राजकुमार ने बताया कि दादरी कोतवाली में पहली एफआइआर दर्ज कराने वाले राजस्थान के निवेशक सुनील कुमार मीणा, मेरठ के धर्मेंद्र कुमार व दिल्ली के संतोष कुमार गुप्ता को बुधवार को ईडी लखनऊ कार्यालय की मुहर लगा नोटिस मिला है।

ईडी के सहायक निदेशक ने पीड़ितों को साक्ष्य पेश करने के लिए लखनऊ बुलाया : प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक देवेंद्र सिंह ने बाइक बोट के पीड़ितों को नोटिस भेजकर सात अगस्त से दस्तावेज व साक्ष्यों के साथ लखनऊ स्थित कार्यालय में बयान देने के लिए बुलाया था। पीड़ित संतोष कुमार, सुनील मीणा व अन्य शिकायतकर्ताओं की तरफ से बाइक बोट टैक्सी यूनियन के महासचिव नंद कुमार गुप्ता सुनवाई के दौरान ईडी के समक्ष मौजूद रहे। ईडी के अलावा दिल्ली पुलिस व गौतमबुद्ध नगर पुलिस भी बाइक बोट घोटाले की जांच कर रही है।

आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार का इनाम घोषित : पुलिस ने फरार आरोपितों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। बीएन तिवारी, भूदेव सिंह, पुष्पेंद्र, करनपाल, दीप्ति बहल, रीता चौधरी, विदेश भाटी समेत दर्जनों फरार आरोपितों पर पुलिस विभाग द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

फ्लैट नहीं लेना तो 90 दिन में लौटाएं, नहीं तो जब्त होगी आवेदन राशि

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय योजना में निकले फ्लैट को यदि कोई आवेदक नहीं खरीदना चाहता, तो 90 दिन के डीडीए को सूचित कर दें नहीं तो उनकी आवेदन की राशि जब्त हो जाएगी।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि डीडीए की ओर से फ्लैट लौटाने वाले आवेदकों को एक सप्ताह में आवेदन राशि लौटा दी जाएगी। फ्लैट लौटाने का सिलसिला सफल आवंटियों को आवंटन और मांग पत्र जारी करने के 15 दिन बाद तक चलेगा। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि कि मांग और आवंटन पत्र जारी होने के 15 दिन में फ्लैट सरेंडर करने पर कोई राशि नहीं काटी जाएगी। इसके बाद 16 से 30 दिन तक फ्लैट सरेंडर करने पर 10 फीसद आवेदन राशि काट कर वापस की जाएगी। वहीं, 31 से 90 दिन तक फ्लैट सरेंडर करने का आवेदन करने पर 50 फीसद राशि काटकर वापस की जाएगी। इसके बाद सरेंडर करने पर आवेदन राशि जब्त हो जाएगी। डीडीए की ऑनलाइन आवासीय योजना-2019 में 16 दिन में ही करीब 40 प्रतिशत आवंटियों ने फ्लैट लौटा दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 3390 फ्लैट नरेला में लौटाए गए। इसके अलावा डीडीए ने बैंकों को योजना में असफल आवेदनकर्ताओं को एक सप्ताह में आवेदन राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं।

प्ले स्कूल की तरह आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा माहौल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर पाठ्यक्रम लांच करने व आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन बांटे जाने के लिए बुधवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्ले स्कूल की तरह माहौल मिलेगा। दिल्ली सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत 10 हजार लोगों को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं।

अर्ली चाइल्डहुड केयर पाठ्यक्रम लांच करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल जैसा माहौल देने की कोशिश की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। यहां काम कर रहीं सेविकाओं को अब 11-12 रजिस्टर नहीं रखने होंगे। वे स्मार्टफोन के जरिये ही पूरी जानकारी दे सकेंगी। वर्ष 2015 से पहले आंगनबाड़ी केंद्र केवल खाना बांटने के सेंटर की तरह जाने जाते थे। इसमें हमने बदलाव किया है। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं से कहा कि दिल्ली के छह लाख बच्चों का भविष्य उनके हाथों में है। आप दिल्ली के बच्चों का भविष्य संवारें। हम आपको कोई तकलीफ नहीं होंने देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब देश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सरकारी स्कूलों की बात की जाती है तो दिल्ली में अच्छे काम का जिक्र होता है। इसी तरह आने वाले साल में हम आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इस तरह के बदलाव करना चाहते हैं जहां बच्चों को बुनियादी शिक्षा और उचित पोषक आहार मिले। जिन आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, उनके मोबाइल का खर्च भी दिल्ली सरकार ही वहन करेगी। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व मुख्य सचिव विजय देव भी मौजूद थे।

सिसोदिया बोले, बच्चों के दिमाग को 80 फीसद विकसित करने पर काम हुआ है शुरू : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सारी दुनिया में छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रही पूर्व की व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि छह साल में बच्चे का 80 फीसद दिमाग विकसित हो जाता है, लेकिन हम यहां केवल खाना खिलाने तक ही दिलचस्पी रखते हैं। अब उनके खुश रहने, उनके दिमाग को विकसित करने पर काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आंगनबाड़ी सेविकाओं के हितों का ध्यान रख रहे हैं। उनका वेतन पांच हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। सिसोदिया ने आंगनबाड़ी सेविकाओं से बात कर उनकी समस्याओं को भी जाना।

इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित आंगनबाड़ी सेविकाओं और सुपरवाइजर के बीच स्मार्ट फोन वितरण कार्यक्रम में बच्चों को दुलार करते अरविंद केजरीवाल। साथ में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। संजय

कवायद

ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया था पहला उपदेश, इस वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए इसका है विशेष महत्व

अजंता-एलोरा की श्रेणी में शामिल होगा सारनाथ स्मारक

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

सारनाथ स्मारक वाराणसी के 10 किमी पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। (फाइल फोटो)

छह सौ पन्नों का होगा डोजियर

सारनाथ के ऐतिहासिक स्मारक काफी समय से यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में हैं। एएसआइ की महानिदेशक ने करीब तीन माह पहले इस स्मारक के लिए डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए थे। यह डोजियर करीब 600 पन्नों का होगा। इसमें आधा काम पूरा हो चुका है। अप्रैल 2015 में ही सारनाथ आदर्श स्मारक की श्रेणी में आ गया था। भारत सरकार ने देश के 25 प्राचीन स्थानों को आदर्श स्मारक घोषित किया था। इनमें एक सारनाथ स्थित प्राचीन स्मारक भी है। तब से पर्यटन के क्षेत्र में सारनाथ का अंतरराष्ट्रीय महत्व और बढ़ा है।

प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक सारनाथ का स्मारक देश-दुनिया में पहले ही पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। भगवान बुद्ध ने यहां अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए इस स्थान का अलग ही महत्व है। लेकिन अब यह स्मारक ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाओं की श्रेणी में शामिल हो सकता है। दरअसल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) विभाग ने वाराणसी स्थित सारनाथ स्मारक को विश्व धरोहर में शामिल कराने की कवायद शुरू कर दी है।

एएसआइ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सारनाथ स्मारक का प्रस्ताव यूनेस्को भेजने के लिए डोजियर तैयार किया जा रहा है। इसे फरवरी में होने वाली संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) में प्रस्तुत किया जाएगा। इस पर जून 2020 में होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद इसे लेकर यूनेस्को अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद अगले साल मौके पर जाकर यूनेस्को की टीम निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपेगी। इसी के आधार पर जून 2021 की बैठक में सारनाथ स्मारक को विश्व धरोहर में शामिल करने के फैसले पर निर्णय लिया जाएगा।

बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थों में से एक है सारनाथ : सारनाथ स्मारक वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया और जो बौद्ध मत के प्रचार-प्रसार का आरंभ माना जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थों में से एक है। यहां अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, धामेख स्तूप, चौखंडी स्तूप आदि दर्शनीय स्थल हैं। भारत का राष्ट्रीय चिह्न यहीं के अशोक स्तंभ के मुकुट की अनुकृति है।

मुहम्मद गोरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद वर्ष 1905 में खोदाई का काम प्रारंभ कराया गया था। उसी समय बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इतिहास के विद्वानों का ध्यान इधर गया। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में दृष्टिगत होता है। उन्होंने ही सारनाथ में स्तूप एवं स्तंभ का निर्माण करवाया था।

ग्रेटर नोएडा में महिला पुलिसकर्मी ने रचाई हिस्ट्रीशीटर से शादी

प्रवीण विक्रम सिंह, ग्रेटर नोएडा

वर्ष 2002 में बनी बॉलीवुड फिल्म गुनाह की कहानी को जिले के हिस्ट्रीशीटर बदमाश राहुल ठसराना और उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला कांस्टेबल ने फिर तरोताजा कर दिया है। गुनाह फिल्म में अभिनेत्री बिपाशा बसु एक पुलिसकर्मी के किरदार में थीं और अभिनेता डीनो मोरिया ने बदमाश का रोल अदा किया था। फिल्म में दोनों के बीच प्रेम हो गया था। ठीक उसी तर्ज पर दनकौर कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर बदमाश राहुल ठसराना के इश्क में ग्रेटर नोएडा में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी इस कदर डूब गई कि दोनों ने शादी रचा ली। राहुल इस समय जमानत पर है। शादी के बाद दोनों ठसराना गांव से दूर कहीं अज्ञात जगह पर रह रहे हैं। राहुल पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। राहुल 2014 में जिले में हुए बहुचर्चित मनमोहन गोयल हत्याकांड में जेल गया था। राहुल पांच हजार का इनामी बदमाश भी रह चुका है।

राहुल जब जेल में बंद था तो अक्सर कोर्ट में पेशी पर आता था। इस दौरान उसे कोर्ट परिसर के बंदी गृह में रखा जाता था। महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी बंदी गृह पर थी। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ा। राहुल के जेल से छूटने के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद महिला कांस्टेबल तो अपने ससुराल ठसराना गांव आती-जाती रहती है, लेकिन राहुल को कभी गांव में नहीं देखा गया।

अनिल दुजाना गिरोह का शार्प शूटर है बदमाश : 2014 में दनकौर में हुए व्यापारी मनमोहन गोयल हत्याकांड के बाद पुलिस ने अनिल दुजाना गिरोह के बदमाशों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनमें राहुल ठसराना भी शामिल था। तब पता चला था कि राहुल अनिल दुजाना गिरोह का शार्प शूटर है। जमीन कब्जे के विवाद में कुख्यात अनिल दुजाना ने शूटरों से व्यापारी की हत्या करवाई थी।

17,403

किमी वन मार्गों का रखरखाव अब उत्तराखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत किया जाएगा। 71.05 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में 13671.177 किमी पैदल, 3263.602 किमी कच्चे और 467.880 किमी पक्के वन मार्ग हैं।

1982 में पड़ी डकैती में चले गए कई सुबूत : निर्मोही अखाड़ा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कोर्ट ने कहा कि ये रिकॉर्ड तो राजस्व विभाग के पास होगा, लेकिन वकील ने रिकॉर्ड पेश करने में असमर्थता जताई
- अदालत ने कहा, विवादित स्थल पर कब्जे और प्रबंधन को लेकर सुबूत देने ही होंगे

अयोध्या में राम जन्मभूमि की पूरी जमीन पर अपना हक जता रहा निर्मोही अखाड़ा अपने दावे में सुबूत तो देगा, लेकिन पूरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि वर्ष 1982 में पड़ी डकैती में जमीन के खसरा संबंधी दस्तावेज गायब हो गए थे। अखाड़ा ने राम जन्मभूमि के विवादित भूमि से एक तिहाई हिस्सा देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

बुधवार को सुबह निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील जैन ने कब्जा साबित करने के लिए जब बहस शुरू की तो कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने उनसे कहा कि वह विशिष्ट रूप से मौखिक और दस्तावेजी सुबूत पेश करें जिससे साबित हो कि उनका विवादित भूमि पर लंबे समय से कब्जा था और वह वहां प्रबंधन करते थे। जैन ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में ही संदर्भ दिए गए जिससे उनका दावा साबित होता है, लेकिन कोर्ट ने उनसे अलग से स्पष्ट साक्ष्य पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इसके बगैर अदालत इस बारे में फैसला कैसे करेगी।

अपील में कहा गया है कि 1931 में अखाड़ा के एक महंत के नाम जमीन का खसरा था जिसकी 1941 में प्रविष्टि हुई थी। जैन ने कहा कि 1982 में उनके यहां डकैती पड़ी थी जिसमें सारे दस्तावेज चले गए इसलिए वह इसके दस्तावेज पेश करने में असमर्थ हैं। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या डकैत खतौनी भी ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड तो राजस्व विभाग के पास होगा, लेकिन जैन ने कहा कि वह रिकॉर्ड पेश करने में असमर्थ हैं। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वहां राम जन्मस्थान बहुत लंबे समय या ना मालूम कब से हो, यह बात मंदिर के लिए है लेकिन आप वहां कब से कब्जे में हैं और कब से पूजा अर्चना या प्रबंधन देख रहे हैं यह दूसरी बात है। आपको अपना कब्जा साबित करना होगा।

प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किया कि जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में जमीन की क्या स्थिति दर्ज है। जैन ने कहा कि यह जमीन नजूल भूमि है और अयोध्या में ज्यादातर मंदिरों की जमीन नजूल भूमि है। जस्टिस एसए बोबडे का सवाल था कि क्या इस जमीन (विवादित स्थल) का राजस्व दिया गया या उसकी स्थिति क्या है।

इसे पहली अदालत बने रहने दो

बुधवार को सुनवाई के दौरान अचानक एक वकील के खड़े होकर दखल देने पर कोर्ट ने फिर ऐतराज जताते हुए कहा कि यह देश की सबसे बड़ी और पहली अदालत है। इसे पहली अदालत बने रहने दें। इस तरह बीच में खड़े होकर सुनवाई में दखल न दें। मालूम हो कि मंगलवार को कोर्ट ने वकील राजीव धवन के जवाब देने के तरीके पर ऐतराज जताते हुए उन्हें कोर्ट की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी थी।

एक नई आजादी...

दुनिया से कदमताल करते हुए देश तेजी से बदल रहा है। लोगों की अपेक्षाएं-उम्मीदें बदल रही हैं। भारत के सवा सौ करोड़ नागरिकों की दिनचर्या बदल रही है। समाज के सोचने, काम करने और जागरूक होने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। ऐसे में बदलते देश की सोच और जरूरत से तारतम्य साधते हुए मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र में कई ऐतिहासिक कानून बनाए। कुछ दिन बाद हम आजादी मिलने के 73वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएंगे, लेकिन इन कानूनों ने उसके पहले ही अप्रासंगिक-असामयिक हो चले नियमों-प्रावधानों और उपबंधों से मुक्ति दिला दी है। देश के सभी नागरिकों के लिए यह एक नई आजादी की तरह है।

ऐ भाई जरा देख के चलो!

अगर कोई किशोर वाहन लेकर सड़क पर जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इसके लिए अभिभावक या गाड़ी मालिक जिम्मेदार होगा। इसी तरह यदि मानकों के अनुसार तैयार न हुई सड़क की वजह से दुर्घटना में कोई हताहत होता है तो उसके लिए ठेकेदार या संबंधित निर्माण संस्था जिम्मेदार होगी। ऐसे कई प्रावधान मानसून सत्र में पारित किए गए नए अधिनियम में शामिल हैं। लोगों को सड़क पर चलने का शऊर और सलीका सिखाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन दशक पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1988 को नए रूप-रंग में पेश किया है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में सख्ती के साथ नरमी को भी शामिल किया गया है। जो जिस तरीके से समझे, उसे उसी तरह समझाने का प्रयास है। 15 जुलाई को इसे लोकसभा में पेश किया गया। 23 जुलाई को संसद के निचले सदन से यह पारित हुआ। 31 जुलाई को राज्यसभा ने इस पर अपनी मुहर लगाई। देश के लिए यह इसलिए भी अहम मसला है कि हर साल 1.5 लाख मानव संसाधन की हमारी सड़कों पर मौत होती है। 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इनमें ज्यादातर लोग बाकी जिंदगी दिव्यांग का जीवन जीने को विवश होते हैं।

अर्थदंड में प्रभावी इजाफा

ज्यादा जुर्माना चुकाने का भय लोगों को कानून तोड़ने से रोकता है। इस स्थापित सत्य को कानून के जरिए जमीन पर उतारा गया है। यातायात से जुड़े तमाम उल्लंघनों के लिए जुर्माने में दोगुनी, तिगुनी वृद्धि हुई है। सौ रुपये का न्यूनतम जुर्माना अब पांच सौ हो चुका है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर अर्थदंड पांच सौ से पांच हजार हो चुका है। सीट बेल्ट न बांधने का जुर्माना सौ रुपये से बढ़कर एक हजार हो चुका है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दो हजार की जगह 10 हजार रुपये चुकाने होंगे। आपातकालीन वाहनों से एंबुलेंस आदि को पास न देने पर दस हजार जुर्माना देना पड़ सकता है।

भलाई करने वालों की सुरक्षा

सड़क दुर्घटना के समय मददगार के लिए बेहतर प्रावधान हैं। पहले नियम-कानूनों के फेर में पड़ने के चलते लोग जरूरतमंदों की मदद को आगे नहीं आते थे, लिहाजा दुर्घटना के तुरंत बाद के गोल्डेन ऑवर में उनकी मदद नहीं हो पाती थी। अब दुर्घटना पीड़ित की मौत हो जाने के बाद भी मददगार को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जा सकेगा।

तय हुई जवाबदेही

सड़क संरचना में खामी के चलते हो रही दुर्घटनाओं के मामले में ठेकेदार या निर्माण करने वाली संस्था पर मुकदमा चलेगा। किशोर वाहन चालक द्वारा दुर्घटना करने की स्थिति में अभिभावक या गाड़ी मालिक जिम्मेदार होंगे। गाड़ी में खराबी की बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं या टेस्टिंग एजेंसी द्वारा शिकायत मिलने पर केंद्र सरकार कंपनी को वाहनों की वापसी का निर्देश दे सकेगी। पहले ऐसे नियम नहीं थे।

मुआवजा और इंश्योरेंस कवरेज

पहले हिट एंड रन मामले में अगर किसी की मौत हो जाती थी तो मुआवजा महज 25 हजार रुपये था, अब इसे बढ़ाकर दो लाख किया गया है। घायल होने पर मुआवजा 12500 से बढ़ाकर 50 हजार हुआ है। सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से इंश्योरेंस कवर और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष गठित होगा।

लाइसेंस का पात्र

पुराने कानून में लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आठवीं तक शैक्षिक योग्यता जरूरी थी। अब ऐसा नहीं है। अगर किसी ड्राइविंग स्कूल का आपके पास प्रमाणपत्र है तो आप लाइसेंस के पात्र हैं।

अनुच्छेद 370 पर थमा नहीं है कांग्रेस का घमासान

विवाद ▶ पार्टी लाइन तय होने के बाद भी अलग-अलग सुर थमते न देख सभी राज्यों के नेताओं की कल बुलाई बैठक

युवा ब्रिगेड के नेताओं और वरिष्ठों के बीच हुई जमकर बहस

संजय मिश्र, नई दिल्ली

कार्यसमिति की बैठक में जम्मू-कश्मीर के बंटवारे को गलत ठहराने की पार्टी लाइन तय हो जाने के बावजूद अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस का अंदरूनी घमासान अभी थमा नहीं है। इस मुद्दे पर कार्यसमिति की तय की गई सियासी लक्ष्मणरेखा को कांग्रेस के तमाम नेता सहज रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे। पार्टी में इस मसले पर विद्रोह के मुखर सुर को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने नौ अगस्त को सभी राज्यों के नेताओं की विशेष बैठक बुलाई है।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपने विचार से अवगत कराते पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल। एएनआइ

अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस में अंदरूनी घमासान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार्यसमिति में मंगलवार रात इस मुद्दे पर पार्टी के दिग्गजों और युवा नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। इस बहस का ही नतीजा रहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 हटाने का सीधे तौर पर विरोध करने से परहेज करने की रणनीति अपनाई। कार्यसमिति के प्रस्ताव में सीधे तौर पर इस अनुच्छेद को हटाने का जिक्र करने के बजाय संवैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी कर प्रस्ताव लाने और जम्मू-कश्मीर के बंटवारे का विरोध करते हुए इसकी निंदा की गई। पार्टी की इस आधिकारिक लाइन के बावजूद अनुच्छेद 370 के समर्थन में नेताओं के आ रहे बयानों से परेशान होकर नौ अगस्त को नेताओं की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया है। पार्टी महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं के साथ पार्टी के सभी अग्रणी संगठनों और विभागों के प्रमुखों को इस बैठक में बुलाया गया है।

जम्मू-कश्मीर पर पार्टी की नीतिगत लाइन पर अपने ही नेताओं के विरोधी सुर की झलक कार्यसमिति की बैठक में साफ दिखाई दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में पार्टी युवा ब्रिगेड के नेताओं ने अनुच्छेद 370 हटाने के पक्ष में व्यापक जनभावना को देखते हुए इसका विरोध करने पर सवाल उठाया। सूत्रों के अनुसार संसद में पार्टी नेताओं के रुख से कांग्रेस का राजनीतिक नुकसान होने की बात उठाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र हुड्डा और जितिन प्रसाद सरीखे नेताओं ने बैठक में कहा कि जनता के मूड के खिलाफ वैचारिक दृष्टिकोण से पार्टी की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। सिंधिया ने सरकार का समर्थन करने के अपने रुख को यह कहते हुए सही साबित करने का प्रयास किया कि लोगों की व्यापक राय इसके पक्ष में है। हालांकि इसे अंजाम देने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाने की बात के जरिये उन्होंने अपना बचाव भी किया। दीपेंद्र हुड्डा ने भी कुछ ऐसी ही राय जाहिर की।

सूत्रों के अनुसार झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि नीतिगत आधार पर पार्टी का नजरिया भले सही हो मगर जनता को इस बारे में समझाना मुश्किल है। इसीलिए जनता के बीच इस मुद्दे पर जाने के लिए सहज व्यावहारिक नजरिया क्या होना चाहिए, पार्टी को यह स्पष्ट करना होगा। युवा ब्रिगेड के एक और सदस्य जितिन प्रसाद ने संसद में जम्मू-कश्मीर पर पार्टी नेताओं के भाषण से कांग्रेस को नुकसान होने की बात उठा गुलाम नबी आजाद को आक्रोशित कर दिया। जितिन ने कहा कि ऐसे भाषणों से कश्मीर में कुछ लोगों को फायदा भले हो जाए बाकी देश में पार्टी को नुकसान हो रहा है। पी. चिदंबरम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस तर्क के आधार पर उत्तर भारत की जनभावना के अनुरूप कल को तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक में हिंदी को अनिवार्य करने का सरकार फैसला लेती है तो क्या हम इन राज्यों से किया पुराना वादा भूल सकते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी चिदंबरम की राय से सहमति जाहिर की और कहा कि भारत की अवधारणा के बुनियादी उसूल और संवैधानिक स्वरूप कांग्रेस की विचारधारा की आत्मा हैं। संवेदनशील मामलों में केवल जनभावना ही सही या गलत का पैमाना नहीं हो सकती। राहुल ने कहा कि राजनीति का मतलब केवल तात्कालिक नफा नुकसान या चुनावी हार-जीत ही नहीं बल्कि देश का दीर्घकालिक हित भी होता है और हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। सूत्रों के अनुसार सोनिया और प्रियंका गांधी ने भी राहुल के इस रुख से पूरी सहमति जताई।

हालांकि इस तीखी बहस और युवा ब्रिगेड के नेताओं के दबाव का असर प्रस्ताव में दिखा। साथ ही लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के बयान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कार्यसमिति के प्रस्ताव के जरिये कांग्रेस ने साफ किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके साथ पीओके और अक्साई चिन भी हमारा है। कार्यसमिति ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान से केवल द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। जम्मू-कश्मीर मामले में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कतई स्वीकार नहीं है।

जलियांवाला बाग विधेयक पर कांग्रेस ने लगाया अड़ंगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राज्यसभा से बगैर चर्चा पारित कराना चाहती थी सरकार

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक आखिरकार बुधवार को राज्यसभा में फंस गया। हुआ यह कि सरकार इस विधेयक को सदन में बगैर चर्चा के ही पारित कराना चाहती थी पर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। वह विधेयक के जरिये स्मारक के ट्रस्ट से कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने का विरोध कर रही थी। टकराव की स्थिति बनते देख विधेयक को अगले सत्र तक के लिए टाल दिया गया। लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है।

सरकार इस विधेयक के जरिये जलियांवाला बाग ट्रस्ट में बदलाव करना चाहती है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को हटाना भी शामिल है। इसके साथ ही वह ट्रस्ट में शामिल विपक्ष के नेता की जगह विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को इनमें शामिल करना चाहती है। राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि यह विधेयक सरकार को किसी भी मनोनीत न्यासी का कार्यकाल बिना कारण बताए पांच साल की तय अवधि से पहले खत्म करने का अधिकार भी देता है।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने इस पर आपत्ति की और कहा कि सरकार कांग्रेस अध्यक्ष को क्यों हटाना चाहती है। देश की आजादी के आंदोलन की अगुआई कांग्रेस ने ही की थी। इसे स्वीकार करने में किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए। न ही ऐसा संशोधन होना चाहिए। सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए। सरकार की ओर से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को जवाब दिया और कहा कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका को कोई कम नहीं कर रहा है। देश ने इसे देखा है। इस बदलाव को किसी दल से जोड़कर देखने के बजाय ट्रस्ट की संरचना से जोड़कर देखा जाना चाहिए। जलियांवाला बाग की शताब्दी वर्ष के महत्व को देखते हुए इसे पारित करना चाहिए। वैसे भी किसी भी सरकारी ट्रस्ट में कोई पद राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। सपा और बसपा ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि ट्रस्ट का कोई भी पद पदेन होना चाहिए क्योंकि कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक पद पर नहीं रहता है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन और बजट सत्र के अंतिम दिन सरकार कोई टकराव नहीं चाहती थी, लिहाजा विधेयक को अगले सत्र के लिए टाल दिया गया।

राज्यसभा में सत्र के अंतिम दिन दो और विधेयक पेश हुए। इनमें से राज्यसभा से पहले पारित हो चुके जम्मू-कश मीर आरक्षण विधेयक को अनुच्छेद 370 खत्म होने के चलते वापस ले लिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की और नियुक्ति से जुड़े विधेयक को पारित मानते हुए लोकसभा को वापस भेज दिया गया।

पीएम आज देश को कर सकते हैं संबोधित

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश को संबोधित कर सकते हैं। ऐसी संभावना है कि वह अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और इसे दो केंद्र शासित क्षेत्रों में तब्दील करने के फैसले पर बात करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम बार देश को लोकसभा चुनाव से पहले 27 मार्च को सेटेलाइट रोधी मिसाइल द्वारा एक सेटेलाइट को मार गिराने की क्षमता की घोषणा करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया था। मंगलवार को संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित क्षेत्र बनाने वाला विधेयक भी पारित हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है, जब स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के उनके औपचारिक संबोधन में कुछ ही दिन बचे हैं।

विधायी कार्य में इजाफे के लिए सत्तापक्ष व विपक्ष में सहयोग बढ़ाना जरूरी : वेंकैया

नई दिल्ली, प्रेट्र : उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन की बैठक के दौरान हुए विधायी कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि सदन के कामकाज को और अधिक बढ़ाने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आपसी सहयोग व तालमेल को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है।

नायडू ने राज्यसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदन में विभिन्न दलों के 25 नेताओं के साथ बैठक में कहा कि इस सत्र के दौरान विधायी कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। राज्यसभा सचिवालय की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बैठक में मोदी सहित सभी दलों के नेताओं ने भी बजट सत्र के दौरान हुए कामकाज पर संतोष व्यक्त किया। सभापति कार्यालय में हुई बैठक में नेता सदन थावर चंद गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सपा के रामगोपाल यादव, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, अकाली दल के नरेश गुजराल और माकपा के टीके रंगराजन सहित अन्य दलों के नेता मौजूद थे।

नायडू ने सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आपसी संवाद बेहतर होने के कारण कामकाज के लिहाज से बजट सत्र को अच्छा बताया। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे अपने दल के सांसदों को आसन के समीप आने से बचने का सुझाव दें। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की जरूरत पर बल दिया कि संसद सदस्यों को जनता के बीच बन रही उनकी छवि के बारे संजीदा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग संसद में सदस्यों की कार्यप्रणाली पर सजगता से नजर रखते हैं इसलिए संसद सदस्यों को सदन में जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल न उठें। इस दौरान नेताओं ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर भी संक्षिप्त चर्चा की और इस पर संसद में चर्चा की जरूरत बताई।

मानहानि मामले में थरूर को नोटिस जारी करने पर फैसला सुरक्षित

जासं, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में दायर मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ नोटिस जारी करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 27 अगस्त को फैसला सुनाएगी कि तय आरोप पर नोटिस जारी करना है या नहीं।

इस मामले में पिछले माह शशि थरूर राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष पेश हुए थे। सुनवाई के बाद अदालत ने 20 हजार के निजी मुचलके पर उनको जमानत दे दी थी। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर की ओर से दायर शिकायत में कहा गया है कि बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में शशि थरूर ने जान बूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे हिंदू भावनाएं आहत हुईं। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया।

'अनुच्छेद 370 व 371 अलग-अलग, सिक्किम सुरक्षित'

इरफान-ए-आजम, सिलीगुड़ी

- मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने कहा, कश्मीर से 370 हटना राष्ट्रहित में
- कहा, सिक्किम के अपने प्रावधान हैं, वे बरकरार रहेंगे, विशेष राज्य के दर्जे पर कोई आंच नहीं

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग (पी. एस. गोले) ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना राष्ट्रहित में है। वह बुधवार को सिलीगुड़ी में एक समारोह के अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में केंद्र सरकार की जो भी कार्यवाही-कार्रवाई होगी हम सदैव उसका समर्थन व स्वागत करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अलग चीज है और 371 अलग चीज है। उनसे पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर की ही भांति अब अन्य राज्यों विशेष कर सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों का भी विशेष दर्जा समाप्त किए जाने की आवाजें उठने लगी हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 371 सही है। इसके अनेक खंड हैं। अलग-अलग खंडों से पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। 1975 में सिक्किम का जब भारत में विलय हुआ तब विशेष राज्य के दर्जे की शर्तों के साथ ही हुआ। उसी के मद्देनजर 371-एफ के तहत सिक्किम संरक्षित है। 371 में कोई समस्या नहीं है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 371 को नहीं हटाया जाएगा वह बरकरार रहेगा।

अनुच्छेद 371 में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? इस पर तामांग ने कहा कि इसका कोई सवाल ही नहीं है। सिक्किम के अपने प्रावधान हैं। वह बरकरार रहेंगे। इसके विशेष राज्य के दर्जे पर कोई आंच नहीं आएगी।

शराबी कर्मचारियों पर एटीसी में भी लगेगी रोक

नई दिल्ली, प्रेट्र : अब सिर्फ पायलट और केबिन क्रू ही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट पर काम करने वाला कोई भी कर्मचारी शराब पीकर ड्यूटी पर नहीं आ सकेगा। इसके लिए डीजीसीए ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नागर विमान महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को हवाई यातायात नियंत्रक (एटीसी), विमान का रखरखाव करने वाले कर्मचारी (एएमपी) व ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ (जीएचएस) समेत विमान के परिचालन से जुड़े सभी कर्मचारियों के श्वांस परीक्षण (ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट) के लिए प्रारूप तैयार किया है। फिलहाल, केवल पायलट और केबिन क्रू ही इस परीक्षण के दायरे में आते हैं। श्वांस जांच के जरिये यह पता लगाया जाता है कि संबंधित कर्मचारी ने शराब तो नहीं पी है।

डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इस कदम से सुरक्षा को बेहतर करने में मदद मिलेगी। यह घटनाओं और दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद करेगा।' प्रारूप से प्रावधानों के अनुसार, एटीसी, एएमपी व हवाई अड्डा परिचालन कर्मी भी श्वांस जांच के दायरे में होंगे।

रखी बात

तीन तलाक और धारा 370 के खात्मे को लेकर जदयू ने स्पष्ट रूप से जताया था अपना विरोध, इसके बाद शुरू हुआ था अटकलों का दौर, जिसे दोनों दल खारिज कर रहे हैं

कुछ मुद्दों पर मतभेद के बावजूद कायम रहेगी भाजपा-जदयू की दोस्ती

अरुण अशेष, पटना

तीन तलाक हो या 370-भाजपा और जदयू के बीच जब किसी मुद्दे पर मतभेद होता है, गठबंधन टूटने के कयास शुरू हो जाते हैं। खासकर उन लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है, जिन्हें लगता है कि गठबंधन टूटने की हालत में लड़ने लायक विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। उन्हें टिकट भी मिल जाएगा। दूसरे तबके में भी बेचैनी बढ़ती है। यह दोनों दलों के विधायकों का तबका है। इन्हें डर सताता है-गठबंधन नहीं रहा तो टिकट भले ही मिल जाए, जीतने की गारंटी नहीं रहेगी। इसी उम्मीद और बेचैनी में गठबंधन टूटने या बने रहने के कयास चलते रहते हैं।

उम्मीदवारों की बात छोड़ दें तो विधायकों जैसी बेचैनी नेतृत्व के स्तर पर भी है। दोनों दलों के पास अकेले लड़कर परास्त होने का अनुभव है तो साथ लड़कर सर्वश्रेष्ठ जीत हासिल करने का रिकॉर्ड भी है। यही वह तत्व है, जो दोनों को एक साथ रहने के लिए मजबूर भी करता है। भाजपा को दूसरे दलों के साथ दोस्ती का तजुर्बा भी है। फिर भी भरोसेमंद पार्टनर जदयू ही है। जीत की गारंटी उसे जदयू के साथ रहने पर ही मिलती है। जदयू को भी दूसरे के साथ चुनावी कामयाबी मिली। लेकिन, अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी। 2015 का विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है। नीतीश कुमार सहयोगी दल का दबाव झेल नहीं पाए। अंततः उन्हें सरकार चलाने के लिए भाजपा से दोस्ती करनी पड़ी।

जदयू की तरह भाजपा को भी राज्य की राजनीति में दूसरे दलों की दोस्ती रास नहीं आती है। लोजपा और रालोसपा जैसे दलों के साथ उसे 2014 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली। वह नमो लहर का दौर था। इसके बावजूद 2009 के 32 सीटों पर जीत का रिकार्ड नहीं टूटा। उसके गठबंधन को 2009 में लोकसभा की एक सीट कम मिली थी। जबकि 2019 में रालोसपा और हम जैसी पार्टियां एनडीए से अलग हो गई थीं। सिर्फ जदयू जुड़ा था। 39 सीट का अविश्वसनीय आंकड़ा मिल गया। 2014 के लोकसभा में 31 सीट जीतने वाला एनडीए अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में 58 सीटों पर सिमट गया, जबकि राजद-कांग्रेस के साथ गठबंधन कर जदयू सत्ता में आ गया। ऐसी बात नहीं है कि अलग रहने पर भाजपा को ही घाटा उठाना पड़ा है। जदयू भी अछूता नहीं रहा है। उदाहरण 2014 का लोकसभा चुनाव है। इसमें 38 सीटों पर लड़ने वाला जदयू दो सीट जीत पाया। यानी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की क्षमता हासिल करना अभी उसके वश में भी नहीं है।

गठबंधन के बने रहने की दो वजह बहुत साफ है। पहलीः भाजपा और जदयू का जनाधार आपस में कभी टकराता नहीं है। वे एक साथ वोट करते हैं। राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच कभी भेदभाव नहीं किया। यहां तक कि किसी भी स्तर पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी नहीं की गई। दूसरी वजह, भाजपा ने कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं किया। अफसरों के तबादले हों या शीर्ष पदों पर तैनाती, भाजपा ने कभी दखल नहीं किया। राजद को भले ही लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हुई। लेकिन, उसके समर्थक और विरोधी अब भी पहले की तरह ही सक्रिय हैं। विधानसभा चुनाव में राजद मुद्दा रहेगा ही। उसे रोकने के नाम पर ही सही, भाजपा-जदयू का साथ रहना अपरिहार्य है। जदयू के राजद से हाथ मिलाने की चर्चा भी होती रहती है। लेकिन, यह संभवतः ऐसा विकल्प है, जिसे नीतीश कुमार शायद ही दूसरी बार स्वीकार करें।

जदयू ने साफ किया, अनुच्छेद 370 समाप्त तो अब इसका विरोध नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना : जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और संसदीय दल के नेता आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद अब इसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। जब बहुमत से निर्णय हो गया है तो इसके खिलाफ छाती पीटना उचित नहीं है। जदयू के कुछ नेता अभी भी अनुच्छेद 370 की समाप्ति का विरोध कर रहे। आरसीपी ने उन्हें नसीहत दी कि इस मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड साफ है। जिनका पार्टी में मन नहीं लगता है, वे कहीं और चले जाएं। पार्टी के भीतर इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। वह बुधवार को पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। मालूम हो कि जदयू के विधान परिषद सदस्य गुलाम रसूल बलियावी और पूर्व सांसद डॉ. मोनाजिर हसन सहित कुछ नेता आज भी जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति का विरोध कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि जदयू ने संसद के दोनों सदनों में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध करने का तरीका है। पक्ष-विपक्ष में मतदान करने के अलावा मतदान में हिस्सा न लेना भी संसदीय कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

अपना टाइम आ गया

1.87 लाख ओवरलोडेड वाहनों के चालान किए गए हैं, बीते पांच सालों में हरियाणा में। करनाल में 17,757, गुरुग्राम में 15,480 और रेवाड़ी में 14,879 चालान काटे गए। प्रदेश में हर साल सड़क हादसों में पांच हजार लोगों की जान चली जाती है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 अगस्त 2019

महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए मुसीबत बना 370 पर पार्टी का रुख

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

- जनता के सवालों का नहीं दे पा रहे हैं जवाब

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से चंद दिनों पहले संसद में अनुच्छेद 370 पर दिखा पार्टी का आधिकारिक रुख प्रदेश कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि भाजपा-शिवसेना इस मुद्दे का इस्तेमाल भी चुनाव में उनके खिलाफ करेंगी और उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर संसद में कांग्रेस के नेताओं ने सरकार विरोधी रुख अपनाया। लेकिन, कांग्रेस के कई युवा नेता अपनी ही पार्टी की इस लाइन के खिलाफ जाते दिखे। इनमें मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा भी थे। देवड़ा ट्वीट कर सरकार के फैसले का स्वागत करते दिखाई दिए थे। इसी प्रकार मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह भी अगले दिन यह कहते नजर आए कि भारत का नागरिक होने के नाते मैं जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का स्वागत करता हूं। उनके अनुसार कश्मीर में अलग संविधान और अलग झंडे का अस्तित्व बिल्कुल सही नहीं था। इसी प्रकार मीरा-भायंदर कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार मिश्र भी मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करते दिखे। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी मानना था कि अनुच्छेद 370 अस्थायी व्यवस्था है और समय आने पर इसका समाधान अपनेआप हो जाएगा। मिश्र का कहना है कि देशहित के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने सबको भरोसे में लेकर यह कदम उठाया होता तो और अच्छा होता।

बता दें कि हाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस-राकांपा को सूबे में करारी हार का सामना करना पड़ा है। राकांपा को चार सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस को एक सीट से ही संतोष करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस-राकांपा के नेताओं की भाजपा-शिवसेना की ओर भगदड़ शुरू हो चुकी है। अब तक कांग्रेस-राकांपा के जनाधार वाले कई विधायक भाजपा और शिवसेना में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस 24 दिनों की महाजनादेश यात्रा पर हैं। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने का निर्णय लेने के कारण महाराष्ट्र में भाजपा के पक्ष में माहौल और मजबूत हो गया है। दूसरी ओर पार्टी के केंद्रीय नेताओं द्वारा संसद में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के कदम के विरोध में दिए गए भाषण महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के गले की हड्डी बन गए हैं। वह इस मुद्दे पर जनता के बीच जवाब नहीं दे पा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री फड़नवीस अपनी यात्रा के दौरान अब इस मुद्दे पर भी कांग्रेस-राकांपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

उत्तराखंड में भी पसोपेश में पड़ी कांग्रेस

विकास धूलिया, देहरादून

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने का फैसला उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि इस मसले पर क्या स्टैंड लिया जाए। पार्टी के लिए चिंता का सबब यह है कि नेतृत्व की ओर से इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट न किए जाने के कारण वरिष्ठ नेता किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से कतरा रहे हैं तो कई कांग्रेस नेता केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के पक्ष में खुलकर भी आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के पुत्र और पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस टिकट पर लड़े मनीष खंडूड़ी के अलावा प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने केंद्र के फैसले को सही ठहराया है।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र के फैसले का हालांकि संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन संसद के बाहर कई बड़े नेता पार्टी लाइन से अलग अपनी बात रख चुके हैं। अब ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में भी होता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दो दिन पूर्व इस मसले पर राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के स्टैंड को पार्टी का स्टैंड मानने से इन्कार करते हुए कहा था कि विधेयक का मसौदा देखे-समझे बगैर इस मामले में वह टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बुधवार शाम 'जागरण' से बातचीत में उन्होंने फिर यही बात दोहराई। प्रीतम ने कहा कि पार्टी का स्टैंड अभी नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस की परंपरा रही है कि वह सदैव देशहित के मुद्दों के पक्ष में खड़ी होती है। राष्ट्रहित में जो भी निर्णय लिया जाएगा, कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी।

कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर अब कई कांग्रेस नेता खुलकर इसकी पैरवी में उतर आए हैं। बुधवार को गोपेश्वर(चमोली) में मीडिया से बातचीत में पौड़ी लोकसभा सीट से पिछला चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके मनीष खंडूड़ी ने केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार की मंशा सही है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका भी सही होना चाहिए।

झारखंड में एक साथ होगी तीन वर्षों की सिविल सेवा परीक्षा

राज्य ब्यूरो, रांची

- 2017, 2018 व 2019 के लिए होगी एकीकृत संयुक्त परीक्षा
- जेपीएससी का निर्णय, कार्मिक ने सभी विभागों से मांगीं रिक्तियां

झारखंड में एक साथ तीन वर्षों की सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2017, 2018 व 2019 के लिए एकीकृत संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से इन तीन वर्षों की रिक्तियों का ब्योरा मांगा है, ताकि नियुक्ति की अनुशंसा भेजी जा सके।

कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव ओमप्रकाश साह द्वारा सभी विभागों के सचिवों, प्रधान सचिवों या अपर मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जेपीएससी ने परीक्षाओं को नियमित करने के लिए राज्यहित में इन तीन वर्षों की रिक्ति के आधार पर एकीकृत संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने 10 अगस्त तक राज्य सेवा के विभिन्न रिक्त पदों का ब्योरा जेपीएससी को भेजने का अनुरोध किया है। साथ ही उसकी एक प्रति कार्मिक विभाग को देने को कहा है। रिक्तियों का ब्योरा मिलने के बाद जेपीएससी इसकी प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करेगा।

18 के बदले हुई महज छह परीक्षाएं

झारखंड गठन से लेकर अबतक 18 सिविल सेवा परीक्षा होनी चाहिए थीं, लेकिन विभिन्न विवादों के कारण अभी तक सिर्फ पांच सिविल सेवा परीक्षाएं ही पूरी हो पाई हैं। छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हो चुकी है। झारखंड हाई कोर्ट क आदेश के बाद इसका परिणाम जारी होगा। पूर्व मुख्य सचिव वीएस दूबे की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने पांच साल पहले ही यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित करने की अनुशंसा की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

पंजाब सरकार की संपत्ति रहेगा कपूरथला हाउस

फैसला ▸ दिल्ली हाई कोर्ट ने जायदाद को बेचने का अधिकार खारिज किया

एडवोकेट जनरल बोले- महाराजा कपूरथला का स्वामित्व खत्म

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

कपूरथला हाउस फाइल फोटो

नई दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस अब पंजाब सरकार के कब्जे के अधीन रहेगा। यह ऐतिहासिक भवन मौजूदा समय में पंजाब के मुख्यमंत्री की रिहायश है। भारत सरकार की मांग के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कपूरथला के दिवंगत महाराजा की इस आलीशान जायदाद को बेचने के अधिकार को खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर व जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने फैसला दिया कि मान सिंह रोड पर नंबर-3 की जायदाद को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि महाराजा ने इस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार गंवा दिया है। अदालत में इस केस संबंधी पंजाब सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैरवी की। इस केस में मुख्य पक्ष भारत सरकार थी। इसने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसने पंजाब को इस प्रॉपर्टी का सही हकदार समझते हुए इसका कब्जा पंजाब को दे दिया है।

एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने बताया कि पैप्सू (पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन) में शामिल होने से पहले और इसके बाद पैप्सू के भारत सरकार में शामिल होने से पहले कपूरथला रियासत थी।

1950 में 1.5 लाख रुपये में खरीदा था : इस प्रॉपर्टी की रिक्वीजीशन दिल्ली प्रीमाइसिस (रिक्वीजीशन एंड एक्वीजीशन) एक्ट-1947 की धारा 3 के अंतर्गत 17 जून, 1950 को पास हुए एक आदेश में की गई। चार दिसंबर, 1950 को भारत सरकार की ओर से स्वर्गीय राधेश्याम मखनीलाल सेकसरिया से इस प्रॉपर्टी का कब्जा लिया गया। उन्होंने इसको कपूरथला रियासत के पूर्व शासक महाराजा परमजीत सिंह से 10 जनवरी, 1950 को 1.5 लाख रुपये की रजिस्टर्ड सेल डीड से खरीदा था।

यह है विवाद : विवाद तब पैदा हुआ जब सेकसरिया ने 1960 में जिला अदालत, दिल्ली में अपनी जायदाद के हक के लिए मुकदमा दर्ज किया था। 1967 में मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिया गया। मुकदमे के दौरान सेकसरिया का देहांत हो गया और उसके चार बच्चों को उसके कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर उनकी योग्यता के अनुसार वादी पक्ष के तौर पर नामजद किया गया।

1989 में मुद्दई के हक में फैसला : साल 1989 में हाई कोर्ट के एक जज ने मुद्दई के हक में इस आधार पर फैसला किया कि 1952 के एक्ट के अंतर्गत 17 साल बीत जाने पर 1987 में भारत सरकार की ओर से हक छोड़ दिया गया। इसके तुरंत बाद पंजाब सरकार ने अपील की और हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने कहा कि मुद्दई का जायदाद पर कोई अधिकार नहीं है।

हाई कोर्ट ने रद किया जायदाद पर अधिकार : बेंच ने याचिकाकर्ता के जायदाद पर अधिकार को इस आधार पर रद कर दिया कि इसकी मांग के बाद महाराजा कपूरथला का इस जायदाद पर कोई हक नहीं रहा। इसलिए वह याचिकाकर्ताओं के पुरखों को जायदाद का हक नहीं दे सकता। अदालत ने फैसला दिया कि याचिकाकर्ताओं के संपत्ति पर हक की कमी स्पष्ट तौर पर पहले की रजिस्ट्री से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत उक्त दावा किया जा रहा है।

मीसाबंदियों को पेंशन देगी कमलनाथ सरकार

बंदियों का मप्र की कांग्रेस सरकार में भौतिक सत्यापन पूरा, 13 लोगों को पेंशन होगी जारी

नईदुनिया, भोपाल

इसे राजनीति कह लीजिए या समय का फेर, केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार का विरोध करने पर जेल जाने वाले मीसाबंदियों को मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार पेंशन देगी। इनके भौतिक सत्यापन के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भोपाल जिले के 13 मीसाबंदियों को पेंशन देगी। गौरतलब है कि मप्र में कांग्रेस ने सत्ता संभालने के बाद ही मीसाबंदियों के भौतिक सत्यापन के निर्देश जारी किए थे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इसी साल 15 जनवरी को सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए थे कि वह मीसाबंदी (लोकतंत्र सेनानी) का भौतिक सत्यापन कर इसकी रिपोर्ट 15 दिन में शासन को भेजें। भौतिक सत्यापन होने तक उन्हें दी जाने वाली पेंशन रोक दी गई। भोपाल के गोविंदपुरा, बैरागढ़, एमपी नगर, शहर व हुजूर तहसील के अंतर्गत रहने वाले मीसाबंदियों का भौतिक सत्यापन करीब सात महीने बाद अब पूरा हुआ है। सत्यापित मीसाबंदियों की सूची राज्य सरकार से हरी झंडी पाकर वापस भी आ गई है। इनमें से 13 मीसाबंदियों को पेंशन जारी करने का प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर ने जिला कोषालय को भेज दिया है। रोक के पहले जिले के करीब 123 मीसाबंदियों को पेंशन जारी हो रही थी। मप्र में कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही मीसाबंदियों की पेंशन पर रोक लगा दी गई थी। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि पेंशन प्राप्त करने वालों की सूची में ऐसे लोग भी शामिल हैं, जो मीसाबंदी थे ही नहीं। प्रारंभिक जांच में कई जिलों में ऐसे प्रकरण सामने भी आए जिनमें दस्तावेज झूठे पाए गए या फिर पेंशन पाने वाले भौतिक रूप से मिले ही नहीं।

युवाओं पर दांव लगाएगी मप्र सरकार, हर पंचायत में बनेगा युवा शक्ति संगठन

नईदुनिया, भोपाल

कमलनाथ फाइल फोटो

- 35 साल तक के युवाओं को मिलेगा मौका, बैठकों में हिस्सा लेने पर दिया जाएगा भत्ता
- एक पंचायत में 10 से 15 युवाओं का बनेगा संगठन

युवाओं को सरकार के साथ जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में युवा शक्ति संगठन के नाम से नेटवर्क खड़ा करेगी। पंचायत स्तर पर 10 से 15 युवाओं का संगठन होगा। इसमें 35 साल तक के युवाओं को रखा जाएगा। इन्हें योजनाओं की निगरानी के साथ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिलेगी। संगठन के युवाओं को बैठकों में शामिल होने के लिए विशेष भत्ता दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग चलाएगा। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार में प्रचार-प्रसार की कमी महसूस की जा रही है। मंत्रियों ने गत मंगलवार को कैबिनेट में भी इस मुद्दे को उठाया। यही वजह है कि सरकारी तंत्र के समानांतर व्यवस्था बनाने की रणनीति पर कुछ विभाग काम कर रहे हैं। कृषि विभाग के तहत हर दो पंचायतों में कृषक बंधु नियुक्त करने का मसौदा लगभग तैयार कर लिया गया है। इसमें कृषक बंधुओं के माध्यम से कर्जमाफी से लेकर खेती से जुड़ी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम होगा। इन्हें एक निश्चित मानदेय भी दिया जाएगा। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पंचायत स्तर पर युवा शक्ति संगठन खड़ा करेगा। इसमें 35 साल तक के 10 से 15 तक युवाओं को शामिल किया जाएगा। इन्हें ग्रामीण विकास की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के साथ सरकार की अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार का काम सौंपा जाएगा। बैठकों में शामिल होने के लिए भत्ता देने की व्यवस्था भी रहेगी। इसके लिए कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव रखा जाएगा।

कांग्रेस समर्थकों को मिलेगी तवज्जो

चाहे कृषक बंधु हों या फिर युवा शक्ति संगठन, इनमें कांग्रेस समर्थकों को तवज्जो मिलेगी। संगठन और जनप्रतिनिधियों से इसके लिए नाम भी मांगे जा सकते हैं। दरअसल, कमलनाथ सरकार आने के बाद से लगातार यह बात सामने आ रही है कि कार्यकर्ता और पार्टी समर्थकों को सत्ता से किसी न किसी रूप में जोड़ा जाएगा। इन व्यवस्थाओं के अलावा जिला सरकार का फार्मूला भी लागू किया जा रहा है। इसमें भी स्थानीय लोगों को भरपूर तवज्जो मिलेगी। उधर, कॉलेजों की जनभागीदारी समितियों में भी पार्टी समर्थकों को स्थान देने की तैयारी चल रही है। शिवराज सरकार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में इनमें मौका दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के निस्तारण में आएगी और तेजी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 किए जाने संबंधी विधेयक पर बुधवार को संसद की मुहर लग गई। माना जा रहा है कि शीर्ष अदालत में जजों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों के निस्तारण में और तेजी आएगी।

सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक-2019 को राज्यसभा में विचार व वापसी के लिए रखते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'मैं सदन से इस विधेयक पर विचार करने का आग्रह करता हूं।' इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, 'हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है...लेकिन संसद सदस्य इस पर चर्चा चाहते हैं, क्योंकि हम सामान्य तौर पर न्यायपालिका पर चर्चा नहीं करते...हम दशक या छह महीने में एक बार ऐसा मौका पाते हैं...हम भी न्यायपालिका के बारे में जानना चाहते हैं।'

सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि यह वित्त विधेयक है। कानून मंत्री ने कहा है कि वह न्यायपालिका पर नवंबर में चर्चा रखेंगे। इस दौरान बसपा के सतीश चंद्र ने आग्रह किया कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।

सदन के नेता थावरचंद गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक-2019 व द जालियांवाला बाग राष्ट्रीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक-2019 को पारित करने का आग्रह किया। हालांकि, सभापति ने सुप्रीम कोर्ट विधेयक को अलग रखा, जो बिना किसी चर्चा के पास हो गया। इस विधेयक को लोकसभा पांच अगस्त को पारित कर चुकी है।

- जजों की संख्या 30 से 33 करने पर संसद की मुहर

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाओं का बकाया चुकाना ही होगा : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- कोश्यारी व बहुगुणा की पुनर्विचार याचिका खारिज, कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास समेत अन्य सुविधाओं का बकाया चुकाना ही होगा। हाई कोर्ट ने बकाया किराया जमा करने के आदेश के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की पुनर्विचार याचिका को निरस्त कर दिया है। कोश्यारी ने खुद की माली हालत का हवाला देते हुए बकाया जमा करने में असमर्थता जताई थी, जबकि बहुगुणा ने बांबे हाई कोर्ट के न्यायाधीश व सांसद के तौर पर सेवाओं को ध्यान में रखने को आधार बनाया था। यह भी कहा था कि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को कानूनी आधार नहीं होने पर निरस्त कर दिया।

देहरादून की रूरल लिटीगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र (रूलक) संस्था ने 2010 में जनहित याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए सरकारी आवास समेत अन्य सुविधाएं दिए जाने को चुनौती दी थी। कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास समेत सुविधाओं का बकाया वसूला जाए। याचिकाकर्ता ने अपने स्रोतों से जुटाई जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों से करीब 14 करोड़ बकाया वसूली की मांग की थी। इसी साल मई में हाई कोर्ट ने छह माह के भीतर किराया समेत सुविधाओं का ब्यौरा तैयार कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया की वसूली का आदेश पारित किया था। इसके खिलाफ कोश्यारी व बहुगुणा ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। बुधवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता के अनुसार, कोर्ट ने साफ किया है कि पूर्व के फैसले को चुनौती देने का कोई कानूनी आधार नहीं है। हमारा पक्ष नहीं सुना गया जैसा तथ्य कानूनी आधार के दायरे में नहीं आ सकता। कोर्ट के आदेश से पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है।

पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया हैं 2.85 करोड़

सरकार की ओर से कोर्ट में पेश रिपोर्ट में कहा गया था कि पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर करीब 2 .85 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें पूर्व सीएम व वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ . रमेश पोखरियाल निशंक पर 40 .85 लाख, बीसी खंडूड़ी पर 46 .95 लाख, विजय बहुगुणा पर 37 .50 लाख, भगत सिंह कोश्यारी पर 47 .57 लाख, पूर्व सीएम एनडी तिवारी पर 1 .13 करोड़ रुपये बकाया हैं। इस आदेश के खिलाफ कोश्यारी व बहुगुणा ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

बसपा का मुस्लिम कार्ड मुनकाद बने उप्र अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- सपा के यादव वोटों में सेंध लगाने को श्याम सिंह को दलनेता की जिम्मेदारी
- कुशवाहा होंगे राष्ट्रीय महासचिव, रितेश पांडेय को लोकसभा में उपनेता बनाया

लोकसभा चुनाव के बाद से बसपा संगठन में उलटफेर जारी है। बुधवार को मायावती ने मुस्लिम कार्ड चलते हुए पुराने वफादार मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं गठबंधन तोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक पर भी निगाहें लगी हैं। यादवों में सेंध लगाने के लिए नौकरशाह से सांसद बने श्याम सिंह यादव को लोकसभा में दलनेता नियुक्त किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा को प्रोन्नत कर राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। सोशल इंजीनियरिंग की मजबूती के लिए रितेश पांडेय लोकसभा में उपनेता बनाए गए जबकि सांसद गिरीश चंद्र जाटव लोकसभा में मुख्य सचेतक बने रहेंगे।

समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने व विधानसभा के उपचुनावों में उतरने की घोषणा के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को संगठन में फेरबदल करते हुए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। इस उलटफेर के जरिए दलित-मुस्लिम गठजोड़ को मजबूती देने के साथ वफादार व मिशन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया गया है। वहीं, श्याम सिंह यादव जैसे नए चेहरे को तरजीह देकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में हारने के बाद से प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा की कुर्सी खतरे में दिख रही थी। अब कुशवाहा को हटाकर मायावती ने मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अर्से बाद किसी मुस्लिम नेता की ताजपोशी चौंकाने वाली है। जानकारों का कहना है कि मेरठ निवासी मुनकाद अली को प्रदेश संगठन की कमान सौंप मायावती ने पश्चिम उप्र में स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है।

बेअदबी मामला

एसआइटी चीफ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी, राजनीतिक स्तर पर भी दिन भर होते रहे प्रयास, सीएम ऑफिस में हड़कंप

कैप्टन के हस्तक्षेप के बावजूद विधायक अड़े

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल फोटो

कांग्रेसी विधायकों की ओर से बेअदबी मामले की जांच कर रही स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) के प्रमुख प्रबोध कुमार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के फैसले से मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को विधायकों को शांत करवाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कमान संभाली। इसके बावजूद मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। राजनीतिक स्तर पर भी विधायकों के गुस्से को शांत करने का प्रयास जारी रहा।

'दैनिक जागरण' में खबर प्रकाशित होने के बाद सुबह से ही मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रिय हो गया। विधायकों के गुस्से को शांत करने के लिए सरकारी और राजनीतिक स्तर पर काम किया गया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारियों ने अलग-अलग स्तर पर विधायकों से बातचीत की। वहीं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई विधायकों के मुलाकात कर उनके गुस्से को शांत करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि अगर विधायक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के साथ सीधा-सीधा राजनीतिक टकराव हो जाएगा। इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

कुछ के सुर शाम तक पड़े नरम : गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। इससे सीधा असर मुख्यमंत्री पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि सुबह से ही मुख्यमंत्री खुद इस मामले को देख रहे थे। देर शाम तक आधे विधायकों के सुर तो नरम पड़ गए, लेकिन बाकी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे मामले को बेहद गोपनीय तरीके से किया जा रहा है, ताकि मीडिया को इसकी जानकारी न हो। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्र बताते हैं कि विधायकों के गुस्से को शांत कर दिया गया है।

यह है मामला

सीबीआइ ने बेअदबी कांड पर क्लोजर रिपोर्ट सीबीआइ कोर्ट में दिया था। इसके बाद बेअदबी कांड की जांच कर रही एसआइटी के प्रमुख ने सीबीआइ को पत्र लिख कर बेअदबी कांड की जांच दोबारा करवाने को कहा था। विधानसभा में सीबीआइ से केस वापस लिए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस कारण कांग्रेस के विधायकों ने इसे विशेषाधिकार हनन का मामला माना। मंगलवार को विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद विधायकों ने इस मामले में स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने का फैसला किया था।

मप्र में संगठन चुनाव के बाद निकाय चुनाव की तैयारी में जुटेगी भाजपा

नईदुनिया, भोपाल

- कांग्रेस सरकार बनने के बाद नगरीय निकाय चुनाव में इस बार कड़ी टक्कर की संभावना

संगठन चुनाव की कवायद पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में होने वाले वाली नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद नगरीय निकाय चुनाव में इस बार कड़ी टक्कर होने की संभावना है। ऐसे हालात में पार्टी की तैयारी है कि हर नगर निगम में पार्षद से महापौर तक के टिकट के लिए चेहरे चिह्नित करने और सर्वे कराने आदि का काम संगठन चुनाव के तत्काल बाद प्रारंभ कर दिया जाए। पार्टी इन चुनाव में नए चेहरों को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।

लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीतने के बाद भाजपा नगरीय निकाय चुनाव में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा इन दिनों संगठन चुनाव में व्यस्त है। इसके तहत सदस्यता अभियान और फिर मंडल से लेकर प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव होंगे। पार्टी इसके बाद कुछ महीनों बाद होने वाले नगरीय निकाय की तैयारी में जुट जाएगी। भाजपा विधानसभा चुनाव की गलती न दोहराकर नगरीय निकाय चुनाव में नई पीढ़ी को सामने लाना चाहती है। पार्टी नेताओं की मानें तो राजनीति के पायदान पर ये छोटे चुनाव बेहद अहम होते हैं। यहां से इंट्री के बाद ही नए चेहरे विधानसभा और लोकसभा तक जाते हैं। संगठन चुनाव के बाद ही पार्टी नए चेहरों की तलाश शुरू कर देगी। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पिछले चुनाव में भाजपा सभी 16 नगर निगम में काबिज हो गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ इस बार पुराने परिणामों को दोहराना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। इसी हिसाब से पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी।

झाबुआ उपचुनाव भी बना चुनौती : इधर, भाजपा के लिए झाबुआ विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखने की भी बड़ी चुनौती है। इस सीट से जीते जीएस डामोर के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव होना है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रेट्र

लोधी रोड शवदाह गृह में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अन्य। संजय

साल्वे से 10 मिनट पहले ही कहा था, ले जाओ जाधव केस की फीस

हरीश साल्वे फाइल फोटो

नई दिल्ली, एएनआइ : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव मामले की पैरवी करने वाले देश के जाने-माने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे मंगलवार की रात हुई पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की असामयिक मौत से गमगीन हैं। उन्होंने बुधवार को कहा, 'मेरे लिए सुषमा स्वराज बड़ी बहन जैसी थीं। मंगलवार रात 8:45 बजे ही उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था- आप आओ और कुलभूषण जाधव मामले की अपनी फीस (एक रुपया) ले जाओ। इसके कुछ देर बाद ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया।'

साल्वे ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत को मिली सफलता का श्रेय सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा, 'कुलभूषण जाधव मामले में की गई पहल का पूरा श्रेय सुषमा स्वराज को जाता है। इस मामले से संबंधित ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं था, जिसे उन्होंने खुद नहीं देखा हो। वह सभी चीजों की निगरानी करती थीं और अपना महत्वपूर्ण सुझाव देती थीं। सभी व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने के संबंध में आश्वस्त करने के लिए वह प्रधानमंत्री के पास भी खुद ही जाया करती थीं।'

सुषमा जी के रूप में विदा हो गई राजनीति की सौम्यता

नितिन गडकरी
(लेखक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं।)

सुषमा स्वराज जी हमारे बीच नहीं हैं। उनके साथ बीते पल और साझा की गई बातें मेरे लिए अनमोल हैं, वे जीवनभर स्मरण रहेंगी। उनसे मेरा बहुत गहरा नाता था। वह राजनीति में मेरी पथ प्रदर्शक थीं, पारिवारिक रूप से बड़ी बहन थीं। भारतीय राजनीति की सौम्यता हमसे विदा हुई है। उनका जाना निश्चित तौर पर व्यक्तिगत क्षति है। उनकी बेजोड़ भाषा शैली ने आमजन के मन में हिंदी के प्रति आकर्षण पैदा किया। वह श्रेष्ठ हिंदी वक्ता थीं और सार्वजनिक जीवन में गरिमा, साहस और निष्ठा की प्रतिमूर्ति थीं। लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। उन्होंने प्रखर वक्ता, आदर्श कार्यकर्ता, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि और कर्मठ मंत्री जैसे विभिन्न रूपों में भारतीय राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

भाजपा में शुरुआती कार्यकाल से ही वह जिम्मेदार और समर्पित कार्यकर्ता की भूमिका में रहीं। उनमें विचारधारा के प्रति वचनबद्धता और गंभीरता थी। पार्टी में उन्हें जो भी भूमिका मिली उसे न्यायपूर्ण तरीके से निभाया। जब वह विपक्ष की नेता थीं, तब पूरी ईमानदारी से जनता का पक्ष रखा और जब विदेश मंत्री थीं तब भी पूरी कटिबद्धता के साथ काम को पूरा किया। बतौर विदेश मंत्री उन्होंने दुनियाभर में बसे भारतीयों की जिस तरह मदद की, उससे लोगों के मन में सरकार के प्रति नया विश्वास पैदा हुआ। वह हर काम बहुत कुशलता से करती थीं। मुसीबत में फंसे लोगों को जब तक सहायता नहीं मिल जाती थी, वह चैन से नहीं बैठती थीं। विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने सांसदों के साथ संगठनात्मक और पारिवारिक जुड़ाव स्थापित किया। टैलेंट कार्यक्रम के जरिये भाजपा के हर सांसद की अभिरुचि को जानकर उनकी पसंद के मुताबिक काम करने का अवसर उपलब्ध कराया। जब उन्हें लगा कि जनता के लिए पूरी गंभीरता से काम नहीं कर पाएंगी, तब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस समय मुझे उनका बहुत सहयोग मिला। उस दौर में कुछ राज्यों में असहमति की स्थिति थी, संसदीय बोर्ड में भी कई बार मत नहीं बन पाते थे, ऐसे में वह मेरी मदद करती थीं। वह मुझे बताती थीं कि किस मसले का कैसे मार्ग निकलेगा। मेरे लिए सुषमा जी का सहयोग बहुत बड़ा आधार था। पार्टी में कई बार ऐसी स्थिति आई जिसमें निर्णय लेना बहुत कठिन होता था। सुषमा जी ने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया और काम को सहजता से करने का रास्ता बताया। उनके नैतिक समर्थन के कारण मैं बहुत सारे काम कर पाया।

उनका मेरे प्रति अथाह स्नेह था। उनमें मुझे बड़ी बहन का रूप दिखाई देता था। वह उसी तरह मेरी चिंता भी करती थीं। एक बार मैं बीमार हुआ तो वह तत्काल एम्स से चिकित्सक लेकर आ गईं। अधिकार के साथ पूरा चेकअप कराने को कहा। उनके कहने पर मैं एम्स गया, वहां पूरी जांच कराई। उन्होंने मेरी स्वास्थ्य रिपोर्ट के बारे में जाना और मुझे पूरे अधिकार के साथ स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की हिदायत दी। मैं उनकी बात को पूरी गंभीरता से लेता था, लेकिन विभिन्न व्यंजन खाना मेरा स्वभाव है, उसमें मैं फिर लापरवाही करने लगा। जब उन्हें यह पता चला तो नागपुर में मेरी पत्नी कांचन को फोन लगाकर बोलीं कि वह मेरा ध्यान रखें क्योंकि मैं स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाही करता हूं। ऐसी चिंता करने वाले विरले ही होते हैं। उन्होंने हर किसी के साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर उसे पूरी तरह से निभाया।

मुझे जब भी समय मिलता उनसे मिलने चला जाता था। मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि वह हमारे लिए दुख-सुख साझा करने वाली जगह बन गई थीं। उनकी बेटी बांसुरी उन्हीं की तरह बुद्धिमान, सहज और सरल बिटिया है। वह अक्सर मेरे यहां आती है। उसे हमारे यहां का बना पराठा और दही बहुत पसंद है। मैंने कह रखा था कि जब भी हमारे यहां पराठा बने, वह बांसुरी के लिए देकर आना है। मैं जब सुषमा जी से मिलने जाता था तो वह मेरे लिए विशेष रूप से पोहा बनवाया करती थीं। सुषमा जी मेरे राजनीतिक और पारिवारिक जीवन की बहुत चिंता करती थीं। जब उन्हें मेरी नागपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया कि वहां से चुनाव लड़ना बहुत जोखिम भरा है क्योंकि वह सीट भाजपा के अनुकूल नहीं है। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैंने नागपुर से चुनाव लड़ने का निश्चय कर लिया है और वहां से जीतकर ही आऊंगा तो वह मेरे इस फैसले से बहुत खुश हुईं। राजनीति में विपरीत परिस्थितियों को चुनने के मेरे निर्णय से वह बहुत प्रभावित थीं। मैं जब 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर आया तो वह बहुत खुश थीं। इस बार जब मैं लोकसभा चुनाव जीतकर आया तो संयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय में और सुषमा जी साथ-साथ पहुंचे। उन्हें देखते ही मैं पास गया तो आदर से मेरा सिर झुक गया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए अभिभावक का अहसास कराया। मैंने कहा कि आज आपके स्नेह में मुझे फिर अपनी बड़ी बहन का अहसास कराया है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद मैं जब मंत्री बना तो उनसे मिलने घर गया। करीब एक-डेढ़ घंटा हम साथ रहे। पूरे समय घर-परिवार की बातें होती रहीं। उनके निधन से देश ने एक ओजस्वी स्वर खो दिया है।

मित्र और मजबूत साथी के निधन से दुखी हूं : पोंपियो

- दुनियाभर के नेताओं ने सुषमा स्वराज के निधन पर जताई संवेदना
- शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश ने एक अच्छा मित्र खो दिया

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो। फाइल

वाशिंगटन, प्रेट्र : पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के निधन पर अमेरिका, रूस, चीन, बांग्लादेश, ईरान और सिंगापुर समेत दुनियाभर के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। नेताओं ने दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध स्थापित करने में उनके योगदान को याद किया है।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा, 'मेरी मित्र और मजबूत साथी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। वह अमेरिका के इस विचार से इत्तेफाक रखती थीं कि दुनिया में जितना लोकतंत्र रहेगा, उतनी ही शांति रहेगी।' संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ने ट्वीट किया, 'सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। एक असाधारण महिला एवं नेता, जिन्होंने अपना जीवन जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया। मुझे भारत यात्रा के दौरान उनसे मिलने का मौका मिला और मैं हमेशा उन्हें याद करूंगी।'

इजरायल ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि भारत और इजरायल के संबंधों के प्रति उनके समर्पण, करुणा और योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। चीन और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। उनकी मौत के साथ, बांग्लादेश ने एक अच्छा दोस्त खो दिया है।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वह श्रीलंका की सच्ची मित्र और अच्छी पड़ोसी थीं। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने उनके साथ हुई चर्चाओं को याद किया। बहरीन के विदेश मंत्री खालिद बिन अहमद अल खलीफा ने संवेदना व्यक्त की और सुषमा स्वराज को 'प्रिय बहन' बताया।

रूसी विदेश मंत्रालय ने भी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि हम सुषमा स्वराज के निधन पर भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

भूटान के पीएम ने कहा कि मैं और भूटान सुषमा स्वराज के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। भूटान-भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके नेतृत्व को हमेशा याद रखेंगे। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि सुषमा स्वराज, एक वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री थीं। सरकार और भारत के लोगों के साथ-साथ परिजनों के प्रति संवेदना। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने उन्हें 'बहनजी' संबोधित करते हुए उनके निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया, 'बहनजी सुषमा स्वराज के इंतकाल से दुखी हूं। वह एक कद्दावर नेता, महान वक्ता और लोगों की नेता थीं। भारतवासियों, उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना।' अफगानिस्तान के विदेश मंत्री एस रब्बानी ने दुख जताते हुए उन्हें विशिष्ट और दृढ़निश्चयी प्रतिनिधि बताया। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर दुख प्रकट करते हुए उन्हें भारत मालदीव की दोस्ती की शिल्पकार करार दिया।

राज्यसभा में दी गई श्रद्धांजलि, भावुक हुए वेंकैया

- सदस्यों ने रखा मौन, वेंकैया ने कहा- रक्षाबंधन पर उनकी कमी महसूस करूंगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा में बुधवार को पूर्व विदेश मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदान का स्मरण किया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सुषमा उन्हें हर साल राखी बांधने आती थीं, लेकिन इस बार वह रक्षाबंधन पर नहीं आ पाएंगी, जिसका उन्हें अफसोस है।

बैठक शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू ने सदन को स्वराज के निधन की जानकारी देते हुए कहा, 'नियति ने उन्हें हमारे बीच से उठा लिया।' उन्होंने कहा कि वह तीन बार... अप्रैल 1990 से अप्रैल 1996, फिर अप्रैल 2000 से अप्रैल 2006 तथा उसके बाद अप्रैल 2006 से मई 2009 तक राज्यसभा की सदस्य रहीं।

नायडू ने कहा कि वह 'मेरी छोटी बहन' के समान थीं और उन्हें सदैव 'अन्ना' कहकर बुलाती थीं। वह हर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती थीं। नायडू ने कहा कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कहा था कि 'इस बार आप मेरे घर पर राखी बंधवाने नहीं आइएगा, क्योंकि यह उपयुक्त नहीं होगा। मैं आपके घर राखी बांधने आऊंगी।'

नई दिल्ली में लोधी रोड शवदाह गृह में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अंतिम संस्कार के दौरान उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू रो पड़े। संजय

नायडू ने कहा कि वह इस वर्ष रक्षाबंधन पर उनकी कमी बहुत महसूस करेंगे। सभापति ने कहा कि विभिन्न भूमिकाओं में उल्लेखनीय योगदान के कारण सुषमा स्वराज हमारे लिए हमेशा प्रेरणा की स्रोत रहेंगी। इसके बाद सदस्यों ने सुषमा स्वराज के सम्मान में कुछ क्षणों का मौन रखा।

सोनिया ने लिखा सुषमा के पति को पत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : सार्वजनिक जीवन में सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज भले ही एक दूसरे की धुर विरोधी रही हों, लेकिन निजी जीवन में उनके बीच मित्रवत व मधुर संबंध थे। सुषमा स्वराज के निधन पर उनके पति स्वराज कौशल को लिखे शोक पत्र में खुद सोनिया गांधी ने दिवंगत नेता के साथ अपने गर्मजोशी भरे संबंधों को याद किया है।

सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा है, 'मैं आपकी प्रिय पत्नी सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन पर स्तब्ध और बहुत दुखी हूं।' उन्होंने कहा, 'सुषमा जी एक शानदार वक्ता, महान सांसद थीं और उनका मित्रवत स्वभाव ऐसा था कि संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य में उन्हें सबका स्नेह और प्रशंसा मिली। लोकसभा में वर्षों तक सहयोगी के तौर पर हमने काम किया और हमारे बीच एक गर्मजोशी भरा संबंध बना। आज मुझे बहुत क्षति का आभास हो रहा है।' संप्रग अध्यक्ष ने आगे लिखा है, 'सुषमा स्वराज असाधारण प्रतिभा वाली महिला थीं, उन्होंने जो भी पद संभाला उस पर रहते हुए उन्होंने साहस, प्रतिबद्धता, समर्पण और योग्यता का परिचय दिया।' उन्होंने कहा है, 'वह बहुत ही मिलनसार थीं और समाज के सभी तबकों के लोगों के साथ उनका गर्मजोशी भरा रुख होता था।'

देश ने एक सम्मानित और समर्पित नेता खोया : मनमोहन

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुषमा स्वराज के निधन पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को कहा कि देश ने एक सम्मानित और समर्पित नेता खो दिया है। सुषमा स्वराज को महान सांसद और असाधारण-प्रतिभाशाली केंद्रीय मंत्री बताते हुए मनमोहन सिंह ने में कहा, 'सुषमा स्वराज जी के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। उनके लोकसभा नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उनके साथ मेरी सुखद यादें हैं।' उन्होंने कहा, 'वह एक उच्च कोटि की नेता थीं, जिनका सभी सम्मान करते थे।'

समय से घंटों पहले पहुंचे लोग

पहले पेज का शेष

अपनी प्रिय नेता सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई देने के लिए लोधी रोड श्मशान घाट पर प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। अंतिम संस्कार शाम तीन बजे होना था, लेकिन लोग दोपहर एक बजे से ही पहुंचने लगे थे।

डाइवर्ट किया गया ट्रैफिक

वीआइपी लोगों के आने व भारी संख्या में आम लोगों के जुटने के कारण लोधी रोड पर यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया था। इस कारण कुछ देर तक लोगों को आवागमन में असुविधा हुई। हालांकि, वीआइपी के जाने के बाद फिर से इस मार्ग पर यातायात सुचारू हो गया।

दिल्ली और हरियाणा में दो दिन का राजकीय शोक

दिल्ली और हरियाणा की राज्य सरकारों ने सुषमा के सम्मान में दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान सरकार की ओर से मनोरंजन से संबंधित कोई भी कार्यक्रम या गतिविधि आयोजित नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा।

देशभर के नेताओं, मुख्यमंत्रियों ने शोक प्रकट किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर देश में हर पार्टी के नेताओं, कई राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों सहित तमाम लोगों ने उन्हें एक करिश्माई नेता, महिला सशक्तीकरण का प्रतीक और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण शख्सियत बताया।

भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें अपनी सबसे करीबी सहकर्मियों में से एक और महिला नेताओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया। आडवाणी ने कहा कि एक भी ऐसा साल नहीं रहा, जब वह उनके जन्मदिन पर उनका पसंदीदा चॉकलेट केक लाना भूली हों।

भाजपा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह ने सुषमा स्वराज के निधन को भाजपा एवं भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया और कहा कि विदेश मंत्री सहित विभिन्न पदों पर काम करते हुए उन्होंने देश का मान बढ़ाया।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ट्वीट किया, 'हमारी वरिष्ठ नेत्री सुषमा जी के आकस्मिक निधन से भाजपा परिवार का प्रत्येक सदस्य शोकाकुल और स्तब्ध है।' उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे देश तथा भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया, 'स्वराज के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।' दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'भारत ने एक महान नेता खो दिया। सुषमा जी एक विलक्षण इंसान थीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।' जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उन्हें करिश्माई नेता और महिला सशक्तीकरण का प्रतीक बताया। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संवेदनाएं व्यक्त कीं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वराज के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने स्वराज के निधन को व्यक्तिगत नुकसान करार दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि स्वराज 'लोगों की मंत्री' थीं, जिन्हें देश में सामाजिक-राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सम्मान मिला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने दक्षिणी राज्य में उनके योगदान को याद किया। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने उन्हें करिश्माई व्यक्तित्व वाला एक 'स्टार महिला' बताया। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरन बेदी ने कहा, 'उनके काम करने के तरीके में गर्मजोशी और फिक्र थी।'

पाकिस्तान की कैद में रहे हामिद निहाल अंसारी के लिए दूसरी मां थीं सुषमा

मुंबई, प्रेट्र : जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में छह साल बिताकर भारत लौटे हामिद निहाल अंसारी (36) के लिए सुषमा स्वराज 'दूसरी मां' थीं। उनके निधन से हामिद बेहद व्यथित हैं।

हामिद ने बताया, 'सुषमा जी की कोशिशों की वजह से ही मैं घर लौट सका। जब मुझे बाघा-अटारी बॉर्डर पर भारत के हवाले किया गया तो वहां मैं अपने माता-पिता से मिला, मेरी एक मां थीं। बाद में जब सुषमा जी से मिला और उन्होंने मुझे बेटा कहकर आत्मीयता से गले लगाया, मुझे हिम्मत बंधाई तो मुझे लगा कि मेरी एक और मां हैं। मैं अब इस क्षति को महसूस कर रहा हूं।' सॉफ्टवेयर इंजीनियर से चमड़ा व्यवसायी बने हामिद से जब पूछा गया कि क्या सुषमा जी से उनकी बाद में और बातचीत हुई? इस पर हामिद ने कहा, 'इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने सारे इंतजाम कर दिए थे। उन्होंने हर चीज इतनी अच्छे से कर दी थी कि उनसे दोबारा संपर्क करने की कोई वजह ही नहीं थी।' मालूम हो कि हामिद इंटरनेट पर बनी एक महिला मित्र से मिलने पाकिस्तान गया था और वहां उसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हामिद की मां फौजिया ने कहा, 'ऐसा लग रहा है कि हमारे सिर के ऊपर से एक पेड़ की छांव हटा ली गई है। वह बहुत ही असाधारण नेता और महिला थीं।'

हैदराबाद की दो महिलाएं दुखी

हैदराबाद, एएनआइ : सुषमा स्वराज के निधन से हैदराबाद में रहने वाली दो महिलाएं जैनब बी और अमीना बेगम बेहद व्यथित हैं। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज की कोशिशों से ही दोनों खाड़ी देशों में दासता से मुक्त होकर भारत लौट सकी थीं। आंसुओं से भरी आंखों से जैनब ने बताया, 'जब मुझे पता चला कि सुषमा जी नहीं रहीं, मैं पूरी रात सो नहीं सकी। यह मेरे लिए बेहद दुखद है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। मैं न तो कुछ खा पाई और न ही सो सकी। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं भारत लौट सकूंगी, लेकिन सिर्फ उनकी कोशिशों की वजह से मैं भारत में अपने परिवार से मिल सकी।' इसी तरह अमीना बेगम ने बताया, 'मैंने सुषमा जी से भारत लौटने में मदद करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और सऊदी अरब जाने के एक साल बाद 2018 में मैं भारत लौट सकी। उन्होंने मुझे उन अत्याचारों से बचा लिया जो वहां मुझ पर हो रहे थे।'

अभिनेता करणवीर बोहरा ने भी पूर्व विदेश मंत्री की मदद को किया याद

नई दिल्ली, आइएएनएस : टेलीविजन अभिनेता करणवीर बोहरा ने ट्विटर पर सुषमा स्वराज की मदद को याद किया जब उन्हें क्षतिग्रस्त पासपोर्ट की वजह से हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने लिखा, 'सुनकर धक्का लगा कि सुषमा जी नहीं रहीं। एक ऐसी महिला, जिन्होंने हमारे देश की बेहतरी के लिए कठिन परिश्रम किया। विदेशी धरती पर मुश्किल में फंसे किसी भी भारतीय को उन्होंने कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। अगर सुषमा जी नहीं होतीं तो मुझे रूस में कैद कर लिया जाता। सुषमा जी की आत्मा को शांति मिले। जह हिंद।'

संवेदना

सुषमा की पहल पर पाकिस्तान से लौटी गीता इंदौर के मूक-बधिर संस्थान में रह रही हैं, उनके निधन की खबर का पता चलते ही रो पड़ीं

इशारों में गीता ने बताया- मैं अनाथ हो गई

इंदौर के मूक-बधिर संस्थान में रह रही पाकिस्तान से आई गीता को बुधवार जब यह खबर मिली कि सुषमा स्वराज नहीं रही, तो वह स्तब्ध रह गई। इशारों में अपना दुख प्रकट किया। निलेश होलकर

नईदुनिया, इंदौर

गीता बुधवार सुबह नींद से जागीं तो उनका सामना उनके जीवन की सबसे बुरी खबर से हुआ। सामने खड़ी मूक-बधिर संगठन की प्राचार्य डॉ. उषा पंजाबी इशारों में जो कुछ बता रही थीं, वह देखकर गीता को यकीन नहीं हो रहा था। जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान से भारत लाने वालीं पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ महिला नेता सुषमा स्वराज नहीं रहीं, तो वह स्तब्ध रह गईं। गीता का हैरान और बदहवास चेहरा देखकर डॉ. पंजाबी ने एक बार फिर यही जानकारी दी। यह जानकर कुछ देर तो गीता स्तब्ध सी बैठी रहीं और फिर रो पड़ीं। इशारों में बताया, मैं आज अनाथ हो गई। मेरे सिर से माता-पिता दोनों का साया एक साथ उठ गया।

गौरतलब है कि सुषमा स्वराज के विदेश मंत्री रहते अक्टूबर 2016 में मूक-बधिर गीता को पाकिस्तान से भारत लाया गया था। गीत ईदी फाउंडेशन के पास थीं और उन्होंने बताया था कि वह भारत की हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के स्कीम नं. 71 स्थित मूक-बधिर संस्थान को उनकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तब से गीता यहीं पर हैं। सुषमा स्वराज ने गीता के माता-पिता को तलाशने की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने ही गीता को 'हिंदुस्तान की बेटी' नाम दिया था। गीता ने बताया कि सुषमा से मिला प्यार, दुलार और अपनापन वह कभी नहीं भूल सकतीं। वह बिलकुल मां की तरह प्यार करती थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ देंगी। अगर मैं एक बार मिल पाती तो मुझे तसल्ली हो जाती।

दूसरे नेता भी मेरे बारे में सोचें

गीता ने बताया कि वह मुझे हमेशा मां की तरह समझाइश देती थीं। जिस तरह से वह मेरे माता-पिता को तलाशने के लिए चिंतित थीं, वैसे ही अब दूसरे नेता भी मेरे बारे में सोचें। गीता के मन में कहीं न कहीं अब यह चिंता भी उभरती नजर आई कि सुषमा स्वराज के जाने के बाद क्या उनका उसी तरह ख्याल रखा जाएगा?

गीता का कन्यादान करना चाहती थीं सुषमा

गीता को पाकिस्तान से भारत लाने में अहम भूमिका निभाने वाले सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र पुरोहित को गीता की शादी के लिए उपयुक्त लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि सुषमा स्वराज को गीता के लिए एक लड़का पसंद भी आ गया था। उन्होंने गीता को शादी के लिए मन बनाने को कहा था। तब गीता ने यह कहकर शादी से मना कर दिया था कि 'मेरे घर वाले डांटेंगे कि तुमने हमसे बिना पूछे शादी कर ली।' तब सुषमा स्वराज ने गीता को कहा था कि 'मैं हूं न, तुम मत घबराओ'। मैं तुम्हारे परिवार से भी बात करूंगी। उन्हें गीता की शादी की भी काफी चिंता थी। उन्होंने कहा था कि रिश्ता तय हो जाता है तो वह खुद गीता का कन्यादान करेंगी।

1.25 करोड़ आबादी है जम्मू-कश्मीर की। इसमें पुरुष 66.40 लाख, जबकि महिलाएं 59 लाख हैं। शहरी बेरोजगारी दर 70 फीसद है, जो राष्ट्रीय औसत 34 फीसद से दोगुनी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 अगस्त 2019

उमर और महबूबा से छिनेंगी सुविधाएं

बदलेगी तस्वीर ▶ आजाद का श्रीनगर में सरकारी निवास नहीं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं

बेहद पॉश माने जाने वाले गुपकार मार्ग पर रहते हैं उमर-महबूबा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। पुलिस हिरासत में लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती से सरकारी आवास, सुविधाएं और स्टाफ वापस ले लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुरूप कोई भी पूर्व सीएम पदाच्युत होने के बाद सरकारी निवास का अधिकार नहीं रखता है।

गौरतलब है कि इस समय केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में चार पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हैं। आजाद को छोड़ अन्य तीनों कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाले और सबसे ज्यादा पॉश माने जाने वाले गुपकार मार्ग पर रहते हैं। उमर व महबूबा जिस सरकारी निवास में रहते हैं, वह उन्हें बतौर मुख्यमंत्री आवंटित किए गए थे, लेकिन पद से हटने के बाद भी उन्होंने सुरक्षा का हवाला देकर सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं। दोनों की श्रीनगर में अपनी निजी संपत्ति भी है। गुलाम नबी आजाद ने कोई सरकारी निवास नहीं लिया है। वह कश्मीर प्रवास के दौरान गुपकार मार्ग पर ज्येष्ठा देवी मंदिर से पूर्व जठियार में स्थित जेके बैंक के गेस्ट हाउस में रुकते हैं। एक तरह से उन्होंने गेस्ट हाउस अपने लिए ले रखा है।

अपना मकान किराये पर दिया : डॉ. फारूक अपने मकान में रह रहे हैं। कथित तौर पर मकान का एक हिस्सा एस्टेट विभाग को लीज पर दिया है। इससे मिलने वाला किराया बंद हो सकता है। डॉ. फारूक का कहना है कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें सरकारी मकान आवंटित करना राज्य की जिम्मेदारी है।

50 करोड़ रुपये की राशि साज सज्जा पर खर्च की जाती : राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उमर और महबूबा मुफ्ती के निवास पर करीब 50 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न सुविधाओं को जुटाने व साज सज्जा पर खर्च की गई है। उमर के निवास में जिम भी है।

श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र नौगाम में स्थित महबूबा के पिता स्व. मुफ्ती मुहम्मद सईद के निजी मकान के सौंदर्यीकरण और आवश्यक मरम्मत पर भी राज्य सड़क एवं भवन निर्माण विभाग ने लाखों रुपये खर्च किए हैं। चारों पूर्व सीएम को सुरक्षा के नाम पर पुलिस व केंद्रीय बलों का दस्ता, जैमर, बुलेट प्रूफ वाहनों के अलावा घरों में विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कुछ सरकारी स्टाफ भी हैं। इनका खर्च भी राज्य सरकार उठाती है। केंद्रीय कानून लागू होने के बाद सभी से यह सुविधाएं वापस ली जा सकती हैं। सुरक्षा दस्ते में भी कटौती हो सकती है।

नेकां व पीडीपी के एजेंडे भी समाप्त

सतनाम सिंह, जम्मू

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होते ही नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एजेंडे दफन होकर रह गए।

अनुच्छेद 370 से मिले विशेष अधिकारों के कारण कश्मीर में राज करने वाली नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जरूरत से ज्यादा आजादी तो नहीं मिली, लेकिन जो विशेष अधिकार थे वह भी हाथ से निकल गए। कश्मीर केंद्रित पार्टियां खुद मुख्तियारी के नाम पर राज्य के अधिकारों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र पर दबाव बनाती रही।

नेकां ने स्वायत्तता का मुद्दा छेड़कर शुरुआत की। 26 जून 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला के समय जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र को भेजा गया। नेकां ने चुनाव में इसे मुद्दा बनाया, लेकिन केंद्र ने कभी इस पर गौर नहीं किया। इस बार भी नेकां ने वायदा किया था कि अगर वह सत्ता में आई तो स्वायत्तता को लागू करेगी।

पीडीपी ने अक्टूबर 2008 में स्वायत्तता के मुद्दे से एक कदम आगे बढ़कर स्वशासन का मुद्दा उठाया। पार्टी के मुख्य संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 25 अक्टूबर 2008 में महबूबा मुफ्ती की उपस्थिति में श्रीनगर में स्वशासन का दस्तावेज जारी किया। विधानसभा चुनाव से पहले यह दस्तावेज जारी करते हुए पीडीपी ने इसे मुद्दे बनाया।

स्वशासन में यह भी था कि अनुच्छेद 356 को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जाए। राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं होने चाहिए कि वे सरकार या विधानसभा को भंग कर सकें। पीडीपी ने चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया। पीडीपी ने वर्ष 2002 से 2008 तक कांग्रेस के साथ सरकार चलाई। वर्ष 2008 में नेकां ने कांग्रेस के साथ छह साल तक सरकार चलाई।

डोभाल का संदेश, कश्मीर में 'ऑल इज वेल'

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ आतंक के गढ़ शोपियां में सड़क पर आम लोगों के साथ खाया खाना

▶ स्थानीय लोगों से जानी राय, सुरक्षाबलों के साथ भी मिले

जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बुधवार को शोपियां जिले में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए। प्रेट्र

जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित किए जाने के बाद कश्मीर घाटी में पैदा हालात पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने घाटी के विभिन्न इलाकों में दौरा कर सुरक्षाबलों से लेकर आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कई जगहों पर लोगों ने उन्हें अपने घर पर चाय की दावत भी दी। आतंकियों का गढ़ कहलाने वाले दक्षिण कश्मीर के शोपियां में उन्होंने सड़क पर लोगों के साथ खाना खाकर देश-दुनिया को संदेश दिया कि यहां सबकुछ सामान्य चल रहा है।

राज्य के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी हो गई है। एहतियातन गत रविवार रात से ही प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगा रखी है। सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को पहले घाटी से निकाला जा चुका है। मंगलवार को श्रीनगर पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से हालात पर चर्चा की और पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिकबलों के आलाधिकारियों के साथ बैठक की थी।

बुधवार को उन्होंने श्रीनगर के विभिन्न इलाकों का जायजा लिया। कुछ जगहों पर खरीदारी कर रहे लोगों से कश्मीर के ताजा हालात और केंद्र सरकार के फैसले पर भी विचार विमर्श किया। इसके बाद राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के साथ दक्षिण कश्मीर के दौरे पर निकले। उन्होंने अवंतीपोर, पुलवामा और शोपियां में पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों व अधिकारियों के साथ बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया।

डोभाल शोपियां में विभिन्न बाजारों में भी गए। वहां लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों ने राज्य के पुनर्गठन के मुद्दे पर आशंकाएं जाहिर की, लेकिन डोभाल ने उनकी चिंताओं को दूर किया। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अपने घर में चाय की दावत भी दी। डोभाल उनके घर तो नहीं गए, लेकिन बाजार में ही उनके साथ खाना खाया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि राज्य के पुनर्गठन का फैसला स्थानीय लोगों की उम्मीदों और कश्मीर को ब्लैकमेल की राजनीति से आजाद कराने के लिए ही लिया गया है। वह दोपहर बाद श्रीनगर लौट आए।

राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ही निष्प्रभावी हुआ अनुच्छेद 370

▶ कानून मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना

▶ संसद के दोनों सदनों से संकल्प पारित होने के बाद यह कदम उठाया गया है

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा कर दी है। संसद के दोनों सदनों से इससे संबंधित संकल्प पारित होने के बाद यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही अब जम्मू-कश्मीर में यह अनुच्छेद निष्प्रभावी हो गया है।

कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि छह अगस्त, 2019 से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड, सिवाय निम्नलिखित के, जो नीचे दिए गए के अनुसार है, प्रचलन में नहीं रहेंगे, अर्थात :- '370. इस संविधान के समय समय पर यथा-संशोधित, सभी उपबंध बिना किन्हीं उपांतरणों या अपवादों के अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू-कश्मीर के संविधान में किसी अन्य उपबंध या किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ी या प्रथा या किसी लिखित संधि या करार जो अनुच्छेद 363 के अधीन यथा-परिकल्पित या अन्यथा है, मैं तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होंगे।'

मालूम हो कि भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने का संकल्प और विधेयक पेश किया था।

उसी दिन ये राज्यसभा से पारित भी हो गए थे। लोकसभा ने भी प्रस्ताव और विधेयक को भारी बहुमत से मंगलवार को स्वीकृति दे दी थी। भाजपा ने लोकसभा चुनावों में इसका वादा किया था जिसे मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 90 दिनों के भीतर पूरा कर दिया।

जम्मू-कश्मीर से दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे कैदी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद अब वहां की जेलों में बंद कैदियों को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। जम्मू-कश्मीर से पहली खेप में गुरुवार को 30 कैदियों को आगरा सेंट्रल जेल लाया जायेगा। यहां उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच तनहाई बैरकों में रखा जायेगा।

जम्मू-कश्मीर से बंदियों को उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य बड़े राज्यों की जेलों में भी भेजा जायेगा। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकार से सहमति मांगी थी। यूपी में और अधिक बंदियों को भेजे जाने की तैयारी थी, लेकिन फिलहाल 30 लोगों को ही लाया जा रहा है। बताया गया है कि यूपी की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों के बंद होने के चलते दिक्कत है। पहले चरण में आगरा स्थित सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था की गई है। जम्मू-कश्मीर से बंदियों को हवाई जहाज से आगरा लाया जायेगा। आगरा हवाई अड्डे से सेंट्रल जेल के बीच पुलिस का कड़ा पहरा होगा। पुलिस-प्रशासन से लेकर खुफिया विभाग हाई अलर्ट है। उच्च स्तर पर सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिये गये हैं। आगरा के डीएम व एसएसपी को जेल की सुरक्षा-व्यवस्था परखने के निर्देश भी दिये गये।

घाटी से फंसे 10 हजार श्रमिक वापस लौटे

जागरण न्यूज नेटवर्क, जम्मू

▶ सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के बाद भी विभिन्न हिस्सों में फंसे थे श्रमिक

▶ करीब 4200 श्रमिक विशेष ट्रेनों से दरभंगा भेजे गए

जम्मू रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही विशेष रेलगाड़ी में सवार होकर अपने घर को लौटते विभिन्न राज्यों के श्रमिक। ये श्रमिक कश्मीर घाटी से लौटे हैं। जागरण

घाटी में फंसे बाहरी राज्यों के श्रमिक अब धीरे-धीरे बाहर निकलने लगे हैं। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद माहौल बेशक शांत हैं, लेकिन वहां रह रहे दूसरे राज्य के लोगों में तमाम तरह की आशंकाएं हैं। उन्होंने फिलहाल लौटना मुनासिब समझा।

गौरतलब है कि 2 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियों ने बाबा अमरनाथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों व बाहरी राज्य के लोगों को घाटी छोड़ने की सलाह दी थी। इसके बाद यात्रा को स्थगित कर लोगों को विशेष बसों और रेलगाड़ियों के माध्यम से घाटी से निकाला था। मगर कुछ श्रमिक दूर-दराज के क्षेत्रों में होने के कारण फंस गए थे। अब वह भी धीरे-धीरे वहां से बाहर निकलने लगे हैं। मंगलवार और बुधवार को घाटी के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे करीब 10 हजार श्रमिक घाटी को छोड़कर जम्मू और ऊधमपुर पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में विभिन्न राज्यों के सात हजार से अधिक श्रमिक जम्मू कश्मीर से अपने-अपने घरों को रवाना हो गए हैं।

बुधवार को करीब चार हजार श्रमिकों को ऊधमपुर और जम्मू रेलवे स्टेशन से 20 जनरल कोच वाली दो विशेष ट्रेनों के जरिये दरभंगा रवाना किया गया। दोनों ट्रेनें अंबाला, लखनऊ, गोरखपुर, समस्तीपुर से होते हुए दरभंगा में पहुंचेंगी। पिछले 24 घंटे में विभिन्न रेलगाड़ियों के माध्यम से तीन हजार श्रमिक और यात्री विभिन्न राज्यों के लिए रवाना हुए हैं। अन्य फंसे श्रमिकों के लिए गुरुवार को विशेष ट्रेन के जरिये जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा जाएगा।

ऊधमपुर से 2375, जम्मू से 1800 श्रमिक भेजे : फिरोजपुर डिवीजन के डीआरएम राजेश अग्रवाल ने बताया कि घाटी से लौटे श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचने के लिए दो विशेष रेलगाड़ियां रवाना की हैं। ऊधमपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर बाद 16:20 बजे दरभंगा के लिए एक रेलगाड़ी में 2375 यात्री रवाना किए। इसके अलावा रात आठ बजे जम्मू रेलवे स्टेशन से एक और 20 कोच वाली विशेष रेलगाड़ी में 1800 के करीब यात्रियों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि वीरवार को ऊधमपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर दो बजे एक और विशेष रेलगाड़ी दरभंगा रवाना की जाएगी। तीनों रेलगाड़ियों में घाटी से लौटने वाले सभी लोगों को घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा अन्य ट्रेनों के जरिये भी यहां से यात्री रवाना हुए हैं।

45 बसों में रवाना हुए बाहरी राज्यों के श्रमिक और यात्री : घाटी में फंसे श्रमिक जब जम्मू में पहुंचे तो रात को चलने वाली प्राइवेट बस आपरेटरों की बसें बुधवार दोपहर शुरू हो गई। नरवाल स्थित आइएसबीटी से रात तक 25 स्लीपर और वॉल्वो बसें के माध्यम से श्रमिक और यात्री रवाना हुए। पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से कटड़ा के लिए अंतर राज्यीय बस सेवा सामान्य रही। जम्मू बस अड्डे से राज्य परिवहन निगम की 20 बसें यात्रियों को लेकर दिल्ली, अमृतसर और जालंधर के लिए रवाना हुई। शाम को दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार और जयपुर जाने वाली बस सेवा प्रभावित रही।

30 बसें घाटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजीं : कश्मीर में अभी भी हजारों की तादाद में बाहरी राज्यों के श्रमिक फंसे हैं। राज्य परिवहन निगम ने यात्रियों को निकालने के लिए बुधवार को 30 बसें श्रीनगर के लिए रवाना किया जो वीरवार सुबह टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर श्रीनगर से यात्रियों को लाएंगी। एसआरटीसी के जीएम आपरेशन स. परमजीत सिंह ने बताया कि घाटी में फंसे यात्रियों को सुरक्षित जम्मू पहुंचाया जाएगा।

इस्लामाबाद में जगह-जगह लगे 'अखंड भारत' के पोस्टर

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जगह-जगह भारत के समर्थन में बैनर लगने से हड़कंप मच गया। भारत सरकार द्वारा सोमवार को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद मंगलवार को 'अखंड भारत' लिखे ये बैनर पाकिस्तानी संसद नेशनल असेंबली और पीएम इमरान खान के आवास के पास भी दिखे। पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो प्रिंटिंग प्रेस चलाता है।

महा-भारत लिखे बैनर पर सबसे ऊपर 'अखंड भारत' का नक्शा छपा था। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को मिल अखंड भारत का हिस्सा बताया गया था। बलूचिस्तान को लेकर एक चेतावनी भी थी।

समाचार पत्र डॉन के मुताबिक एक बैनर पर भड़काऊ संदेश में कहा गया था, 'अखंड भारत रियल टेरर' यानी अखंड भारत की विचारधारा असली आतंकवाद है। बैनर पर भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही का फोटो छपा था, जिसमें शिवसेना नेता संजय राउत नजर आ रहे थे। बैनर पर संजय राउत का वो भाषण भी छपा था जिसमें उन्होंने कहा था, 'आज जम्मू-कश्मीर लिया, कल बलूचिस्तान, पीओके (पाक के कब्जे वाला कश्मीर) लेंगे। मुझे विश्वास है देश के प्रधानमंत्री अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे।' बता दें कि यह अखंड भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य लक्ष्यों में से एक रहा है। साथ ही यह बीजेपी का भी उद्देश्य रहा है।

सेक्टर एफ-6 में प्रेस क्लब के सामने वाली सड़क और अबपारा चौक पर बिजली के खंबों पर भी बैनर लगाए गए थे। साजिद महमूद नाम के एक व्यवसायी ने सबसे पहले इस बैनर को देखा। इसके बाद उन्होंने इसका एक वीडियो बनाया और फिर उसे ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते दो मिनट का ये वीडियो वायरल भी हो गया। इसके बाद पाकिस्तान की कानून-प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया।

शहर के पुलिस अधीक्षक अमीर खान ने संवादाता को बताया कि राजधानी क्षेत्र की पुलिस ने बैनर हटा दिए हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने बताया है कि पंजाब के गुजरांवाला के किसी व्यक्ति ने उसे बैनर बनाने का ऑर्डर दिया था।

श्रीनगर में दुकानें खुलीं, लोगों ने की खरीदारी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ प्रशासनिक पाबंदियों, इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं तीसरे दिन भी बंद

▶ कुछ जगहों पर शरारती तत्वों का सुरक्षाकर्मियों पर पथराव, 12 घायल

अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी प्रशासनिक पाबंदियों, इंटरनेट सेवा और टेलीफोन सेवाओं पर रोक रही। श्रीनगर सहित कई क्षेत्रों में दुकानें खुलने से लोगों ने खरीदारी की। वहीं कुछ जगहों पर हिंसक झड़पों में एक दर्जन लोग जख्मी हो गए। जम्मू संभाग में स्थिति नियंत्रण में है। निजी बस ऑपरेटर और एसआरटीसी की अंतरराज्यीय और अंतर जिला बस सेवा बहाल हो गई। हालांकि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद गुरुवार को भी बंद रहेंगे। जम्मू विवि ने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है।

राज्य के पुनर्गठन के साथ ही घाटी में तनाव पैदा हो गया था। अपेक्षाकृत शांत माने जाने वाले मौलाना आजाद रोड, राजबाग, इंदिरा नगर और श्रीनगर के बाहर कुछ कस्बों में लोग घरों से बाहर निकले तो सुरक्षाबलों ने नहीं रोका। कुछेक जगहों पर रेहड़ी-फड़ी पर सामान बेचने वाले भी निकले। शहर के भीतरी हिस्सों में दुकानें खुलीं। ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुली।

श्रीनगर समेत सभी शहरों और कस्बों में बड़ी संख्या में पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिकबलों के जवान तैनात हैं। डाउन-टाउन समेत वादी के किसी संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। स्कूल-कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद रहे। श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर के बारामुला में कुछ जगहों पर शरारती तत्वों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर जुलूस निकलाने का प्रयास करते हुए सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया। हिंसक झड़पों में एक दर्जन लोगों के जख्मी होने की सूचना है। कहा जा रहा है कि गत सोमवार को पालपोरा में पुलिसकर्मियों से बचने के प्रयास में एक प्रदर्शनकारी ने कथित तौर पर झेलम दरिया में छलांग लगा दी और दरिया में डूबने से उसकी मौत हो गई। उसका नाम उसैब अल्ताफ बताया जाता है। आधिकारिक स्तर पर किसी ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं है। श्रीनगर के जिला उपायुक्त शाहिद इकबाल ने छिटपुट हिंसा की पुष्टि करते हुए कहा कि शहर में कोई बड़ी गंभीर घटना नहीं हुई है। किसी जगह कोई कर्फ्यू भी नहीं है। एसएसपी सिक्योरिटी इम्तियाज हुसैन मीर ने भी हिंसा और किसी युवक की मौत से इन्कार करते हुए कहा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोग धीरे-धीरे घरों से बाहर आ रहे हैं।

तत्काल तीन तलाक से भी मिली आजादी

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू कश्मीर की मुस्लिम महिलाओं को भी तत्काल तीन तलाक से आजादी मिल गई है। साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में निर्धारित 10 फीसद आरक्षण का लाभ भी प्रभावी हो गया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अधिसूचना जारी होने और अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद 100 से भी अधिक केंद्रीय कानून लागू हो गए। प्रदेश में जवाबदेही आयोग, प्रदेश सूचना कानून, पब्लिक गारंटी व स्टेट कंज्यूमर एक्ट और रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) जैसे कई कानून समाप्त हो गए।

कोर्ट नहीं करेगा जमीन की रजिस्ट्री : जम्मू-कश्मीर में धारा 370 व 35ए के चलते जमीन की खरीद-फरोख्त कोर्ट के माध्यम से होती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई। अब राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास जमीन की खरीद-फरोख्त करवाने का अधिकार होगा। कोर्ट के स्थान पर तहसीलदार या असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू को यह अधिकार दिए जा सकते हैं।

कश्मीर के दर्जे में बदलाव पर संरा का टिप्पणी से इन्कार

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के भारत के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र ने कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है। महासचिव के प्रवक्ता ने इस सवाल पर भी कुछ नहीं किया कि भारत का यह कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प का उल्लंघन है। पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को यह दावा करते हुए संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा था।

भारत सरकार ने सोमवार को अनुच्छेद 370 खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। बुधवार को राष्ट्रपति ने राज्य के पुनर्गठन की संसद की सिफारिश पर दस्तखत कर दिए और अधिसूचना जारी होते ही जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बन गया। जम्मू-कश्मीर का हिस्सा रहा लद्दाख भी अब अलग केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा, हम क्षेत्र में बन रहे हालात को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए महासचिव सभी संबद्ध पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील कर चुके हैं। डुजारिक ने जम्मू-कश्मीर का दर्जा बदले जाने पर कोई टिप्पणी करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।

प्रवक्ता से जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के पत्र के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ऐसे किसी पत्र के बारे में जानकारी होने से इन्कार कर दिया। यह वही पत्र है जिसमें पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन होने का दावा किया है। प्रवक्ता ने कहा, ऐसा कोई पत्र प्राप्त होने पर उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद कोई जवाब दिया जाएगा। महासचिव ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव पर चिंता जताई थी और दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की थी।

अमेरिका में भारतीय राजदूत की दो टूक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन आंतरिक मामला

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन भारत का आंतरिक मामला है और इस फैसले से दूसरे देशों के साथ संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 'समकालीन भारत : विदेश नीति, विकास रणनीति और मोदी 2.0 के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताएं' पर बातचीत में श्रृंगला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन अंतरराष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा को प्रभावित नहीं करता है। यह कदम बेहतर प्रशासन के लिए उठाया गया है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि जो सामाजिक-आर्थिक लाभ भारत के अन्य लोगों को मिलते हैं, वे जम्मू-कश्मीर के लोगों, विशेषकर वंचित वर्ग को भी मिलें।

अमेरिका ने कहा, जम्मू-कश्मीर पर नहीं थी जानकारी : अमेरिका ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर पर बड़े फैसले लेने से पहले भारत ने उसे जानकारी दी थी। दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की अमेरिकी उप मंत्री एलिस जी वेल्स ने ट्वीट कर यह स्पष्टीकरण दिया है। खबरों में कहा गया था कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और उसका पुनर्गठन करने की पूर्व जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो को बैंकॉक (थाइलैंड) दौरे में दे दी गई थी। बीत चुके हफ्ते में आसियान देशों के कार्यक्रम के दौरान पोंपियो की अपनी भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात हुई थी।

लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धौनी बने कश्मीर के रक्षक

नई पारी

दक्षिण कश्मीर में तैनात पूर्व कप्तान धौनी बालीवॉल में आजमा रहे हाथ, गीत गुनगुनाकर बढ़ा रहे जवानों का हौसला

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धौनी दक्षिण कश्मीर में अपनी यूनिट के साथियों के साथ बालीवाल खेलते हुए। धौनी इन दिनों दक्षिण कश्मीर में तैनात हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

धौनी दक्षिण कश्मीर में अपने जूते खुद पालिश करते हुए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धौनी कश्मीर में रक्षक की भूमिका में हैं। दक्षिण कश्मीर में तैनाती के दौरान वह अपने तरीके से जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कभी मेस में तो कभी गश्त के दौरान गीत गुनगुनाते हैं। वह तय समय पर सुबह-शाम मैदान में पीटी करते व बालीवॉल खेलते नजर आ रहे हैं।

धौनी सेना की 106 टीए बटालियन पैरा के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उन्हें यह रैंक 2011 में प्रदान किया गया था। उन्होंने कुछ समय पहले कश्मीर में सेवाएं देने की इच्छा जताई थी। रक्षा मंत्रालय ने उन्हें दक्षिण कश्मीर में तैनात 106 टीए बटालियन में ड्यूटी की अनुमति दी थी। उन्होंने गत शुक्रवार को औपचारिक रूप से अपनी ड्यूटी संभाली थी।

जवानों के बीच गा रहे ...मैं पल दो पल का शायर हूं : क्रिकेट की चकाचौंध से दूर धौनी एक सैन्य अधिकारी की जिंदगी जी रहे हैं। सोने के लिए दस फुट का कमरा है, जिसमें एक तख्त है। अपने सभी निजी कार्य खुद कर रहे हैं। जूते स्वयं पालिश कर रहे हैं। अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों की हाजिरी लेने के साथ उनके लिए काम भी आवंटित कर रहे हैं। वह वरिष्ठ अधिकारियों को काम-काज की रिपोर्ट भी कर रहे हैं। धौनी अक्सर शाम को मेस में खाने की मेज पर गाने गुनगुनाते हैं। विक्टर फोर्स में अपनी सैन्य जिंदगी के सफर के वीडियो धौनी ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं। बालीवॉल खेलते, बूट पालिश करते उन्होंने अपनी तस्वीरें व वीडियो शेयर किए हैं। कभी-कभी फिल्म का गीत ..मैं पल दो पल का शायर भी वह गुनगुनाते हुए एक वीडियो में नजर आ रहे हैं। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है।

15 अगस्त तक कश्मीर में रहेंगे धौनी

दक्षिण कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों का संचालन कर रही सेना की विक्टर फोर्स के अवंतीपोर स्थित मुख्यालय में ही 106 टीए बटालियन तैनात है। विक्टर फोर्स मुख्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके पास ही है। संबंधित सैन्य अधिकारियों के अनुसार, धौनी को आतंकरोधी अभियानों की ड्यूटी नहीं दी गई है। वह 15 अगस्त तक यहीं रहेंगे।

उप्र के पीलीभीत के धर्मस्थल में आगजनी, तनाव

जासं, पीलीभीत : उप्र के पीलीभीत शहर से सटे गौहनियां गांव में बुधवार को खुराफातियों ने धर्मस्थल में रखा सामान जलाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया। इससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। सुनगढ़ी थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट की गई है। एहतियात के तौर पर गांव में फोर्स तैनात है। गौहनियां के कुछ बच्चों ने बुधवार सुबह गांव के बाहर स्थित दूसरे समुदाय के धर्मस्थल से धुआं निकलते देख ग्रामीणों को जानकारी दी। दूसरे समुदाय के लोग जुट गए। पता चला कि किसी खुराफाती ने धर्मस्थल में चादर व अन्य सामान में आग लगा दी है।

जनमत

मुद्दा

क्या जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भारत के साथ सही मायने में उसके जुड़ाव के बीच अघोषित रुकावट था?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। MUDDA लिखें, स्पेस देकर YES या NO लिखकर 57272 पर भेजें।

1.13 लाख लोगों को अब तक महाराष्ट्र में सुरक्षित जगह पर भेजा जा चुका है। राज्य में बारिश से मुंबई, पुणे और नासिक के बाद अब कोल्हापुर व सांगली में भी हालात बिगड़ गए हैं। राहत-बचाव कार्य के लिए नेवी और वायु सेना की भी मदद ली जा रही है।

जांच में सही पाए गए हैं दुष्कर्म पीड़िता के आरोप : सीबीआइ

उन्नाव दुष्कर्म कांड ▸ सीबीआइ ने अदालत में आरोप पत्र के कुछ अंश पेश किए, शुक्रवार तक के लिए टली सुनवाई

कोर्ट ने कहा, पीड़िता, परिजनों और गवाहों का नाम-पता न लिखे मीडिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उन्नाव कांड से जुड़े दुष्कर्म के मामले में बुधवार को तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा (पश्चिम) की अदालत में सीबीआइ ने आरोप पत्र के कुछ अंश पेश किए। इसमें जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि अभी तक की जांच में पीड़िता के आरोप सही पाए गए हैं। शशि सिंह ने नौकरी का लालच देकर पीड़िता को कुलदीप सिंह सेंगर के घर पहुंचाया। उस वक्त घर पर सुरक्षा कर्मी नहीं थे। वहां सेंगर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ था।

सीबीआइ ने अदालत में पीड़िता का बयान दोहराया कि किस तरह उस पर दबाव बनाया गया। वहीं, कुलदीप सिंह सेंगर के वकीलों की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि आरोप गलत हैं। अदालत में आरोप तय करने के लिए सुनवाई काफी देर तक चली और बाद में इसे शुक्रवार के लिए टाल दिया गया।

पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को तय की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मीडिया पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। अदालत ने कहा कि मीडिया पीड़िता, उनके परिजनों और गवाहों के बारे में कोई जिक्र न करे।

दुष्कर्म पीड़िता और वकील की हालत अब भी गंभीर: दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गंभीर हालत में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता और उनके वकील की हालत में अब तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। एम्स की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वकील अब भी अचेत हैं।

सीबीआइ ने चश्मदीदों से की पूछताछ

जासं, नई दिल्ली : उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की कार के हादसे स्थल रायबरेली के अटौरा में बुधवार सुबह फिर सीबीआइ टीम पहुंची। इस बार जांच की अगुवाई एडीशनल डायरेक्टर ने की। चार चश्मदीदों से पूछताछ की गई। यूपी-100 के दो कर्मियों के बयान दर्ज हुए। एसपी से अटौरा के आसपास पिछले पांच साल में हुए सड़क हादसों का ब्योरा तलब किया गया है। वहीं सीबीआइ लखनऊ मुख्यालय में मौरंग आढ़तियों से पूछताछ का क्रम जारी रहा। सुबह लगभग 10 .45 बजे जांच एजेंसी के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा, संयुक्त निदेशक संपत मीना सात सदस्यीय टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

पीड़िता के खून में बैक्टीरिया, बेअसर थीं दवाइयां

जागरण संवाददाता, लखनऊ

▸ केजीएमयू की कल्चर रिपोर्ट से मिली जानकारी

▸ बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजी जाएगी रिपोर्ट

उप्र के उन्नाव (माखी) कांड की पीड़िता के रक्त में संक्रमण मिला है। रक्त में खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है जिससे उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है। इसी कारण उसे दी जाने वाली मुख्य एंटीबायोटिक दवाएं भी बेअसर साबित हो रही हैं।

पीड़िता को लखनऊ के केजीएमयू में 28 जुलाई को भर्ती कराया गया था। मल्टीपल फ्रैक्चर की वजह से उसके शरीर में अंदरूनी रक्तस्राव हुआ। तकरीबन ढाई लीटर ब्लड लॉस की वजह से वह शॉक में चली गई। ट्रॉमा में भर्ती के दौरान एक अगस्त को कल्चर जांच के लिए सैंपल माइक्रोबायोलॉजी विभाग भेजे जा गए थे। इस बीच पांच अगस्त को उसे एम्स, दिल्ली भेज दिया गया। मंगलवार को कल्चर जांच की रिपोर्ट ट्रॉमा सेंटर के वेंटिलेटर विभाग पहुंची। रिपोर्ट में घातक ब्लड इंफेक्शन की बात कही गई है। उसके खून में एंटिरोकोकस बैक्टीरिया मिला। साथ ही अधिकतर एंटीबायोटिक बेअसर पाई गईं।

अब सेप्टीसीमिया से निबटना चुनौती : विशेषज्ञों के मुताबिक, एंटिरोकोकस बैक्टीरिया खतरनाक है। यह मरीजों के ब्लड में रेयर ही पाया जाता है। दावा है कि यह बैक्टीरिया अधिकतर फीकल (मल) में पाया जाता है। ब्लड में बैक्टीरिया होने से अब सेप्टीसीमिया से निबटना चुनौती होगी।

> पीड़िता में एंटिरोकोकस बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। इसकी रिपोर्ट एम्स भेज दी जाएगी। मल्टी ड्रग रजिस्टेंस की जानकारी नहीं है।
> -डॉ. संदीप तिवारी, प्रवक्ता, केजीएमयू (लखनऊ)

सात में से छह दवाएं फेल : आइसीयू में भर्ती मरीजों को दी जाने वाली प्रमुख एंटीबायोटिक के प्रभाव की टेस्टिंग की गई। लैब में ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग में सात एंटीबायोटिक दवाओं की जांच की गई। उसमें से पीड़िता पर छह एंटीबायोटिक बेअसर पाई गईं। इसमें वैंकोमाइसिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन-हाई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाओं का ड्रग रजिस्टेंस मिला। विशेषज्ञों ने इसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस करार दिया।

यूनिट में इंफेक्शन कंट्रोल पर उठे सवाल

ब्लड में बैक्टीरिया पहुंचने पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह बैक्टीरिया मरीज के चेस्ट ट्यूब डालने, इंडोट्रैकियल वेंटिलेटर ट्यूब से, दवा देने के लिए डाली गई सेंट्रल लाइन से, यूरिन कैथेटर से व साफ-सफाई का ध्यान न रखने से फैलता है। जाहिर है कि केजीएमयू की वेंटिलेटर यूनिट में इंफेक्शन कंट्रोल का ठोस प्रबंध नहीं है। अभी गत माह भर्ती मरीज में कैंडिडा ऑरिस बैक्टीरिया पाया गया था, जिसकी मौत भी हो गई थी।

दुष्कर्म पीड़िता के पिता के इलाज में हुई थी लापरवाही, डाक्टर दोषी

जागरण संवाददाता, उन्नाव

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता के इलाज में जेल से उमाशंकर दीक्षित जिला अस्पताल तक लापरवाही बरती गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें जेल से अस्पताल रेफर करते वक्त डॉक्टर ने पूर्व में हुई जांच रिपोर्ट ही नहीं भेजी। जिला अस्पताल में ईएमओ ने हालत गंभीर होने पर भी उन्हें दूसरे हॉस्पिटल रेफर नहीं किया। ये सच्चाई निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की जांच में सामने आई। उन्होंने दोनों को दोषी मानकर कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी। उन पर कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

पीड़िता के पिता को विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल आदि ने पीटा था। माखी पुलिस ने घायल को ही तमंचा रखने के आरोप में तीन अप्रैल 2018 को जेल भेज दिया था। गंभीर चोट होने से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरे दिन डॉक्टरों ने पुलिस के अनुरोध पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। न्यायालय से उन्हें जेल भेजा गया। आठ अप्रैल-2018 की रात हालत बिगड़ी तो जेल के डॉ. वंशबहादुर ने उन्हें जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में आकस्मिक चिकित्साधिकारी (ईएमओ) डॉ. गौरव अग्रवाल ने उन्हें भर्ती किया। हालत गंभीर होने पर भी रेफर नहीं किया। नौ अप्रैल की सुबह पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी। उक्त मामले में राज्यपाल ने विभागीय जांच के आदेश दिए थे। निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. पूजा पांडेय ने जांच की। रिपोर्ट में उन्होंने डॉ. गौरव पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप सही पाया वहीं कारागार के डॉ. वंशबहादुर पर रेफर के साथ जांच रिपोर्ट नहीं भेजने का आरोप सच मिला। निदेशक ने शासन को भेजी रिपोर्ट में दोनों पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। उनका निलंबन तय माना जा रहा है वहीं डॉक्टरों में चर्चा है कि मामला हाई प्रोफाइल होने से दोनों की बर्खास्तगी भी हो सकती है।

दो डॉक्टर दोषमुक्त: मामले में जिला अस्पताल के डॉ. मनोज सिंह, सर्जन डॉ. जीपी सचान और ईएमओ डॉ. गौरव अग्रवाल आरोपित थे। डॉ. मनोज को प्राथमिक जांच में ही दोषमुक्त कर दिया गया जबकि डॉ. सचान अब बेकसूर साबित हुए।

डॉक्टरों से 15 दिन में मांगा जवाब: निदेशक प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर शासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्यपाल के निर्देश पर सचिव वी हेकाली झिमोमी ने उमाशंकर दीक्षित जिला अस्पताल के ईएमओ डॉ. गौरव व जेल डॉक्टर वंश बहादुर से 15 दिन में जवाब मांगा है।

एसआइटी ने जानी सोनभद्र नरसंहार की हकीकत

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : सोनभद्र के उभ्भा गांव नरसंहार मामले में कड़ी कार्रवाई के बाद गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने बुधवार को गांव में पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और घटनास्थल देखा। करीब डेढ़ घंटे तक टीम ने एक-एक बिंदु पर पड़ताल की।

डीआइजी जे रवींद्र गौड़ के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल नौ लोग बुधवार दोपहर गांव पहुंचे। सबसे पहले गांव के लोगों से मिलकर 17 जुलाई की घटना के बारे में पूछा। इसके बाद मृतकों के परिवार वालों से मिले। घायलों से मिलकर घटना के समय का माहौल पूछा। इसके बाद टीम ने घटनास्थल पर जमीन देखने के साथ गांव के कैलाश को बुलाकर पूछताछ की। उनकी जमीन के खाता नंबर और जोत के बारे में विस्तार से पूछा। इसके बाद गांव के रामराज से कुछ जरूरी कागजात लिये। जिसमें उन्होंने आरटीआइ के माध्यम से सूचना जुटाई थी। 1989 में जमीन व्यक्तिगत हाथों में जाने व 1952 में पट्टा आदि के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने ग्रामीणों पर कब-कब, किन-किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, उन्होंने क्या किया इसके बारे में भी पूछा। बता दें कि टीम दो महीने में शासन को अपनी रिपोर्ट देगी।

रांची राजधानी एक्सप्रेस में छात्रा से छेड़छाड़, टीटीई निलंबित

जागरण संवाददाता, रांची

▸ ट्वीट कर शिकायत की तो हरकत में आए अधिकारी, जांच के लिए बनी टीम

नई दिल्ली से रांची आ रही एक छात्रा से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में टीटीई और पेंट्री कार के वेटर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। छात्रा ने ट्वीट कर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी और रेल मंत्री पीयूष गोयल, पीएमओ, रेलवे, सीएम रघुवर दास और झारखंड भाजपा को टैग कर आरोपित टीटीई और वेटर पर कार्रवाई की मांग की तो रेलवे के अधिकारी हरकत में आए। इसके बाद आरोपित टीटीई एनआर सरोज को निलंबित करते हुए पेंट्रीकार के वेटर वीर बहादुर सिंह को हटा दिया गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। युवती ने इस मामले में लिखित प्राथमिकी दर्ज कराने से इन्कार किया है।

यह है मामला : पीड़ित छात्रा का कहना है कि मंगलवार को वह राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली से अकेले रांची आ रही थी। टिकट बुकिंग के समय उसने खाने का ऑर्डर नहीं दिया था। बाद में भूख लगी तो उसने टीटीई और वेटर से बात की तो खाने का इंतजाम कर दिया गया। खाने के साथ आइसक्रीम के बदले उसे मिठाई मिली थी, लेकिन वह आइसक्रीम खाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद बहस होने के बाद युवती रोने लगी। यह देख टीटीई ने आइसक्रीम का इंतजाम करा दिया। उसने छात्रा का नंबर यह कहकर लिया कि वह खुद भी हालचाल पूछता रहेगा। इसके बाद टीटीई चला गया।

छात्रा ने बताया कि सुबह टीटीई ने उसे शौचालय के पास बुलाया। जब वहां गई तो टीटीई एक आइसक्रीम लेकर आया था। टीटीई उसे आइसक्रीम जबरन खाने के लिए उकसाने लगा। इस दौरान टीटीई उसे बदनीयत से छूने करने लगा। छात्रा किसी तरह खुद को छुड़ाकर अपनी सीट पर चली गई। छात्रा ने आशंका जताई है कि टीटीई उसे नशीला पदार्थ मिलाकर आइसक्रीम खिलाना चाहता था। आरोपित टीटीई एनआर सरोज का कहना है कि उसने ऐसा छात्रा के साथ छेड़खानी नहीं की है। मामले में रांची रेल मंडल के सीनियर डोओएम नीरज कुमार ने बताया कि टीटीई को निलंबित कर दिया गया है और वेटर को आइआरसीटीसी ने हटा दिया है। जांच को लेकर कमेटी का गठन किया गया है।

सीबीआइ ने अतीक के करीबी अकाउंटेंट को किया गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सीबीआइ ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी अकाउंटेंट पवन कुमार सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। लखनऊ के रियल इस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने व उससे जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराये जाने के मामले में सीबीआइ उसकी भूमिका की जांच कर रही थी। सूत्रों का कहना है कि मोहित की कंपनियों को हड़पने की साजिश में पवन कुमार सिंह की अहम भूमिका थी। सीबीआइ इस मामले में अतीक अहमद के बेटे उमर की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है।

उल्लेखनीय है कि रियल इस्टेट कारोबारी के साथ देवरिया जेल में हुई घटना के मामले में सीबीआइ लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 12 जून को अतीक अहमद व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआइ ने 28 दिसंबर 2018 को लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल की ओर से कृष्णानगर कोतवाली में अतीक अहमद समेत अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआइआर को अपने केस का आधार बनाया था। सीबीआइ ने 17 जुलाई को अतीक अहमद के प्रयागराज स्थित आवास समेत अन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी।

नहीं रहे रितिक रोशन के नाना और फिल्म निर्माता जे. ओम प्रकाश

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

▸ लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में हुआ निधन

▸ 'आप की कसम' और 'आदमी खिलौना है' जैसी फिल्मों का किया था निर्देशन

बॉलीवुड अभिनेता रितिक रोशन के नाना और प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक जे. ओम प्रकाश का बुधवार को निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे जे. ओम प्रकाश 93 वर्ष के थे। बुधवार सुबह आठ बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के विलेपार्ले स्थित पवन हंस श्मशानगृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राकेश रोशन और रितिक रोशन ने उन्हें मुखाग्नि दी।

निधन की खबर सुनते ही उनके अंतिम दर्शन के लिए सितारों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र के अलावा रितिक की पूर्व पत्नी सुजैन खान भी दोनों बच्चों के साथ पहुंची। जे. ओम प्रकाश के निधन की जानकारी अभिनेता दीपक पराशर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी।

रितिक रोशन ने अपनी फिल्म 'सुपर 30' की रिलीज के दौरान अपने नाना को अपना सुपर टीचर बताया था। उन्होंने लिखा था कि वह अपने नाना को डेडा कहकर बुलाते हैं और उनके नाना ने उन्हें जीवन के हर कदम

जे. ओम प्रकाश। (फाइल फोटो)

पर अपनी कमजोरियों से लड़ना सिखाया है। नाना की सिखाई हुई बात वह अपने बच्चों से भी साझा करते रहे हैं। अपने नाना के 92वें जन्मदिन पर रितिक ने उनके जीवन से जुड़ी एक बात साझा की थी। रितिक ने बताया था कि उनके नाना जब पढ़ाई कर रहे थे, तब अपनी शादी की अंगूठी बेचकर उन्होंने किताबें खरीदी थीं।

रचनात्मकता से प्रभावित होकर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था। बॉलीवुड में जे. ओम प्रकाश के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। 1974 में उन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'आप की कसम' से की थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 'आखिर क्यों?', 'अपनापन', 'आशा', 'आदमी खिलौना है', 'अर्पण', 'आस पास', 'आशिक हूं बहारों का' जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन किया। बतौर निर्माता उन्होंने 'आए दिन बहार के', 'आई मिलन की बेला', 'आंखों आंखों में', 'आया सावन झूम के' और 'आंधी' जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने पंजाबी फिल्म 'आसरा प्यार दा' का भी निर्देशन किया था। सोशल मीडिया पर उन्हें कई सितारों ने श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, 'हमारे निर्माता, निर्देशक आज सुबह गुजर गए। एक दयालु व्यक्ति, मेरे पड़ोसी और रितिक रोशन के नाना। उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि।'

बाल विवाह पीड़िता ने पढ़ना चाहा तो पंचायत ने लगाया जुर्माना

जागरण संवाददाता, जयपुर

▸ राजस्थान का मामला, ससुराल वालों ने पीड़िता को घर से निकाला

राजस्थान के राजसमंद जिले में बाल-विवाह होने के बाद एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया, क्योंकि वह पढ़कर अपना करियर बनाना चाहती थी। इतना ही नहीं उसकी पढ़ने की इच्छा समाज की पंचायत को इतनी नागवार गुजरी कि उसके ससुराल और मायके वालों का समाज से बहिष्कार कर दिया। पीड़िता और ससुराल पक्ष को फिर से समाज में लेने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।

जानकारी के अनुसार राजसमंद के रेलमगरा उपखंड की सुखी अहीर का विवाह करीब 10 साल की उम्र में 2005 में ही हो गया था। वह दिल में पढ़ाई का अरमान दबाकर ससुराल पहुंची। वह आगे पढ़ना चाहती है, इसलिए उसने स्नातक करने के बाद समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की, लेकिन ससुरालवालों ने पढ़ाई बंद करने का यह कहकर दबाव बनाया कि चूल्हा चौका का काम करो। सुसराल वालों के साथ ही समाज के पंचों ने कहा कि तेरा पति तो दसवीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ा तो तू पढ़कर क्या करेगी। सुखी ने आगे पढ़ने की जिद की तो ससुरालवालों ने इसे प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। सुखी के पढ़ने की जिद के चलते उसके मायके पक्ष ने सहमति दे दी। सुखी पढ़ाई में अड़चन पैदा करने वाले ससुराल और पति के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए उसने तलाक की मांग कर दी। मामला पुलिस और कोर्ट में चला गया। इस पर उसके ससुराल पक्ष ने इसके फैसले के लिए समाज के पंचों से दखलंदाजी की मांग की। इसी बीच विवाहिता के पिता गोपीलाल गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। तभी समाज के पंचों ने पंचायत करके उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। उनके परिवार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की मांग की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो समाज की पंचायत के उपाध्यक्ष लक्ष्मण अहीर ने पीड़ित परिवार को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने से इन्कार कर दिया।

ओडिशा में मूसलधार बारिश से बाढ़ के हालात

जेएनएन, भुवनेश्वर

भुवनेश्वर समेत पूरे ओडिशा में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मलकानगिरी जिले से प्रवाहित नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया है। मलकानगिरी के पोटेरु, कांगरूकोंडा ब्रिज पर तीन से पांच फुट ऊपर पानी का बहाव हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग-326 पर यातायात ठप है। इससे आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं जयपुर के बीच का संपर्क कट गया है।

दमकल विभाग एवं ओड्राफ की टीम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राहत एवं बचाव कार्य में उतार दी गई है। स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने को कहा गया है। कालीमेला में भी भारी बारिश के कारण लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट गया है। मौसम विभाग की ओर से मलकानगिरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश एवं नदियों में आई बाढ़ के कारण जिले के सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। लगातार बारिश से रायगढ़ा जिले में बंशधारा नदी खतरे के निशान को पार करने से आसपास के गांव पानी में डूब गए हैं। यहां का गुड़ारी शहर पानी के घेरे में है।

ओडिशा में बुधवार को रायगढ़ और टिटिलागढ़ के बीच अंबोडाला रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। मूसलधार बारिश के कारण ट्रैक की मिट्टी बहने से हादसा हुआ। एएनआइ

छह जिलों में सौ मिमी से अधिक बारिश : राज्य में हो रही लगातार बारिश एवं विभिन्न नदियों के उफान पर होने से मलकानगिरी जिले में प्रायः सभी ब्रिज के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के छह जिलों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। नौ जिलों में 50 से 100 मिमी. बारिश हुई है। वहीं लांजीगड़, काशीपुर, कोटगड़ ब्लाक में 300 मिमी. से अधिक बारिश हुई। अकेले लांजीगड़ ब्लॉक में 382.6 मिमी. बारिश हुई है जबकि काशीपुर में 317.4 मिमी. एवं कोटगड़ में 308 मिमी. बारिश हुई है।

केदारनाथ हाईवे 40 और बदरीनाथ 18 घंटे बाद खुले: देहरादूनः केदारनाथ हाईवे 40 घंटे और बदरीनाथ हाईवे पर 18 घंटे बाद आवागमन के लिए सुचारु हो गए। हालांकि पैदल यात्रा इस जारी रही। राज्य मौसम केंद्र के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दरम्यान स्थिति सामान्य रहने के आसार हैं। प्रदेश में सौ से ज्यादा संपर्क मार्ग बाधित हैं। केदारनाथ जाने वाला गौरीकुंड हाईवे सोमवार शाम करीब पांच बजे बांसवाड़ा में अवरुद्ध हो गया था, जो यहां पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण आवाजाही बंद हो रखी थी।

आडिशा सीमा पर रेल पटरी बही, मालगाड़ी हुई बेपटरी

नईदुनिया, रायपुर : मूसलाधार बारिश से छत्तीसगढ़ व उसके पड़ोसी राज्य ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राज्य के 10 जिलों में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बीजापुर में एक ग्रामीण नदी में बह गया। संबलपुर रेलवे मंडल टिटलागढ़ में रेल पटरी के नीचे की मिट्टी बह जाने से एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। इस रूट पर कई ट्रेनें रद कर दी गई हैं। बारिश से बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन जिलों का पड़ोसी राज्यों तेलंगाना और महाराष्ट्र से संपर्क टूट गया है। यहां स्कूल-कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई हैं। बीजापुर में मंगलवार की शाम चिंतावागु नदी में सोनला बुधारव (24) बह गया।

विशाखापट्टनम रूट की आठ ट्रेनें रद : विशाखापट्टनम से रायपुर और रायपुर से विशाखापट्टनम जाने वाली आठ पैसेंजर ट्रेनें रद कर दी गई हैं। वहीं, विशाखापट्टन-निजामुद्दीन और निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है।

टी-शर्ट और शॉर्ट पहनने पर महिला ने छात्रा से कहा- तुम्हारा तो दुष्कर्म होना चाहिए

जागरण संवाददाता, कोलकाता : कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय से एमफिल करने वाली एक 25 वर्षीय युवती उस समय हैरान रह गई जब एक महिला ने उसे धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारा तो दुष्कर्म होना चाहिए। इतना ही नहीं विरोध करने पर उस महिला ने छात्रा को थप्पड़ भी जड़ दिए। उस युवती की गलती बस इतनी थी कि वह टी-शर्ट और शॉर्ट पहनकर खरीदारी करने निकली थी। इस घटना के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त से मुलाकात की। इसके बाद छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपित की शिनाख्त कर ली है।

मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती उत्तर 24 परगना के बनगांव की रहने वाली है और प्रेसिडेंसी में पढ़ने के दौरान पांच साल तक साल्टलेक इलाके में रही थी। उसने बताया कि जादवपुर विश्वविद्यालय में एमफिल में दाखिला पाने के बाद से ही वह जोधपुर गार्डन इलाके में रह रही है। बीते गुरुवार डेढ़ बजे के दौरान वह अपने पीजी से कुछ दूर स्थित बाजार में खरीददारी को आई थी और वहां पास में स्थित एक बैंक के समीप आरोपित महिला ने उसे रोका और उसके कपड़ों को लेकर बुरा कहने लगी।

आस्था

चमोली की उर्गम घाटी में 13 हजार फीट की ऊंचाई पर है मंदिर, साल के बाकी दिन देवर्षि नारद करते हैं भगवान नारायण की पूजा-अर्चना

वंशीनारायण मंदिर में सिर्फ एक दिन मिलता पूजा का अधिकार

रणजीत सिंह रावत, चमोली

उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड की उर्गम घाटी में खूबसूरत बुग्यालों (मखमली घास के मैदान) के मध्य भगवान नारायण का एक ऐसा मंदिर है, जिसके कपाट साल में सिर्फ एक दिन रक्षाबंधन पर्व पर ही खुलते हैं। इसी दिन सूर्यास्त से पूर्व शाम लगभग चार बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि साल के बाकी 364 दिन यहां देवर्षि नारद भगवान नारायण की पूजा-अर्चना करते हैं। मनुष्यों को सिर्फ एक दिन ही पूजा का अधिकार है। इस बार कपाट श्रावण पूर्णिमा पर 15 अगस्त को खोले जाएंगे।

समुद्रतल से 13 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान वंशीनारायण मंदिर का निर्माण काल छठी से लेकर आठवीं सदी के मध्य का माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव काल में हुआ था। कत्यूरी शैली में बने दस फीट ऊंचे इस मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है, जहां चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु विराजमान हैं। खास बात यह कि इस मूर्ति में भगवान नारायण व भगवान शिव, दोनों के ही दर्शन होते हैं। मंदिर में भगवान गणेश व

चमोली जिले में स्थित भगवान वंशीनारायण मंदिर। जागरण

वन देवियों की मूर्तियां भी मौजूद हैं। मंदिर की राह बेहद दुर्गम है। यहां पहुंचने के लिए बदरीनाथ हाइवे पर हेलंग से उर्गम घाटी तक आठ किमी की दूरी वाहन से तय करनी पड़ती है। इसके बाद शुरू होता है 12 किमी का दुश्वारियों भरा सफर।

वंशीनारायण मंदिर में मनुष्य को सिर्फ एक दिन पूजा का अधिकार दिए जाने की भी रोचक कहानी है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि के आग्रह पर पाताल लोक में उनके द्वारपाल की जिम्मेदारी संभाली। तब बहुत दिनों तक भगवान के दर्शन न हो पाने के कारण माता लक्ष्मी देवर्षि नारद के पास वंशीनारायण धाम पहुंचीं और उनसे भगवान नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने माता को बताया कि भगवान पाताल में राजा बलि के द्वारपाल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पाताल से भगवान को मुक्त कराने की एक ही युक्ति है कि आप श्रावण पूर्णिमा को राजा बलि की कलई पर रक्षासूत्र बांधकर उनसे भगवान को मांग लेना। लेकिन माता लक्ष्मी ने पाताल लोक का रास्ता ज्ञात न होने की बात कही और देवर्षि से भी साथ चलने का आग्रह किया। मान्यता है कि देवर्षि के माता लक्ष्मी के साथ पाताल लोक चले जाने के कारण वह श्रावणी पूर्णिमा को भगवान वंशीनारायण की पूजा नहीं कर पाए। उस दिन कलगोठ गांव के जाख पुजारी ने भगवान वंशीनारायण की पूजा संपन्न की। तभी से यह परंपरा चली आ रही है।

खिलते हैं दुर्लभ फूल : रक्षाबंधन पर्व पर कलकोठ गांव के प्रत्येक परिवार से भगवान नारायण के भोग के लिए मक्खन आता है। इसी मक्खन से वहां प्रसाद तैयार होता है। भगवान वंशीनारायण की फुलवारी में कई दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं। इन्हीं से श्रावण पूर्णिमा पर भगवान का श्रृंगार होता है। इसके बाद श्रद्धालु व स्थानीय ग्रामीण भगवान वंशीनारायण को रक्षासूत्र बांधते हैं।

रिख उड्यार में करते हैं रात्रि विश्राम : मंदिर में ठाकुर जाति के पुजारी होते हैं। वर्तमान में कलगोठ गांव के जाख पुजारी के पास यह जिम्मेदारी है। मंदिर के पास ही रिख उड्यार (भालू गुफा) है। यहां श्रद्धालु भोजन बनाने के साथ ही रात्रि विश्राम भी करते हैं।

यमुना एक्सप्रेस वे पर 214 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी मर्सिडीज

जागरण संवाददाता, आगरा

▸ एक्सप्रेस वे पर अब तक की सबसे अधिक ओवरस्पीड, दो हजार रुपये का किया गया ई-चालान

सोमवार आधी रात के बाद मर्सिडीज कार ने यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार के रिकार्ड तोड़ दिए। नोएडा से आगरा जाते समय इस कार ने 214 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरा। एक्सप्रेस वे पर लगे स्पीड कैमरे में कार के ट्रेस होते ही संबंधित डाटा कार्रवाई के लिए आरटीओ को भेजा गया है। जुर्माने के साथ ही चालक का लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है।

यमुना एक्सप्रेस पर कार के लिए 100 और भारी वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा की गति सीमा निर्धारित है। गति सीमा तोड़ने वाले वाहनों की पहचान के लिए एक्सप्रेस वे पर जगह-जगह स्पीड कैमरे लगे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे के कॉरीडोर कंट्रोल इंचार्ज मेजर (रिटा.) मनीष सिंह ने मंगलवार को सुबह कंट्रोल रूम में जब डाटा देखा तो चौंक गए। सोमवार रात 2.40 बजे नोएडा से आगरा की ओर जा रही मर्सिडीज कार 214 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक्सप्रेस वे के 108 किमी पर लगे स्पीड कैमरे के पास से गुजरी थी। सोमवार को 120 वाहनों ने अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन किया था। इनमें से अधिकतर की रफ्तार 160-165 किमी प्रति घंटा थी। उन्होंने कार्रवाई के लिए इस कार का डाटा आरटीओ आगरा को मेल कर दिया है। आरटीओ प्रवर्तन अनिल कुमार ने बताया कि ये कार एआरएस स्टील एंड एलॉय पांडिचेरी के नाम से रजिस्टर्ड है। गाड़ी का ओवर स्पीडिंग में दो हजार रुपये का ई-चालान किया गया है। चालक के बारे में जानकारी की जा रही है। उसके लाइसेंस के निलंबन के लिए नोटिस बाद दी जाएगी।

अब तक 202 किमी प्रति घंटा थी सबसे ज्यादा रफ्तार: यमुना एक्सप्रेस वे पर अब तक सबसे अधिक 202 किमी प्रति घंटे की रफ्तार आंकी गई थी। पिछले वर्ष एक बीएमडब्ल्यू कार हेडलाइट बंद कर नोएडा से आगरा की ओर रात में 202 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी थी।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 अगस्त 2019

दैनिक जागरण
स्मृतियां अक्षुण्ण रहना ही अमरता है

बौखलाया पाकिस्तान

अनुच्छेद 370 को बेअसर करके जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भारत सरकार की ऐतिहासिक पहल पर पाकिस्तान जिस तरह भड़का हुआ था उसे देखते हुए यह तय था कि वह कुछ न कुछ करेगा। तमाम गर्जन-तर्जन के बाद उसने जिस तरह भारत से राजनयिक संबंधों का दर्जा कम करने और व्यापारिक संबंध तोड़ने का फैसला किया उससे भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं। आखिर यह भारत ही था जिसने पुलवामा हमले के बाद व्यापार के मामले में पाकिस्तान का सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा खत्म किया था। इसके बाद पाकिस्तान से होने वाले सीमा व्यापार को भी निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उसके जरिये मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। चूंकि भारत के इन कदमों के बाद द्विपक्षीय व्यापार न के बराबर रह गया था इसलिए उसे खत्म करने की पाकिस्तान की घोषणा का कोई मतलब नहीं। जहां तक राजनयिक स्तर घटाने की बात है तो सच्चाई यह है कि सुरक्षा मामलों के भारतीय विशेषज्ञ एक अर्से से यह मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान से राजनयिक संबंध घटाए जाने चाहिए। एक तरह से पाकिस्तान ने वह काम किया जिसके लिए भारत सरकार से अपील की जाती थी।

ऐसा लगता है कि बौखलाहट में आए पाकिस्तान को कुछ सूझा नहीं और इसीलिए उसने ऐसे फैसले ले लिए जो उस पर ही भारी पड़ सकते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत को दबाव में लेने के इरादे से भारतीय यात्री विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र लंबे समय तक बंद रखा और जब भारत सरकार इस पाबंदी से बेपरवाह रही तो उसने मजबूरी में अपने फैसले को पलटा। पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के साथ ही कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने की भी बात कर रहा है। वह जिस तरह द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने को स्वतंत्र है उसी तरह सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाने के लिए भी। वह शायद इस हकीकत से आंखें मूंदे रहना चाहता है कि कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव अब महज कागज का एक टुकड़ा भर रह गया है। उसे यह भी समझ आना चाहिए कि इस प्रस्ताव को निष्प्राण करने मे सबसे बड़ी भूमिका उसी की रही है। पाकिस्तान ने न केवल कश्मीर का एक हिस्सा चीन को सौंप दिया, बल्कि इस जरूरी शर्त को भी पूरा करने से इन्कार किया कि जनमत संग्रह के लिए पहले उसे अपने कब्जे वाले इलाके से अपनी फौज हटानी होगी। पाकिस्तान के नीति-नियंता कुछ भी कहें, सच यही है कि उनके बौखलाहट भरे फैसलों से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।

तंबाकू के दुष्परिणाम

शराब लोगों के स्वास्थ्य को लीलने के साथ ही उनके परिवार को मानसिक पीड़ा देती है। दो साल पहले शराब का निर्माण और इसके सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगने के बाद बिहार को इस सामाजिक बुराई से लगभग निजात मिल चुकी है। शराबमुक्त बिहार के लिए राज्य सरकार के कड़े कानून को लागू कराने का जिम्मा बिहार पुलिस के कंधे पर ही है। अब उसे तंबाकू के खिलाफ भी सघन अभियान चलाने की जिम्मेदारी निभानी है। तंबाकू का सेवन शराब से ज्यादा परेशानी देता है। दरअसल इसका सेवन हर उम्र के लोग करते हैं। स्कूली बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कोर्ट में समय-समय पर प्रशासन-पुलिस और सरकार को फटकार भी मिलती है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। तंबाकू से दमा, खांसी, टीबी आदि रोगों का होना आम है, अब यह लोगों को मुंह का कैंसर भी दे रही है। इसके सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर को देखते हुए केंद्र के कानून कोटपा के तहत नियंत्रण के अलावा राज्य सरकार ने गुटखा पर प्रतिबंध तक लगा रखा है, परंतु इसकी बिक्री रोकने के लिए जिम्मेदार महकमा कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। नतीजतन चौक-चौराहों, मोहल्ले, स्टेशनों और बस स्टैंड के अलावा शिक्षा संस्थानों के निकट इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। बहरहाल एक कहावत है कि जब जागो, तब सवेरा, बिहार पुलिस भी निद्रा त्यागकर तंबाकू के खिलाफ सघन अभियान चलाने को सजग हुई है। एडीजी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि स्कूलों के सौ गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न हो। अभियान को गति के लिए हर जिले में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। बैठक में पुलिसजनों को तंबाकू नियंत्रण के गुर भी सिखाए गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अपराध अनुसंधान विभाग, राज्य सरकार और सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सोसाइटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में हुई बैठक के सकारात्मक नतीजे जरूर सामने आएंगे। तंबाकू उद्योग का सबसे सॉफ्ट टारगेट बच्चे और युवा होते हैं। ये देश का भविष्य हैं। इन्हें बचाना आवश्यक है। लिहाजा नियंत्रण के लिए बने कानून कोटपा को सख्ती से लागू कराने की दिशा में पुलिस को हर जोग-जतन करना चाहिए जिससे देश में एक और बुराई को रोकने में बिहार अगुआ साबित हो।

कश्मीर में शांति और सुरक्षा की चुनौती

राजीव मिश्रा

भारत सरकार को घाटी के विकास की चिंता करने के साथ ही वहां के लोगों को भरोसा दिलाने की भी पहल करनी होगी

जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ए से आजादी मिल गई, लेकिन दशकों की हिंसा ने प्रदेश में एक खाली स्थान पैदा किया है। इस खाली स्थान पर अलगाववादियों और पाकिस्तानपरस्त तत्वों ने कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने यह कोशिश इसीलिए की, क्योंकि मुख्यधारा के राजनीतिक दल रह-रह कर उनकी ही भाषा बोलते रहे। स्पष्ट है कि इस खाली जगह को भरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। इस क्रम में वहां एक ऐसा राजनीतिक विकल्प भी पैदा करना होगा जो अलगाववादियों से प्रेरित न हो और न ही उनके दबाव में आए। इसी तरह सुशासन और शांति स्थापित करने के साथ-साथ भारत सरकार को वहां के युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन करने के अलावा स्थानीय लोगों के बीच सद्भावना का माहौल बनाने की दरकार होगी। इसके साथ ही राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना और निजी क्षेत्र में भारतीय उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और इसके लिए सब्सिडी के नए प्रावधान को विकसित करने की आवश्यकता होगी। भारत सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मामले में जिस तरह गंभीर और संवेदनशील नजर आ रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले पांच वर्षों में कश्मीर में शांति और सुरक्षा से जुड़े मामले सुलझा लिए जाएंगे और संपूर्ण क्षेत्र विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा, लेकिन यह काम आसानी से तब होगा जब कश्मीर के लोगों को यह भरोसा दिलाने में सफलता मिलेगी कि जो कदम उठाए गए हैं वे उनकी भलाई के लिए हैं। इस मामले में शेष देश के लोगों को भी सतर्क और संवेदनशील रहना होगा। कश्मीरियों को यह संदेश देने की जरूरत है कि उनकी पहचान अनुच्छेद 370 और 35-ए से नहीं थी और न हो सकती है। उनकी पहचान तो उस कश्मीरियत से है जो भारतीयता का हिस्सा है। कश्मीरियों को यह संदेश देने की भी जरूरत है कि पाकिस्तान उनकी बर्बादी की जड़ है। यह संदेश देने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन इसे आसान बनाना ही होगा। यह अच्छा हुआ कि गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा के साथ यह भी आश्वासन दिया कि हालात सुधरने पर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा।

अनुच्छेद 370 और 35-ए को खत्म करने से पहले घरेलू स्तर पर जितनी तैयारी की जरूरत थी उतनी ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का रुख अनुकूल रहे। भारत के राजनयिक समय रहते दुनिया के प्रमुख देशों के राजदूतों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय हो गए थे। अब यह साफ है कि वे अनुच्छेद 370 और 35-ए के उन्मूलन के कारणों एवं परिस्थितियों पर विश्व समुदाय को सकारात्मक संदेश देने में सफल रहे। माना जाता है कि मोदी ने दोबारा सत्ता में आने के साथ ही कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी थी और अपने संभावित कदम को लेकर वैश्विक समुदाय को टटोलना भी शुरू कर दिया था। शायद इसी कवायद के चलते विश्व समुदाय की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक नजर आईं।

अवधेश राजपूत

यह और अधिक उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने कश्मीर में परिवर्तन के भारत के कदम को उसका आतंरिक मामला करार दिया। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की बात कर भारत को चिंतित और पाक का मनोबल बढ़ाने का काम किया था। कश्मीर पर अमेरिकी की प्रतिक्रिया पाक के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। अमेरिका के अलावा संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिक्रिया भी भारत का मनोबल बढ़ाने वाली है। इसमें संदेह है कि पाक को संयुक्त राष्ट्र में शोर मचाने से कुछ हासिल होगा, क्योंकि कश्मीर संबंधी उसका प्रस्ताव न जाने कब निष्प्रभावी हो गया था।

पाकिस्तान कुछ भी कहे, सच यही है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। वैसे इस मामले पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह सर्वविदित थी, लेकिन उसके संभावित कदमों को लेकर सतर्क रहना होगा। वह बौखलाहट में आकर ऐसा कोई कदम उठा सकता है जो सीमा पर तनाव बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यह सही है कि अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं की वापसी के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान की समस्या यह है कि अमेरिकी सेना की वापसी की शर्तें पहले ही इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तय हो चुकी हैं। यदि पाकिस्तान को यह लगता है कि वह अमेरिका के साथ कश्मीर बनाम अफगानिस्तान कार्ड खेल सकता है तो शायद वह भ्रम में है। उसे यह समझ आना चाहिए कि अफगानिस्तान से निकलने की चाहत के बाद भी अमेरिका भारत के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। आमतौर पर विदेश नीति के मामले में पश्चिमी देशों का रुख अमेरिकी सोच से प्रेरित रहता है, लेकिन कुछ मामलों में वे अलग स्वर में भी बोलते हैं। कश्मीर के मामले में पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी, इसका अंदाजा उस तब लग गया था जब बीते दिनों भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आधार पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इजरायल ने कश्मीर में पर्यटन कर रहे अपने नागरिकों को कश्मीर से निकल जाने की अपील की थी। शायद ये देश इससे अवगत थे कि कश्मीर में क्या होने वाला है। हालांकि ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के सांसदों की ओर से कुछ शोर-शराबा किया गया है, लेकिन यह आधिकारिक ब्रिटिश प्रतिक्रिया नहीं है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं लगती। बावजूद इसके भारत को इस पर नजर रखनी चाहिए कि रूस और चीन क्या रुख जाहिर करते हैं। माना जा रहा है कि यूरोपीय संघ के तेवर तीखे नहीं होंगे, क्योंकि भारत के साथ यूरोपीय संघ के देशों के द्विपक्षीय व्यापार हित हैं और मौजूदा माहौल में विदेश नीति में व्यापार की भूमिका बढ़ गई है।

भारत और रूस के बीच हाल में हथियारों के बड़े सौदे हुए हैं और द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है। इसलिए संभावना बहुत कम है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत की कश्मीर नीति पर कोई सख्त रुख दिखाएंगे। चीन ने जरूर विरोध किया है, लेकिन इस विरोध को प्रतीकात्मक विरोध ही माना जाना चाहिए। चीन का विरोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा महत्व भी नहीं रखता, क्योंकि दुनिया जानती है कि वह सदैव पाकिस्तान की पैरवी करता रहता है। इसके अलावा आतंकवाद और मानवाधिकारों के मामलों में उसका रिकार्ड अच्छा नहीं रहा है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चा सध जाने के बाद सरकार के लिए यही आवश्यक है कि वह कश्मीर की सुरक्षा और वहां के विकास की चुनौतियों से पार पाने में जुटे। इसकी उम्मीद की जा सकती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में इस चुनौती का सामना सफलता से किया जाएगा।

(स्तंभकार 'आर्टिकल 370-बून ऑर बेन' के लेखक हैं)

response@jagran.com

आकाशगंगा सी सुषमा स्वराज

तरुण विजय

सुषमा स्वराज भद्रता का प्रतिरूप थीं और इसीलिए उन्हें अटल जी के समान अजातशत्रु कहा-माना गया

जिसने भी सुना, यकीन नहीं कर पाया। बार-बार सोचता और शायद यही मनाता कि खबर झूठी हो, लेकिन नियति को कुछ और स्वीकार था। सुषमा स्वराज का अचानक जाना भरी दुपहरी में अंधेरे का अहसास क्यों करा गया? कारण है सिर्फ उनका स्वभाव, उनकी विद्या और वाणी का सारस्वत प्रभाव, उनकी निरहंकारिता। मुझे गत तीस वर्षों से उन्हें जानने, उनके साथ काम करने, उनका स्नेह पाने का सौभाग्य मिला था। पांचजन्य के प्रत्येक समारोह में सुषमा जी के घर की सरस्वती प्रतिमा का आना अनिवार्य था और उस सरस्वती प्रतिमा को वह आग्रह करके फिर वापस अपनी बैठक में ले भी आती थीं। लद्दाख में 1996-97 में जब मैंने सिंधु उत्सव और दर्शन योजना शुरू की तो उन्होंने दूरदर्शन को कहकर उस पर दस कड़ियों वाली सिंधु गाथा का वृत्तचित्र बनवाया। वह सबके लिए समान चिंता करती थीं। 15 वर्ष पूर्व वह बीमार हुईं। बहुत कष्ट था। कुछ मन में उदासी भी थी। मैं मिलने गया तो बोलीं, 'तरुण जी कुछ नहीं कृष्णेच्छा है- कृष्ण जी जैसा चाहें।' कुछ सप्ताह बाद ठीक हो गईं। फिर एक अंतराल के बाद केंद्रीय मंत्री बनीं। उसी संयम, शालीनता से बोलीं, तरुण जी कृष्ण कृपा है। जैसा कृष्ण जी चाहें।

वह किसी का दुख नहीं देख सकती थीं, किसी को आहत नहीं कर सकती थीं। कभी किसी के लिए उनसे कटुवचन, अभद्र, अशालीन, आक्रामक शब्द प्रयोग न लिखे गए, न सुने गए। अभी कुछ दिन पहले, देश में धर्म जागरण की अलख जगाने वाले संत समान मांगेराम जी गर्ग को श्रद्धांजलि देने वाले उनके ट्वीट पर किसी ने एक घृणित ट्वीट भेजा-उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा का। उसका भी सुषमा जी ने इतना शालीन, भद्र उत्तर दिया कि सब तरफ उसकी चर्चा हो गई। भद्रता बहुत दुर्लभ गुण है। बड़ी होना आसान होगा, पर भद्र होना कठिन है। सुषमा स्वराज भद्रता का प्रतिरूप थीं और इसीलिए उन्हें अटल जी के समान अजातशत्रु कहा-माना गया।

आपातकाल में उन्होंने संघर्ष किया। जेपी आंदोलन में वह सबसे कम आयु की युवा नेता थीं। राष्ट्र सेविका समिति की सेविका के नाते शिविरों में जाना, समिति की अधिकारियों- शांता अक्का, प्रमिला ताई के साथ सतत संपर्क, प्रखर हिंदू धर्म की ध्वजवाहिका, हर तीज त्योहार को राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाना। यह सब साधारण कार्यकर्ताओं, संघ-भाजपा से कभी न जुड़े नागरिकों के मन पर गहरे असर करते थे। करवा चौथ पर उनके यहां जो समागम और व्रत निभाने का उत्सव होता था वह भारतीय

परंपरा का शानदार समारोह माना जाता था। रक्षाबंधन पर एक बार मेरी बहन की राखी समय पर नहीं पहुंची। सुषमा जी को पता चला, तुरंत फोन किया-मैं हूं न, मैं बांधूंगी राखी। मैं जीवन में उनके ये शब्द कभी भूल नहीं पाऊंगा। विदेश मंत्रालय का कार्यक्रम हो या व्यक्तिगत समारोह वह स्वयं बिना चूके, अपने अतिथियों को फोन करती थीं। आना है-भूलना मत। भला कौन ऐसा होगा जो इस फोन के बाद भी अनुपस्थित रहे। हर काम को मनोयोग से करना। किसी भी काम में किंचित मात्र भी भूल, लापरवाही, दूसरों पर निर्भरता उन्होंने सीखा ही नहीं था।

दुनिया में विदेश मंत्रालय, दूतावास अक्सर भारतीयों के प्रति रूखे, संवेदनहीन प्रकट होते थे। सुषमा जी ने विश्वव्यापी भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय को स्वदेश मंत्रालय में बदल दिया। कोई भी भारतीय, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कुछ भी तकलीफ हो, वह किसी भी समय सुषमा जी को ट्वीट कर सकता था और उसका उत्तर भी मिलता-समाधान सहित। यह उत्तर पाकर अफ्रीका, रूस, यूरोप, अरब, खाड़ी के देश, पाकिस्तान में बैठे भारतीयों की आंखों में आंसू आ जाते। सुषमा बहन, सुषमा दीदी। सुषमा मां.. कैसे-कैसे आभारी कृतज्ञ भारतीय उन्हें दुआएं देते। ईसाई पादरी, मुस्लिम बहनें, बच्चियां, पाकिस्तान की गीता, जर्मनी में सरदारजी, अमेरिका गई नई-नवेली बहू... अनंत कथा हैं सुषमा जी के विश्वव्यापी विदेश मंत्रालय की। कोई किसी भी पार्टी में हो, किसी भी जमात, मजहब, संप्रदाय वाला हो, वह सुषमा जी से बात करना, कुछ कहना बहुत आसान और सहज मानता था, मानों वह सुषमा जी से चिरपरिचित हो। बेंजामिन नेतन्याहू, पुतिन, शी चिनफिंग, ओबामा, अरब देशों के शेख-सभी ने सुषमा स्वराज के शिखर को झुककर नमन किया और यह सुषमा जी का व्यक्तित्व था कि इन वैश्विक दिग्गज नेताओं के व्यवहार में सुषमा जी के समक्ष आते ही अद्भुत विनय और आदर का भाव प्रकट होता था। सूचना प्रसारण, स्वास्थ्य और विदेश जैसे तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते हुए हर जगह अपनी खास छाप, मेधा और रीति के चिन्ह छोड़े।

25 वर्ष की आयु में मंत्री पद पाईं सुषमा जी 67 वर्ष की आयु तक यानी 42 वर्ष भारतीय राजनीति में अद्भुत गरिमा के साथ देदीप्यमान नक्षत्र जैसी रहीं। वह वस्तुतः ऐसी आकाशगंगा थीं, जो बहुत ऊंचाई से भी सामान्यजन को शीतल, सुखद आत्मीयता का अहसास कराती थीं। उनकी गाथा सार्वजनिक जीवन जी रहे सभी लोगों के लिए एक बड़ा संदेश देती है। ऊंचाई कितनी भी पाओ, पर ध्यान रहे कि तुम्हारे साथ की छाया कभी लुप्त न हो। वाणी की मधुरता को निभाकर सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति की सरस्वती पुत्री बन गईं। उनकी कोई तुलना नहीं, कोई विरोधी नहीं, निर्वैर निर्भीक, दृढ़। भाषा पर उनका अद्भुत अधिकार था। जब कर्नाटक गईं तो आनन-फानन कन्नड़ सीखी। गुजरात में गुजराती। तमिल में ऐसी तमिल कि लोग चकित रह गए। मुझसे अक्सर कहतीं कि तुम तमिलनाडु में काम कर रहे हो, मुझे कुछ बताया करो, तमिल संस्कृति बहुत विराट, महान है। पूर्वी एशिया पर उनका विशेष ध्यान था। लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पालिसी में बदलना उनका ही योगदान था। देश विदेश, सर्व पंथ समभाव, पर हिंदुत्व का गहरा अभिमान, महिला जागृति, परंपराओं की लीक, भाषाई समृद्धि, भारत शत्रु के लिए रणचंडी, हर भारतीय के लिए मां का प्रतिरूप ऐसी सुषमा अब कहां?

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अंतर्द्वंद्व

आज यदि हम अपने चारों ओर नजर घुमाएं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पास या दूर का संसार केवल और केवल किसी द्वंद्व में उलझा हुआ सा है। इस विचार से मन भारी हो जाता है कि मानव की इतनी प्रगति के बावजूद समाज में विरोधाभास, असहमति, क्लेश बस यही सब जैसे हाथ लग पाया है। समाज की इकाई होने के नाते जब बात स्वयं पर आती है तो हम पाते हैं कि हमारे खुद के भीतर अथाह अंतर्द्वंद्व व्याप्त है। और यही अंतर्द्वंद्व धीरे-धीरे हमारे चारों ओर के वातावरण को भी लपेट लेता है। हम अपने को वास्तव में दिन रात छोटे-बड़े, उचित-अनुचित सवालों से घिरा पाते हैं। हमारा प्रत्येक निर्णय जो किसी दंड से कम नहीं, निरंतर एक अंतर्द्वंद्व से गुजरता है।

चूंकि ये ऊहापोह हमारे ही भीतर का है, ऐसे में निर्णय कुछ भी हो, हार या जीत स्वयं की ही होती है। हम किसी कठोर निर्णय पर पहुंच भी जाएं तो भी अंतर्द्वंद्व की पैठ इतनी गहरी होती है कि हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं, वह हमें उतना ही पीछे घसीटती जाती है। छोटे-छोटे आंतरिक संघर्षों में घिरे रहना एक प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति को जन्म देता है। यही अंतर्द्वंद्व हमारे जीवन के बड़े एवं महत्वपूर्ण फैसलों पर हावी होने लगता है। यह अनिश्चतता की स्थिति हमारे व्यक्तित्व को अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है।

यह द्वंद्वात्मक रवैया आजकल बच्चों एवं युवाओं में भी खूब देखने को मिलता है। हर ओर एक विमूढ़, व्याकुल-सी पीढ़ी पनपती जा रही है। हम अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि उनके व्याकुल मन में निर्णय-क्षमता को सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास करते रहें। इसके लिए हमें स्वयं को कठोरता से परखना होगा, क्योंकि अंतर्द्वंद्व किसी गृह युद्ध से कम नहीं, जिसमें क्षति केवल अपनी ही होती है। अंतर्द्वंद्व की चपेट में आए लोगों का दूसरे भी लाभ उठाने का प्रतिकूल प्रयास करते रहते हैं। अच्छा हो, हम अपने अंदर के अंतर्द्वंद्व को पहचानें और यथोचित समय से ही उससे बाहर निकलने का प्रयास करें।

छाया श्रीवास्तव

सड़कों पर पशु-धन

डॉ. महेश परिमल

जो व्यक्ति मूक और हमारे लिए पूज्य पशुओं को सड़कों पर पसरने के लिए विवश करता है उसे भी अपराधी माना जाए

इन दिनों शायद ही ऐसा कोई शहर होगा, जो सड़कों के बीचों-बीच बेसहारा पशुओं से त्रस्त न हो, पर इस समस्या पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जिसे हम पूजते हैं, वही आज सड़कों पर लावारिस हालत में है। उनकी इस स्थिति के लिए आखिर दोषी कौन है? गाय को विशेष पशु का दर्जा दिया जाए, इसके लिए गुजरात में आंदोलन चला था। उसमें एक की मौत हुई थी, कई घायल हुए थे, पर जब यही गौमाता सड़कों पर होती है तो कोई आंदोलन नहीं होता। सड़कों पर पसरे पशुओं के कारण होने वाली मौतों की हम कैसे अनदेखी कर सकते हैं? क्या पशुओं का दोहन करके उन्हें बेसहारा या लावारिस छोड़ने वाला पशु-मालिक अपराधी नहीं है? उसे भी अपराधी मानना ही होगा जो मूक, निरीह और हमारे लिए पूज्य पशुओं को सड़कों पर पसरने के लिए विवश करता है। ये वे पशु हैं, जो यातायात के तमाम नियमों की रोज धज्जियां उड़ाते हैं। वे नगरपालिका, नगर-निगमों को चुनौती देते हैं।

क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कांजी हाऊस में पशुओं को एक या दो सप्ताह तक रखा जाए और इसी बीच यदि पशु-पालक आ जाए तो उसे भारी जुर्माने और हिदायतों के बाद पशु सौंपा जाए। शेष पशुओं को शासन हस्तगत कर ले, उनके पालने की अलग व्यवस्था की जाए। उनके गोबर से खाद, गैस और बिजली के छोटे-छोटे प्लांट तैयार किए जाएं। गो-मूत्र को दवाओं के लिए भेजा जाए और दूध को बेचकर लाभ कमाया जाए। इस दिशा में एक ईमानदार सोच को सकारात्मक रूप से लागू किया जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं कि कई लोगों को रोजगार मिलेगा। खाद एवं खाना पकाने की गैस भी उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरी ओर सड़कों पर बेसहारा पशुओं का जमावड़ा खत्म होगा। सड़कों का ही नहीं, जिंदगी का रास्ता भी आसान होगा।

कुछ भी करें, पर पशु-मालिक को केंद्र में अवश्य रखें। एक व्यक्ति या परिवार यदि उसके पशु से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसका पूरा मुआवजा पशु-मालिक से वसूला जाए, ताकि दूसरों को सबक मिले। पशुओं की पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन हम बेसहारा पशुओं के मालिकों की पूजा नहीं कर सकते। वे अपराधी हैं। नगर-पालिका, नगर-निगमों में बेसहारा पशु-मालिकों के खिलाफ कानून बनाए जाएं तो बेहतर होगा। शासन को भी इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। इन पशुओं से वोट नहीं मिलने वाला, क्या इसीलिए इन्हें बेसहारा घूमने दिया जाए, लोगों की भले ही जान जाती रहे। वैसे भी शहरों की कई सड़कें ऐसी हैं, जिन्हें सड़क कहने में शर्म आती है। उबड़-खाबड़ सड़कों, रोज की आपाधापी, बढ़ता प्रदूषण, उखड़ती सांसों के बीच यदि हमारे बलगम का रंग काला हो जाए तो आश्चर्य नहीं। उस पर रास्तों पर पसरे बेसहारा पशु हमें परेशानी में डाल रहे हैं, हमें भी बेसहारा कर रहे हैं। आप बेसहारा पशु को रास्ते से किनारे कर दें, पर पशु-मालिक पर बिल्कुल रहम न करें। वह अपराधी है, उसे पुलिस के हवाले करें, तभी हम एक अच्छे शहर की बुनियाद रख सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

पटेल को बलि का बकरा न बनाइए

अनुच्छेद 370 को सरदार पटेल से जोड़कर पेश करने की कांग्रेसी मानसिकता निंदनीय है। 'नेहरू की जिद से जुड़ा था अनुच्छेद 370' शीर्षक से प्रकाशित शेरू थपलियाल का लेख स्थिति को स्पष्ट करता है। साफ समझ आता है कि इस हानिकारक अनुच्छेद के दृष्टा एवं सृष्टा नेहरू ही थे। उन्होंने ही शेख अब्दुल्ला को आश्वस्त किया था कि उसकी इच्छा के अनुरूप ऐसा प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने ही गोपालस्वामी आयंगार से इसकी ड्राफ्टिंग करवाई थी, किंतु बड़ी चालाकी दिखाते हुए वह स्वयं विदेश यात्रा पर चले गए और सरदार पटेल को अपने पीछे इसे संविधान सभा से पारित कराने की जिम्मेदारी सौंप गए। उन्हें पता था कि पटेल के कारण यह आसानी से पास हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। आयंगार द्वारा सभा पटल पर रखे जाते ही ज्यों ही बाबा साहब के मित्र हसरत मोहानी ने इसका विरोध शुरू किया, स्थिति को संभालने के लिए सरदार पटेल ने खड़े होकर कहा कि यह एक अस्थायी तथा संक्रमणकालीन व्यवस्था है। कश्मीर में युद्ध के हालात समाप्त होने के साथ ही यह भी खत्म हो जाएगा। उनके इस आश्वासन के बाद ही हसरत मोहानी ने अपना विरोध वापस ले लिया और 306ए पारित हो गया। बाद में यही 370 कहलाया। अब सोचने की बात यह है कि सरकार की ओर से इसकी शीघ्र समाप्ति का आश्वासन देने के बावजूद क्यों उस वचन का पालन नहीं किया गया? क्यों 70 साल इसे बनाए रखा गया? इस असत्यवादिता का दोष सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर है। आज जब सरदार पटेल के आश्वासन को भाजपा पूरा कर रही है, तब भी कांग्रेस विरोध कर रही है। थपलियाल ने सरदार पटेल के सचिव वी. शंकर की पुस्तक से कई प्रमाण देकर सरदार पटेल के 370-विरोधी चिंतन के सुबूत पेश किए हैं।

मेलबाक्स

उनकी बेटी मनुबेन की डायरी भी प्रकाशित हो चुकी है और उसमें भी अन्य कई पुष्टिकारक प्रमाण मिलते हैं।

अजय मित्तल, मेरठ

उचित नहीं विपक्ष का विरोध

देश के इतिहास में ऐसा देखने को मिला जिसकी कल्पना भी नहीं कि गई थी। आज भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड हिंदुस्तान बन गया है। अब एक संविधान, एक निशान (ध्वज) और एक हिंदुस्तान से पूरे भारत देश में अपार खुशी की लहर दौड़ रही है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के बड़े-बड़े नेताओं को भी यह निर्णय और कार्य पसंद आया है। ऐसे में अब भी कुछ नेताओं का महज दिखावे के लिए विरोध करना उचित नहीं है। जिस विधेयक का विरोध किया जा रहा था उसके पक्ष में 370 मत पड़े और विपक्ष में मात्र 70 मत। इससे भी क्या उनको इसकी जरूरत और महत्व को नहीं समझना चाहिए? यदि पूर्वजों से कोई गलती हुई तो क्या बच्चों को उसे सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए था? नेताओं का आपसी द्वंद्व अवश्य हो सकता है, परंतु जहां देश की एकता और अखंडता की बात आए सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना जरूरी होता है। जनता अपनी तथा देश की रक्षा के लिए इन नेताओं को चुनकर सबसे बड़ी पंचायत में भेजती है। भारत सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। हमारे संविधान ने हम सब को समान अधिकार दिए हैं। फिर कश्मीर में भी इसी संविधान की आवश्यकता थी। अब वहां सही मायने में चहुंमुखी विकास संभव है। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग था और भविष्य में भी रहेगा। अब विरोधियों को भी धीरे-धीरे अनुच्छेद 370 हटाने की जरूरत को समझ लेना चाहिए। अखंड भारत की पहचान दुनिया में मिशाल बने इसके लिए हम सब को मिलकर काम करने की जरूरत है।

आचार्य राम कुमार बघेल शास्त्री, पलवल

सावधान रहना होगा

अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। वह कश्मीर को हिंसा की आग में झुलसाने के लिए जी जान से जुट गया होगा। हमें पूरी तरह सावधान रहना होगा। बेहतर यही होगा कि अलगाववादी किसी भी नेता को अभी कश्मीर में रिहा न किया जाए। कश्मीर में अमन और चैन की बहाली के लिए यह बेहद जरूरी है। यदि कोई आंदोलन करता है, हिंसा की कोशिश करता है या जन भावना को भड़काने की कोशिश करता है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाने की जरूरत है। दरअसल यह ताजा जख्म हैं जिसे भरने में समय लगेगा। जो कभी कश्मीर के बादशाह कहलाते थे आज वे अर्श से फर्श पर आ गिरे हैं।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

502 मेडिकल कॉलेज हैं देश भर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वर्ष 2018-19 के आकड़ों के मुताबिक। हालांकि भारत में कम से कम 1,200 मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है।

आजकल

राहुल लाल
स्वतंत्र टिप्पणीकार

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम एनएमसी

देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सभी लोगों तक समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। साथ ही मौजूदा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संगठन में डॉक्टरों के एकाधिकार को कम करने के मकसद से केंद्र सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019 पारित किया है। हालांकि देश भर में चिकित्सक लगातार इस बिल का व्यापक विरोध कर रहे हैं, और इस संबंध में उनके अपने तर्क भी हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार भी सभी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए तात्कालिक उपाय के तौर पर इसे लागू करने को तत्पर है। सरकार के भी अपने तर्क हैं और इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है

देश भर के डॉक्टरों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच नेशनल मेडिकल कमीशन बिल-2019 अर्थात एनएमसी बिल राज्यसभा से भी दो संशोधनों के साथ पारित हो गया। केंद्र सरकार के अनुसार यह बिल भारत में चिकित्सा शिक्षा में सबसे बड़े सुधार के उद्देश्य से लाया गया है। इसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में राष्ट्रव्यापी विरोध जारी है। अब प्रश्न उठता है कि एनएमसी बिल-2019 आखिर क्या है कि केंद्र सरकार इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए जादुई छड़ी मान रही है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर व्यापक पैमाने पर इसका विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह बिल मेडिकल क्षेत्र के लिए उचित नहीं है और इससे कई तरह की चुनौतियां सामने आएंगी।

एमसीआइ और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बदले एनएमसी : नेशनल मेडिकल कमीशन बिल-2019 के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने वाली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया जाएगा। एमसीआइ का गठन भारतीय मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंतर्गत हुआ था। एनएमसी बिल को 16वीं लोकसभा में पहली बार पेश किया गया था। कुछ प्रावधानों पर विपक्ष और डॉक्टरों के विरोध के बाद इसे संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था। 29 जुलाई को लोकसभा और एक अगस्त को राज्यसभा ने इसे कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया। इस तरह इस बिल के अनुसार अब देश में मेडिकल शिक्षा और मेडिकल सेवाओं से संबंधित सभी नीतियां बनाने की कमान इस कमीशन के हाथ में होगी।

एनएमसी क्यों : वर्ष 1934 से एमसीआइ (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) देश में मेडिकल क्षेत्र में काम कर रही थी। हाल तक यह 1956 के कानून द्वारा मेडिकल क्षेत्र में रेगुलेटरी अथॉरिटी थी। इसका आशय है कि अगर संसद ने मेडिकल से जुड़ा कोई नियम बनाया तो एमसीआइ ही इसे देश भर में लागू कराती थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान एमसीआइ के कामकाज से जुड़ी कई समस्याएं सामने आई हैं। केंद्र सरकार के अनुसार एमसीआइ के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही थी। एमसीआइ के एक पूर्व अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए थे। एमसीआइ में चीजें किस हद तक गलत हैं, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआइ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया था। एमसीआइ उन्हें भी काम करने नहीं दे रहा था। उस समिति को स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर बताना पड़ा कि एमसीआइ सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक को नहीं मान रहा है। स्पष्ट है कि एमसीआइ बदलती स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार न तो मेडिकल के पाठ्यक्रमों को बदल पाया और न ही नए कोर्स प्रारंभ कर सका। यही कारण है कि पिछले वर्ष सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी एमसीआइ को निलंबित कर बॉर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) को मेडिकल शिक्षा और सेवा की जिम्मेदारी दे दी थी। फिलहाल एनएमसी देश में मेडिकल शिक्षा को नियंत्रित कर रहे बॉर्ड ऑफ गवर्नर्स की जगह लेगा। एनएमसी बिल तैयार करने वाले नीति आयोग को भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली पर ऐतराज था।

गैर-एमबीबीएस भी देंगे दवा : देश भर में डॉक्टरों ने एनएमसी बिल की धारा 32 (1), (2) और (3) को लेकर चिंता जताई है। दरअसल इसमें एमबीबीएस डिग्री धारकों के अलावा गैर चिकित्सकीय लोगों या सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि एनएमसी बिल द्वारा देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने में सहायता मिलेगी। ब्रिज कोर्स के जरिये सीमित एलोपैथी प्रैक्टिस करने का अधिकार यूनानी, आयुर्वेद या होमियोपैथी के डॉक्टरों को भी मिलेगा। डॉक्टरों का कहना है कि इससे नीम-हकीम, झोलाछाप डॉक्टरों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को छह माह का मेडिकल कोर्स करके प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा। डॉक्टरों को इस प्रावधान पर भी आपत्ति है। डॉक्टरों का कहना है कि हम लोगों को डॉक्टर बनने के लिए कई वर्षों तक पढ़ाई करनी होती है। वैसे में प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स महज छह माह की पढ़ाई करके डॉक्टर कैसे बन जाएंगे तथा उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा, तो स्वास्थ्य की गुणवत्ता भयावह रूप से गिरेगी।

चिकित्सा शिक्षा महंगी होने की जताई जा रही आशंका

प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एक निर्धारित संख्या की सीटों की फीस सरकार अपने हिसाब से तय करेगी। शेष सीटों पर प्राइवेट कॉलेजों का अधिकार होगा कि वो अपने मुताबिक फीस रख सकते हैं। प्रश्न ये है कि रेगुलेटर के रूप में क्या एनएमसी को निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस रेगुलेट करनी चाहिए। सामान्य तौर पर निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में शिक्षा प्रदान करने वाले निजी संस्थानों को गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करना होगा। वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की फीस को रेगुलेट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटेशन फीस पर तो प्रतिबंध लगाया था, लेकिन शिक्षण संस्थानों को वाजिब सरप्लस फीस लेने की अनुमति दी थी, जिसका उपयोग उसके विस्तारीकरण और विकास के लिए किया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि बिल में इस तरह के प्रावधान मेडिकल शिक्षा को सस्ता करेंगे। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि वर्तमान में प्राइवेट कॉलेजों में 85 प्रतिशत सीटें सरकार की तथा 15 प्रतिशत सीटें प्रबंधन की होती हैं। लेकिन नई व्यवस्था में प्रबंधन की सीटें 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जिससे मेडिकल शिक्षा काफी महंगी हो जाएगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में इस समय कम से कम पांच लाख डाक्टरों की कमी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या केवल 502 है, जबकि देश को जरूरत कम से कम 1,200 मेडिकल कॉलेजों की है। ऐसे में देश पहले से ही डॉक्टरों की कमी के कारण झोलाछाप डॉक्टरों की समस्या से ग्रस्त है और अक्सर इसके दुष्परिणाम सामने आते रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ही एक रिपोर्ट इसे स्पष्टता से दर्शाती है कि भारत में डॉक्टरों की भारी कमी के कारण एक तिहाई फर्जी एलोपैथी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को लाइसेंस देने की नीति से फर्जी डॉक्टर की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। भारत में इस समय कम से कम 20 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, समस्या केवल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की नहीं है, अपितु में एंटीबायोटिक दवाइयां देने के लिए उचित तरीके से प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी है। ऐसे में क्या इन अकुशल स्वास्थ्य कर्मियों को छह माह की ट्रेनिंग देकर डॉक्टर बनाया जा सकता है? आजादी से पहले इस तरह की प्रणाली थी। एमबीबीएस डॉक्टरों की संख्या की तुलना में लाइसेंसी डॉक्टर ज्यादा होते थे। वर्ष 1946 में 'भोरे समिति' की रिपोर्ट बताती है कि उस समय देश में करीब 47,500 पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, जिनमें से 17,500 एमबीबीएस और करीब 30,000 लाइसेंसी थे। इसी भोरे समिति ने गैर एमबीबीएस लाइसेंसधारियों को प्रतिबंधित किया था।

एनएमसी के स्वायत्तता से संबंधित विवाद : एमसीआइ में सदस्यों का निर्वाचन होता था यानी वह एक निर्वाचित निकाय थी। लेकिन इसके विपरीत एनएमसी के सदस्य मनोनीत होंगे। सरकार का कहना है कि एमसीआइ चुनाव प्रक्रिया के कारण गुटबंदी, खेमेबाजी और स्वार्थलोलुपता में डूबा था। सरकार का कहना है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी में चुने हुए लोग न होकर नॉमिनेटेड लोग होने चाहिए, जिससे सरकार नीतियों का समुचित क्रियान्वयन कर सके। इस मामले पर डॉक्टरों का कहना है कि एनएमसी में चुनाव होने से वह एक लोकतांत्रिक और प्रतिबद्ध संस्था बनेगी। उनके अनुसार चुनाव के कारण डॉक्टर दिशा भ्रमित होते हैं, यह आरोप उचित नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार इस बिल में मूलतः एनएमसी की स्वायत्तता खत्म कर दी गई है।

मेडिकल छात्रों के लिए प्रस्तावित 'नेक्स्ट' परीक्षा का विरोध : इस बिल के पास होने के बाद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरों को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए एक और टेस्ट देना होगा। विधेयक की धारा 15 (1) में छात्रों को प्रैक्टिस करने से पहले और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले आदि के लिए नेशनल एक्जिट टेस्ट 'नेक्स्ट' की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक यह टेस्ट केवल विदेश से मेडिकल पढ़कर आने वाले छात्र देते थे। उसे पास करने के बाद ही मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलेगा। डॉक्टरों का विरोध इस बात को लेकर है कि कोई छात्र एक बार यह परीक्षा नहीं दे पाया तो उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है।

निष्कर्ष : इस बिल के अंतर्गत एक काउंसिल बनाई जाएगी जो राज्यों की समस्याएं और सुझाव सुनेगी। मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी मेडिकल प्रोफेशनल्स को प्रोत्साहित करने संबंधी प्रावधानों को भी इसमें महत्व दिया गया है। डॉक्टरों का भी कहना है कि एनएमसी से उनका विरोध नहीं है, अपितु इसके कुछ प्रावधानों का वह विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि एमसीआइ को खत्म करेंगे तो पूरा ढांचा टूटेगा और संबंधित गड़बड़ियां सामने आएंगी। मूलतः यह विधेयक भारतीय चिकित्सा प्रणाली में एक शल्य चिकित्सा की तरह है जिसके दूरगामी परिणाम दिखने की संभावना है। साथ ही सरकार कुछ प्रावधानों में भविष्य में क्रियान्वयन संबंधी अनुभवों के बाद संशोधन कर सकती है।

डॉक्टरों का एकाधिकार कम करने की कोशिश

यह बिल मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस के रेगुलेटर के रूप में नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना करता है जिसमें 25 सदस्य होंगे। इन 25 सदस्यों में 17 अर्थात 68 प्रतिशत मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे। एमसीआइ यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की संरचना की पड़ताल करते हुए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी (2016) ने कहा था कि यह विविधतापूर्ण नहीं है और इसमें अधिकतर डॉक्टर होते हैं जो जनहित की अपेक्षा अपना हित देखते हैं। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव दिया था कि डॉक्टरों का एकाधिकार कम करने के लिए एनएमसी में विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को शामिल किया जाना चाहिए जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ के विशेषज्ञ, सोशल साइंटिस्ट, हेल्थ एकॉनोमिस्ट और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े गैर सरकारी संगठन भी शामिल हों। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड किंगडम में जनरल मेडिकल काउंसिल जो मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है, वहां पर 12 मेडिकल प्रैक्टिशनर और 12 सामान्य सदस्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी और स्थानीय सरकार के अधिकारी होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इस तरह के बदलाव प्रावधानों का भारत में डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनका मानना है कि पहले की तुलना में रेगुलेटरी निकाय में उनका प्रतिनिधित्व घटा है।

खरी-खरी

सपनों को काटती 'कट मनी'

सुधीर कुमार चौधरी

सपने दिखाना सत्ता का नैसर्गिक स्वभाव है। सिंहासन पर बैठकर सपने दिखाना आसान होता है। लेकिन जनता के लिए भूखे पेट नींद आना और सपने देखना बेहद दुष्कर। जनता जानती है कि सपनों से पेट नहीं भरता, लेकिन फिर भी जीने के लिए सपने जरूरी हैं।

आम आदमी सपनों और सच के मध्य लड़खड़ाते हुए उम्मीद भरी आंखों से सरकार की ओर ताकता है। उसके कानों में चुनावी वादे गूंजते रहते हैं। सत्ता उसके सपने को सच में तब्दील करने का भरोसा दिलाती है। सत्ता के दलाल उसकी सूनी आंखों में थोड़ा उजास भरने की साजिश में सफल हो जाते हैं। उसके नन्हें से सपने को धुंधली हकीकत में बदलने के रेट भी फिक्स कर दिए गए हैं। राजनीति की भाषा में यही तो सुशासन होता है। मोल-भाव का झंझट ही नहीं। कीमत चुकाओ और सरकारी योजनाओं के पेड़ से मनचाहा सपना तोड़ लो।

कहा गया है कि गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, इसकी प्रकृति व सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आता। इसी तरह रिश्वत को चाहे घूस, कमीशन, रंगदारी, सेवा शुल्क, कट मनी कुछ भी कहो, इसके प्रभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवस्था के उर्वर धरातल पर 'कट मनी' गाजर घास की भांति लहलहा रही है। विकास के तालाब में जल कुंभियों की भांति पनपी कट मनी लुप्त होती ईमानदारी को मुंह चिढ़ा रही है। कट मनी के पिंजरे में कैद बौनी राजनीति सिद्धांतों की दहाड़ मारने का स्वांग भर रही है।

समाजवाद में 'कट मनीवाद' दूध में पानी की भांति विलीन को गया है। यह शक्तिवर्धक प्रजातांत्रिक पेय कुपोषित जनता को शान से परोसा जा रहा है। व्यवस्था के सूचना पटल पर विकास के रेट चस्पा कर दिए गए हैं। रिश्वत के सरकारीकरण ने विकास की राह आसान कर दी है। ऐसी समर्पित सरकार प्रजातंत्र की शान है। जनता ऐसा पारदर्शी शासन पाकर नतमस्तक है। जनता को चाहिए कि कट मनी चुकाकर बने शौचालय में गंधाती राजनीति की दुर्गंध के साथ जीना सीखे। श्मशान में कट मनी का घी पाकर सुलगती लकड़ियों की आंच को सहन करना सीखे। पसीने से खरीदे मनरेगा कार्ड को सहेजकर रखना सीखे। कट मनी की नींव पर खड़े मकान में रहने का आनंद ले। सिलेंडर में भरी कट मनी की गैस से फूलती रोटी का स्वाद चखे। एक अदद वोट और अंजूरी भर कट मनी के बदले सरकार इतना दे तो रही है।

ट्वीट-ट्वीट

सुषमा जी के बिना राजनीतिक परिदृश्य की कल्पना करना मुश्किल है। मेरे राजनीतिक जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उन्होंने बड़ी बहन की तरह हमेशा मेरा सहयोग किया। राजनीति से इतर भी वह एक बहुत अच्छी इंसान थीं।

स्वप्न दासगुप्ता@swapan55

जम्मू-कश्मीर का विभाजन स्वागतयोग्य कदम है। हालांकि कश्मीरियों के मानस पर इसकी टीस लंबे समय तक हावी रहेगी। हमें देश भर में कश्मीरियों को गले लगाने और उनसे सहानुभूति जताने की जरूरत होगी, लेकिन अलगाववादियों को बिल्कुल भाव नहीं देना होगा।

वेद प्रकाश मलिक @Vedmalik1

तमाम लोग जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर पुनर्विचार वाले मेरे ट्वीट पर जयचंद आदि कह रहे हैं। कोस रहे हैं। उन सबसे सविनय निवेदन-स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस कदम को अस्थायी बताया, घोषणा की कि स्थिति सुधरते ही इसे पलटा जाएगा। सोचिए, समझिए। गाली से विचार श्रेष्ठ है।

राहुल देव @rahuldev2

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या टेस्ट मैच की जर्सी पर खिलाड़ियों के नाम और नंबर का चलन उचित है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस के कुछ नेताओं का रवैया पार्टी के लिए आत्मघाती है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सुषमा जी तो ना रहीं याद रहेगा काम,
लेता हर इंसान है इक दिन पूर्णविराम।
इक दिन पूर्णविराम याद उसकी ही आती,
सत्कर्मों की छोड़ गया जो पीछे थाती।
जो थे फंसे सुदूर बनीं उनकी खातिर मां,
ऐसों को अब याद बहुत आएंगी सुषमा।

– ओमप्रकाश तिवारी

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक,
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश डायरी

पहरे के बावजूद कश्मीर पर खुले कुछ हाथ

कश्यपमेरु यानी कश्मीर को जिस अनुच्छेद 370 के कारण अलगाव की घाटी बना दिया गया था उसमें दमदार संशोधन हो गया। कश्मीर केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, ऐसा नमक है जो हिमाचल प्रदेश से कन्याकुमारी तक और कच्छ से मेघालय तक अपने होने की अनुभूति करवाता है। यह वही कश्मीर है, जहां ललद्यद जैसी संत कवयित्री हुईं, सम्राट ललितादित्य जैसे राजा हुए जिनका साम्राज्य ईरान और चीन तक था। यह वही कश्मीर है, जो हमें बॉलीवुड में बाद में दिखा, उससे पहले कालिदास के 'मेघदूत' और 'कुमारसंभव' में दिखा, बल्कि उससे भी पहले कल्हण की 'राजतरंगिणी' की आठों तरंगों में दिखता है जहां मां क्षीर भवानी अब भी आशीर्वाद देती हैं। बेशक उसकी संतानें कश्मीरी पंडित होने का संताप भुगतती रही हैं, जहां वितस्ता ने अपने प्रवाह से संस्कृति को सींचा है, जहां 'हिंद की चादर' गुरु तेग बहादुर जी अपने नौ वर्षीय पुत्र गुरु गोबिंद सिंह के कहने पर औरंगजेब से भिड़ गए थे कि वह कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करने पर बाध्य न करे, शहीद हो गए थे।

इसी कश्मीर पर टेढ़ी नजर करने वालों के खिलाफ हिमाचली सपूत, पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बतरा तक लंबी फेहरिस्त है। जाहिर है, सत्तर वर्ष से जड़ें जमा चुके फोड़े की शल्य क्रिया में चीखें कई तरफ से उठनी थीं। उठीं! सबने प्रतिक्रियाएं भी दीं। अधिसंख्य पक्ष में आए, कुछ प्रतिपक्ष में आए। लेकिन जिस हिमाचल प्रदेश के हर दूसरे घर से एक व्यक्ति सेना में हो, वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता मुंह में दही जमाए बैठे रहें, यह विचित्र दृश्य रहा है। राज्यसभा ने मुहर भी लगा दी, लेकिन न प्रदेशाध्यक्ष बोलने को तैयार हुए और न विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता। आम आदमी खुश था, प्रसन्न थे विस्थापित कश्मीरी पंडित, लेकिन चुप थे कांग्रेस के बड़े नेता। लेकिन देश के कुछ मौलिक प्रश्नों के हल मिलने पर कांग्रेस के ही कई नेता चुप न रह सके। हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में गए भाजपा के बड़े नेता रहे सुरेश चंदेल ने फेसबुक पर केंद्र सरकार को बधाई दी। जवाली से विधायक रहे नीरज भारती ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के युवा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने भी मोदी सरकार के फैसले को सराहा। दूसरे दिन कांग्रेस सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे सुधीर शर्मा ने भी 'पहले देश, फिर पार्टी और फिर परिवार' की बात कहते हुए अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का स्वागत किया। सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजिंद्र राणा ने भी मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया। कांग्रेस का यह परिदृश्य केंद्रीय स्तर पर और पूरे देश में था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसकी बानगी बहुत करीब से देखी गई। पार्टी लाइन की दिक्कत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की इस बात से समझी जा सकती है, 'अभी तक केंद्र से कोई निर्देश नहीं आए हैं। जैसा पार्टी कहेगी, वैसा कहेंगे।' सवाल है कि किससे आने थे निर्देश? क्या कार्यकारी अध्यक्ष मोती लाल वोरा से? सारा देश टीवी देख रहा था। पार्टी लाइन तो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी साफ कर दी थी। उनके विरोध में बेशक उनकी निजी पीड़ा भी थी, लेकिन उनका मत स्पष्ट था। क्या राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता को हिमाचल कांग्रेस अपना नेता नहीं मानती? और अगर अब भी केवल राहुल गांधी के इशारे का ही इंतजार था तो क्या यह समझें कि अध्यक्ष पद को छोड़ चुके राहुल गांधी बेशक पार्टी भी छोड़ दें, पार्टी उन्हीं के इर्दगिर्द घूमेगी?

विक्रमादित्य सिंह, विधायक, कांग्रेस पार्टी

सुरेश चंदेल, नेता, कांग्रेस पार्टी

हिमाचल प्रदेश में विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस के कई ध्रुव हो चुके हैं। बीते दिनों हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाते प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की जयंती को रुतबा देने और पाठयक्रम में उनके कृतित्व को शामिल करने का बड़ा दिल मुख्यमंत्री ने दिखाया, लेकिन कांग्रेस अपने ही नेता की जयंती पर एक न हो सकी। यही कारण है कि वह उस भाजपा से टकरा नहीं पा रही है, जिसके संगठन में भी सुगबुगाहटें साफ सुनी जा सकती हैं। भाजपा के भीतर कांगड़ा से इंदु गोस्वामी, रमेश धवाला के मुद्दे और शिमला स्थित महत्वपूर्ण पदाधिकारी को बदले जाने की चर्चाएं भी रही हैं। लेकिन इन विषयों पर कांग्रेस तब बात करे जब वह अपनी दलदल से निकले। विचित्र यह है कि हिमाचल में कांग्रेस अपने भीतर से दीपेंद्र हुड्डा और मिलिंद देवड़ा के स्वरों को सुधीर शर्मा, विक्रमादित्य सिंह और सुरेश चंदेल जैसे स्वरों में नहीं सुन पा रही है। हिमाचल कांग्रेस को अपने वजूद पर गौर करना चाहिए, यह लोकतंत्र के हक में ही होगा। रही तीसरे दलों की बात तो वह अब इससे अगली धाराओं की बात भी उठा रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा मिला है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि हिमाचल के साथ कश्मीर का इतिहास किसी तरह नत्थी नहीं होता। यह दो विधान और दो झंडों वाला प्रदेश नहीं, अपितु हर कदम पर देश के काम आने वाला राज्य है जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति और भौगोलिक स्थिति है।

मुद्दा

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

विचारधारा के प्रति सदैव समर्पण

चुनावों या अन्य कार्यक्रमों में सुषमा स्वराज की सभा की मांग हर राज्य से होती थी। वाजपेयी और आडवाणी के बाद उनका ही नंबर होता था। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर उनकी पकड़ अद्भुत थी

सुषमा स्वराज को वास्तविक राजनीतिक कार्यकर्ता और संपूर्ण राजनेता कहा जाएगा। आज के दौर में जब धीरे-धीरे राजनीति को भी प्रोफेशन मान लिया गया है उसमें सुषमा स्वराज नई पीढ़ी के लिए कई मायनों में प्रेरणा स्रोत हो सकती हैं। एक सामान्य छात्र कार्यकर्ता से आरंभ करते हुए राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष तक पहुंचने तक की उनकी जीवन गाथा में एक भी पड़ाव ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ा भी स्याह पक्ष हो। कभी प्रोफेशन या कैरियर की तरह सफलता के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता नहीं अपनाया। एक कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, पार्टी पदाधिकारी और प्रवक्ता के रूप में, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने न केवल भारतीय जनता पार्टी, बल्कि भारत की राजनीति तथा प्रशासन पर जो छाप छोड़ी है वह इतिहास का अविस्मरणीय अध्याय बना रहेगा।

आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में एक 25 साल की लड़की का भाषण सुनने के लिए दूर-दूर से लोग किस तरह इकट्ठा होते थे उस समय के लोग उसका रोमांचक वर्णन करते हैं। मुजफ्फरपुर से जॉर्ज फर्नांडिज का नामांकन करा दिया गया था। वह जेल में थे, सुषमा स्वराज उनके प्रचार के लिए वहां पहुंचीं और कई दिनों तक ठहरी थीं। एक मीटिंग खत्म होती और दूसरी मीटिंग कहां है यह जानकारी कर लोग सुनने के लिए वहां भागते थे। जॉर्ज सहित आसपास के दूसरे क्षेत्रों के उम्मीदवारों की विजय में उनका महत्वपूर्ण योगदान था।

इस तरह सुषमा स्वराज की आरंभिक राजनीति हरियाणा से अवश्य आरंभ हुई, लेकिन उसी समय से उसका राष्ट्रीय विस्तार भी हो गया। जब उनका आगमन भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में हुआ वह देश और विदेश में विचारधारा को लेकर व्यापक उथल-पुथल और बदलाव का दौर था। वर्ष 1989 के आसपास केंद्रीय राजनीति में उनका पदार्पण हुआ था। 1990 में जब लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा चली थी, सुषमा स्वराज की भारतीय राजनीति में अलग छाप छोड़ने की शुरुआत वहीं से होती है। अगर हम सुषमा स्वराज के संपूर्ण जीवन का मूल्यांकन करें तो हर स्तर पर वो विचारधारा के प्रति समर्पित और निष्ठावान व ईमानदार नेता दिखाई देंगी। उनके जीवन का अनुशासन और सहजता की तुलना 1990 के दशक में आडवाणी से की जाती थी। वो सबसे मिलती थीं, बात करती थीं, कार्यकर्ताओं को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती थीं। हालांकि भाजपा में उस समय दूसरी पीढ़ी के कई प्रतिभावान नेताओं का दौर था। उमा भारती का पदार्पण उसी दौरान हुआ, केएन गोविंदाचार्य थे, प्रमोद महाजन थे, वेंकैया नायडू का आगमन भी केंद्रीय राजनीति में उसी समय हुआ। इन सब नेताओं के बीच सुषमा स्वराज ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके संसदीय भाषण को जब भी पढ़ा सुना जाएगा उसमें वैचारिक प्रखरता के साथ विषयों की गहराई तथा शब्दों के संयोजन किसी को भी चमत्कृत कर देगा।

बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक समय ऐसा आया जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव पेश हुआ था कि पार्टी का सिद्धांत वही होगा जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का है। यह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय की बात है। सुषमा पहली नेता थीं जिन्होंने इसका डटकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमने बहुमत न होने के कारण राजग की सरकार बनाई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी पार्टी का सिद्धांत बदल गया। उसके बाद और लोगों की आवाज उठी और फिर वह प्रस्ताव गिर गया। जो भी भाजपा के वैचारिक प्रवाह पर शोध करेगा उसे यह प्रकरण अवश्य प्रभावित करेगा कि किस तरह उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान की रक्षा में अपनी भूमिका निभाई।

सुषमा स्वराज के 28 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में तथा उसके पहले दो बार विधानसभा सदस्य के रूप में एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब संसद में बोले गए उनके शब्द को कभी कार्यवाही से अलग करना पड़ा। यह सामान्य बात नहीं है। बड़े-बड़े लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जिनको संसदीय कार्यवाही से निकालना पड़ता है, क्योंकि वे शब्द असंसदीय होते हैं। इसी तरह अपने विरोधियों के खिलाफ तीखा हमला करते हुए सुषमा के शब्द कभी ऐसे नहीं होते थे जिससे किसी व्यक्ति को अपना अपमान महसूस हो। अटल बिहारी वाजपेयी की यही शैली थी और लालकृष्ण आडवाणी की भी। राजनीति में वक्तृत्व कला का सूत्र ही यही है कि विरोधियों के साथ संघर्ष में या उनका विरोध करते हुए उनके मुद्दों पर, कदमों पर पूरे तीखे हमले करिये, लेकिन कभी निजी हमले नहीं होने चाहिए। सुषमा स्वराज ने इस मर्यादा को बनाए रखा। वर्तमान राजनीति में स्वयं भारतीय जनता पार्टी में और दूसरी पार्टी के नेता भी सुषमा स्वराज बहुत कुछ सीख सकते हैं। विदेश मंत्री के रूप में पांच वर्ष का उनका कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें मीडिया में बहुत कुछ उनके बारे में नहीं आता था। उन्होंने कोई इंटरव्यू भी शायद ही दिया। लेकिन वह पहली विदेश मंत्री थीं जिनके पांच वर्ष के कार्यकाल में भारत 182 देशों तक पहुंचा। यह ऐतिहासिक उपलब्धि किसी दूसरे विदेश मंत्री को प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त राष्ट्र में दिए गए उनके दो भाषण ऐसे थे जिनको ऐतिहासिक दर्जा मिल गया। पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारत की दृष्टि से दुनिया को अवगत कराना महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद कराने के लिए काफी कोशिश की और अब होना शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय और भारत के राजनय में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफी कोशिश की। भारत के राजनय में भारतीय संस्कृति सभ्यता सॉफ्ट पावर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसे उन्होंने विदेश नीति का अभिन्न अंग बनाने के कदम उठाए और इसका असर हुआ है। ट्वीटर के माध्यम से विदेशों में रहने वाले लोग सहायता के लिए उनसे जुड़े और उन्हें पर्याप्त सहायता मिली।

टाटा स्टील का शुद्ध लाभ 64 फीसद गिरा

नई दिल्ली : टाटा स्टील के कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफे में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2019) में 63.6 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ 701.97 करोड़ रुपये पर सिमट गया। हालांकि समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की कुल आय बढ़कर 36,198.21 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। कंपनी ने मांग में कमी और लागत मूल्य में बढ़ोतरी को लाभ घटने की वजह बताया है। (प्रेट्र)

सुस्ती का सिलसिला खत्म करने के लिए आरबीआइ द्वारा उठाए कदमों का जल्द असर दिखना शुरू होगा। नीतिगत कदमों के साथ केंद्रीय बैंक के नियामकीय उपाय भी असर दिखाएंगे।
— रजनीश कुमार
चेयरमैन, एसबीआइ

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलोग्राम	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
36,690.50	10,948.25	₹37,920	₹43,670	₹70.89	$56.73
286.35	92.75	₹1,113	₹650	₹0.08	

आरबीआइ की पहल से मांग में बढ़ोतरी तय

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

▶ उद्योगों ने कहा अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में अब बैंकों पर दारोमदार

▶ विकास की दर बढ़ाने के लिए कर्ज की रफ्तार में वृद्धि आवश्यक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की तरफ से पहली बार ब्याज दर कटौती की प्रचलित परंपरा तोड़ते हुए रेपो रेट को 0.35 फीसद नीचे लाने के फैसले को अर्थव्यवस्था के हालात में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्तीय क्षेत्र के जानकारों और उद्योग का मानना है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से न केवल अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में मदद मिलेगी बल्कि घटती मांग में भी बदलाव आएगा। हालांकि उद्योगों का कहना है कि अब यह बैंकों के ऊपर है कि वे रेपो रेट में कमी का लाभ ग्राहकों और उद्योगों को दें ताकि कर्ज के प्रवाह में वृद्धि हो सके।

अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति में जब अधिकांश क्षेत्रों में मांग कम हो रही है रिजर्व बैंक की तरफ से बुधवार को उठाये गये कदम विकास की रफ्तार बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के चेयरमैन रजनीश कुमार का कहना है कि रिजर्व बैंक का यह अप्रत्याशित कदम इस बात को दर्शाता है कि मौद्रिक नीति बाजार को हैरान कर अच्छे नतीजे दे सकती है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की दिशा में पिछले कुछ दिनों में रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति से लेकर विनियमन की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

आरबीआइ ने बैंकों को हिदायत दी है कि वे ग्राहकों को दर कटौती का जल्द से जल्द फायदा दें। प्रतीकात्मक

यस बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री शुभदा राव मानती हैं कि रिजर्व बैंक ने इस कदम ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह के कदम दोहराए जा सकते हैं। 'दैनिक जागरण' से कोटक महिंद्रा बैंक की प्रेसिडेंट कंज्यूमर बैंकिंग शांति एकंबरम ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास की रफ्तार बढ़ाने में मददकारी चौतरफा ढांचा तैयार हो। एकंबरम का कहना है, 'ऐसे वक्त में जब वैश्विक स्तर पर धीमी होती अर्थव्यवस्था से ट्रेड वार के खतरे बढ़ रहे हैं। घरेलू स्तर पर महंगाई की दर नीचे है। निर्यात और आयात दोनों में कमी आ रही है और शहरी व ग्रामीण दोनों बाजारों में मांग घट रही है। केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है।' जानकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज देने का रास्ता खुलेगा। खासतौर पर हाउसिंग सेक्टर में 20 लाख रुपये तक का कर्ज देने का रास्ता साफ होगा।

उधर इंडिया इंक का मानना है कि अब वक्त आ गया है जब बैंक कर्ज का प्रवाह बढ़ाने जैसे कदम उठाएं। फिक्की के प्रेसिडेंट संदीप सोमानी ने अपने एक बयान में कहा है, 'जब तक ब्याज दर में कमी का यह सिलसिला बैंक आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमें निवेश और खपत की स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं दिखेगा। इसलिए बैंकों को यह काम काफी तेज रफ्तार के साथ करना होगा।' पीएचडी चैंबर के प्रेसिडेंट राजीव तलवार ने कहा कि उम्मीद है कि एमएसएमई क्षेत्र तक कर्ज का लाभ पहुंचाने की दिशा में रिजर्व बैंक रेपो दर को पांच फीसद के स्तर तक नीचे लाएगा। 'लेकिन इस वक्त रेपो दर में कमी का लाभ जमीन तक पहुंचाने के लिए अब बैंकों की भूमिका अहम हो गई है।' उधर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन रवि सहगल ने कहा कि केंद्रीय बैंक यह भी सुनिश्चित करे कि निर्यातकों को कर्ज का प्रवाह बढ़े।

रेपो दर घटाने के साथ आरबीआइ ने किया ज्यादा कर्ज बांटने का भी इंतजाम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ 10 लाख रुपये तक के कृषि लोन और 20 लाख रुपये तक के एनबीएफसी के होम लोन को प्राथमिकता क्षेत्र के कर्ज में डालने की मिली इजाजत

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने कर्ज को सस्ता करने के साथ ही इस बात का भी इंतजाम किया है कि बैंकिंग व्यवस्था के जरिए ज्यादा कर्ज बांटे जाएं। कर्ज बांटने में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की अहम भूमिका को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने उनके समक्ष मौजूदा फंड की समस्या को दूर करने के लिए भी कुछ उपायों का एलान किया है। इसके तहत बैंकों को यह छूट दी गई है कि वह अपनी टियर-वन कैपिटल का अधिकतम 20 फीसद हिस्सा किसी एक एनबीएफसी को कर्ज दे सकते हैं। यह सीमा अभी तक 15 फीसद तक की थी। साथ ही बैंक किसी पंजीकृत एनबीएफसी को कृषि, एमएसएमई या होम लोन बांटने के लिए कर्ज देने के लिए जो फंड देते हैं उसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की श्रेणी (पीएसएल) में डाला जाएगा।

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा कि एनबीएफसी अगर कृषि क्षेत्र को 10 लाख रुपये तक के कर्ज, एमएसएमई क्षेत्र को 20 लाख रुपये तक के कर्ज, 20 लाख रुपये तक का होम लोन देने के लिए किसी बैंक से कर्ज लेते हैं, तो बैंक उस फंड को पीएसएल में डाल सकते हैं। इस फैसलों के बारे में दास ने बाद में बताया भी कि, 'आर्थिक विकास तेज करने में बेहद आवश्यक एनबीएफसी को विफल होने नहीं दिया जा सकता। उन्हें बचाने के लिए ये सारे कदम उठाये जा रहे हैं।' उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बड़े व महत्वपूर्ण एनबीएफसी को डूबने नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने जिस तरह से पिछले आम बजट में एनबीएफसी को ज्यादा फंड उपलब्ध कराने के लिए कुछ उपायों का एलान किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आरबीआइ ने ये कदम उठाए हैं। इन सभी कदमों से एनबीएफसी को कुल 1,300 अरब रुपये का कर्ज ग्राहकों को बांटने के लिए मुहैया कराया जा सकता है।

गौरतलब है कि देश के प्रमुख बड़ी एनबीएफसी वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) जैसी बड़ी एनबीएफसी के विफल होने के बाद सरकार के लिए इन कंपनियों को बचाना एक बड़ी चुनौती है। मौजूदा आर्थिक संकट के पीछे भी एक बड़ी वजह यह भी है कि बड़ी एनबीएफसी इस वक्त कर्ज बांटने की हालत में नहीं हैं।

ऑटो सेक्टर ने मांगा प्रोत्साहन पैकेज

गुजारिश ▶ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में उद्योगपतियों ने रखी मांग

कहा, रेपो दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बैंकों को निर्देश दे सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मंदी की मार झेल रहे ऑटो उद्योग ने सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है। ऑटो उद्योग को गति देने के लिए उन्होंने वाहनों पर जीएसटी की दर घटाने की मांग भी की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बुधवार को हुई एक बैठक के दौरान ऑटो क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने यह मांग रखी। इस बैठक में मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव और महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रेसिडेंट (ऑटोमोटिव सेक्टर) राजन वढेरा के अलावा ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों प्रतिनिधि व डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे।

वित्त मंत्री ने यह बैठक ऐसे समय बुलाई, जब ऑटो सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जून के दौरान वाहनों की बिक्री 12.35 फीसद घटकर 60,85,406 यूनिट रह गयी है जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 69,42,742 यूनिट थी। वहीं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का कहना है कि ऑटो सेक्टर में मंदी के चलते बीते तीन महीने में लगभग दो लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है। 'दैनिक जागरण' ने भी हाल में एक विशेष सीरिज के जरिये ऑटो सेक्टर की समस्याओं को उजागर किया था।

ऑटो सेक्टर गंभीर मंदी से गुजर रहा और लाखों नौकरियों पर खतरे का सामना कर रहा है। फाइल

वित्त मंत्री के साथ बैठक में शामिल ऑटो सेक्टर के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री का ध्यान ऑटो क्षेत्र की चुनौतियों की आकर्षित किया। उन्होंने यह भी बताया कि अगर इस क्षेत्र को संकट से नहीं उबारा गया तो इसमें बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां जा सकती हैं।

बढेरा ने कहा कि हमने ऑटो उद्योग के लिए मदद की मांग की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार ऑटो उद्योग को प्रोत्साहन पैकेज देगी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग में गिरावट और इसे बढ़ाने के संभावित उपाय जानने की कोशिश की। बैठक में शामिल भारी उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों का रुख ऑटो सेक्टर को गति देने के समर्थन में था। ऑटो उद्योग ने अपनी समस्याओं का जिक्र करते हुए ऋण की उपलब्धता व वाहनों की बढ़ती कीमतों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। ऑटो उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह मांग भी दोहराई कि वाहनों के पंजीकरण पर लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही परेशानियों का सामना कर रहा है। उन्होंने वाहनों की बिक्री घटने के चलते नौकरियां जाने के बारे में भी जानकारी दी। ऋण की उपलब्धता के बारे में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत ने सरकार से आग्रह किया है कि वह बैंकों को रेपो दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने का आग्रह करे।

इसके अलावा सरकार बैंकों को यह भी निर्देश दे कि पैसेन्जर व्हीकल सेगमेंट जैसे उन क्षेत्रों को उधार देने में कोताही न बरतें जिसमें फंसे कर्ज का स्तर काफी कम है। बैंक सभी डीलरों को डिफॉल्टर न मानें और जो लोग वित्तीय नियमों का पालन कर रहे हैं, उन्हें बैंक उधार देना बंद न करें। साथ ही उन्होंने सरकार से प्रोत्साहन आधारित स्क्रैप पॉलिसी लाने का आग्रह भी किया ताकि पुराने तथा प्रदूषणकारी वाहनों को हटाकर नए वाहनों की मांग को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने वाहनों पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 फीसद करने की मांग भी की।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के लाभ में बड़ी गिरावट

मुंबई, प्रेट्र : घरेलू ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के कंसोलिडेटेड मुनाफे में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 52.6 फीसद की गिरावट आई है। इस गिरावट के साथ अप्रैल-जून, 2019 तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड कर-पश्चात लाभ (पैट) 894.11 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी के मुताबिक बिक्री में बड़ी कमी आने के चलते उसके मुनाफे को चोट पहुंची है। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की कुल आय मामूली बढ़कर 26,289.48 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इस मद में कंपनी को 26,260.64 करोड़ रुपये हासिल हुए थे।

पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले पांच फीसद गिरावट के साथ समीक्षाधीन अवधि में कंपनी 1,23,690 यूनिट वाहन ही बेच पाई। इस अवधि में कंपनी के ट्रैक्टर की बिक्री भी 15 फीसद गिरकर 82,013 यूनिट रह गई। कंपनी के निर्यात में भी 14 फीसद की गिरावट आई और समीक्षाधीन अवधि में उसके सिर्फ 10,923 वाहनों और ट्रैक्टर का निर्यात हुआ।

कंपनी ने कहा कि वर्तमान चुनौतीपूर्ण वैश्विक और घरेलू वातावरण को देखते हुए विकास को गति देने के लिए ठोस सरकारी उपायों की जरूरत होगी। खराब तिमाही नतीजों के चलते ही बुधवार को बीएसई में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 5.62 फीसद गिरकर 518.45 रुपये पर बंद हुए।

सोना सर्वकालिक उच्च स्तर पर, चांदी 650 रुपये उछली

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीन और अमेरिका के बीच गहराता ट्रेड वार पीली धातु के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। इस गहराते संकट के चलते विदेशी बाजारों में सोने के प्रति निवेशकों का जबर्दस्त आकर्षण देखा गया। इस विदेशी रुख पर भारतीय सराफा बाजार में भी बुधवार को सोने में 1,113 रुपये प्रति 10 ग्राम का बड़ा उछाल देखा गया। इस उछाल के साथ सोना 37,920 रुपये पर पहुंच गया, जो इसका सर्वकालिक उच्च स्तर है। चांदी भी बुधवार को 650 रुपये चढ़कर 43,670 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

पिछले कुछ दिनों से सोने के भाव में लगातार उछाल दिख रहा है। इसी सप्ताह सोमवार को सोना 36,970 रुपये प्रति 10 ग्राम तक चढ़ गया था। कारोबारियों का कहना था कि विदेशी बाजारों में पीली धातु को लेकर निवेशकों के जबर्दस्त उत्साह के साथ-साथ घरेलू स्तर पर अच्छी मांग देखी गई। वहीं, चांदी को सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक इकाइयों भरपूर साथ मिला।

न्यूयॉर्क में सोने का भाव उछाल के साथ 1,487.20 डॉलर, जबकि चांदी का भाव भी सुधार के साथ 16.81 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर पहुंच गया। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 1,113 रुपये चढ़कर 37,920 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना 1,115 रुपये मजबूत होकर 37,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। सोने की आठ ग्राम गिन्नी का भाव भी 200 रुपये मजबूत होकर 27,800 रुपये के पर चला गया। चांदी का सप्ताह आधारित डिलिवरी भाव 694 रुपये उछलकर 42,985 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। चांदी के सिक्कों का भाव भी प्रति सैकड़ा 1,000 रुपये चढ़कर 85,000 रुपये खरीद और 86,000 रुपये बिक्री पर पहुंच गया।

▶ 1,113 रुपये के उछाल के साथ 37,920 रुपये पर पहुंच गया प्रति 10 ग्राम सोने का भाव

▶ चांदी का भाव भी बुधवार को 650 रुपये चढ़कर 43,670 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया

प्रतीकात्मक

रेट कट के बावजूद शेयर बाजारों में मायूसी

▶ सेंसेक्स 286 अंक टूटा, निफ्टी में 92 अंकों की गिरावट

▶ आरबीआइ द्वारा विकास दर अनुमान घटाना निवेशकों को नहीं आया रास

मुंबई, प्रेट्र : घरेलू शेयर बाजारों को जिस शिद्दत से नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कटौती की उम्मीद थी, वह पूरी होने के बावजूद बाजारों में रौनक नहीं आई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने रेपो रेट में उम्मीद से ज्यादा 0.35 फीसद कटौती की। लेकिन देश की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा देने के चलते निवेशकों का सारा उत्साह जाता रहा। दिन के कारोबार में बीएसई का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स 286.35 अंक यानी 0.77 फीसद गिरकर 36,690.50 पर और एनएसई का 50-शेयरों वाला निफ्टी 92.75 अंक या 0.85 फीसद गिरावट के साथ 10,855.50 के स्तर पर बंद हुआ।

ऑटो, मेटल और बैंकिंग शेयरों में भारी बिकवाली के बीच बीएसई के मिडकैप सूचकांक में 0.54 फीसद और स्मॉलकैप सूचकांक में 0.14 फीसद गिरावट दर्ज की गई। तेल-गैस इंडेक्स भी 1.5 फीसद गिरकर बंद हुआ। बीएसई के सेंसेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन महिंद्रा एंड महिंद्रा का रहा, जो 5.62 फीसद टूट गया। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एसबीआइ, वेदांता, एक्सिस बैंक, आइटीसी, आरआइएल, मारुति, एलएंडटी, एचडीएफसी व एचडीएफसी बैंक तथा कोटक महिंद्रा बैंक में भी 4.75 फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि एचयूएल, यस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, टेक महिंद्रा तथा इन्फोसिस के शेयरों में 1.95 फीसद तक का उछाल दर्ज किया गया। निफ्टी में बैंकिंग का सूचकांक 1.3 फीसदी टूटा और सरकारी बैंकों के सूचकांक में करीब 3.5 फीसद गिरावट आई। प्राइवेट बैंकों का इंडेक्स भी करीब एक फीसद गिर गया। आइटी, मीडिया और फार्मा शेयरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया। निफ्टी का आइटी इंडेक्स 0.5 फीसदी और फार्मा इंडेक्स 0.45 फीसद बढ़त पर बंद हुए। लेकिन, निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में 2.4 फीसद, मेटल इंडेक्स में 2.7 फीसद और रियल्टी इंडेक्स में 1.3 फीसद गिरावट दर्ज की गई।

प्रतीकात्मक

गिरावट के बड़े कारण

▶ चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान में मामूली कटौती

▶ खरीफ की बोआई घटने से ग्रामीण इलाकों में मांग घटने की आशंका

▶ अमेरिका व चीन के बीच तकरार से दुनियाभर के बाजारों में गिरावट आना।

सरकार ने ई-कॉमर्स पर सबसे मांगे सुझाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ ऑनलाइन कारोबार को नियमित करने को होंगी कई पाबंदियां

▶ रिफंड और रिटर्न नीति को भी स्पष्ट तौर से वेबसाइट पर देना होगा

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के साथ ही सरकार ने ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग पर लगाम लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में उत्पादों के बारे में साइट पर दर्ज फर्जी समीक्षा की नकेल कसी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने ई-कॉमर्स पर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसमें उपभोक्ताओं के साथ होने वाली ठगी और बेईमानी पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए हैं। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अन्य सभी पक्षकारों से सुझाव मांगे गए हैं।

प्रस्तावित दिशा-निर्देश के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए अलग अधिकारी नियुक्त करने होंगे। ऐसे अधिकारियों के बारे में सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी। शिकायतों का निपटारा हर हाल में एक महीने के भीतर करना ही होगा। उपभोक्ता अपनी शिकायत फोन, ई-मेल अथवा वेबसाइट पर कर सकता है, जिसका निपटारा उक्त अधिकारी करेगा। ई-कॉमर्स के दिशा-निर्देश तय करने के लिए गठित कार्यबल की उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को पहले ही सौंप दी थी, जिसे अब जारी किया गया है। इसमें वाणिज्य और उपभोक्ता मामले से जुड़े लोग शामिल थे। देश में ई-कॉमर्स कंपनियों को 90 दिनों के भीतर भारतीय नियम कानून के मुताबिक अधिसूचित किया जाएगा, तभी वे कारोबार कर सकेंगी। दिशा-निर्देश की शर्तों पर खरा उतरने के बाद उपभोक्ता मामले विभाग से कारोबार की मंजूरी लेनी होगी। भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के नियमों को पूरा करना होगा।

ग्राहकों से ठगी का हर रास्ता बंद करने की तैयारी में है मंत्रालय। प्रतीकात्मक

उत्पाद अथवा सेवा की गुणवत्ता को लेकर उठने वाले सवाल की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। वेबसाइटों पर फर्जी समीक्षा (रिव्यू) देने पर भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। उत्पादों की फर्जी रेटिंग करने वालों की नकेल कसी जाएगी। इस पर पाबंदी लगाने के लिए अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस के तहत कानूनी कदम उठाए जाएंगे। दिशा-निर्देश में ई-कॉमर्स कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। खराब या टूटे-फूटे उत्पादों का दायित्व विक्रेता का होगा। ऐसे सामान को 14 दिनों के भीतर वापस करना होगा। 30 दिनों के अंदर उसकी शिकायत का निवारण करना होगा। ई-कॉमर्स कंपनियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसे लेकर सरकार बहुत गंभीर है। इसे देखते हुए सरकार ने उन पर शिकंजा कसने की जुगत शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों से उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2019 पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की सहमति के साथ ही वह कानून में तब्दील हो जाएगा, जिसके नियम व निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

कुवैत से वाट्सएप पर बीवी को दिया तत्काल तीन तलाक

जासं, मुजफ्फरनगर : कुवैत में नौकरी कर रहे शौहर ने अपनी बीवी को वाट्सएप पर तत्काल तीन तलाक दे दिया। यही नहीं महिला को वाट्सएप से काल कर सीधे भी तीन तलाक बोल दिया। पीड़िता ने शौहर के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

उप्र के मुजफ्फरनगर के गांव बिहारी निवासी फिजा बतूल का विवाह 17 जुलाई 2017 को दक्षिणी कृष्णापुरी मुजफ्फरनगर निवासी चांद मियां से हुआ था। आरोप है कि चांद के कुवैत जाने के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए फिजा का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। 27 मई को पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए विवाहिता के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि चचिया ससुर ने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या का प्रयास किया। इसके बाद शहर कोतवाली में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। फिजा ने अब थाना सिखेड़ा में तहरीर देकर पुलिस को बताया कि वह अपने घर गांव बिहारी में रह रही है। आरोप लगाया कि उसके पति चांद मियां ने नौ जून 2019 की रात में वाट्सएप मैसेज के माध्यम से तत्काल तीन तलाक बोल दिया।

नेपाल के नए कानून से बढ़ा गीताप्रेस का संकट

गजाधर द्विवेदी, गोरखपुर

▶ दूसरे देशों से आने वाली पुस्तकों पर 10 फीसद आयात शुल्क लगने से बिक्री पर पड़ेगा असर

▶ गीताप्रेस लागत मूल्य से कम दर पर पुस्तकें उपलब्ध कराता है

नेपाल सरकार ने दूसरे देशों से आने वाली प्रिंटेड पुस्तकों पर 10 फीसद आयात शुल्क लगाया है। इनमें गीताप्रेस की पुस्तकें भी शामिल हैं। काठमांडू में गीताप्रेस के केंद्र से पूरे नेपाल में पुस्तक पहुंचाई जाती हैं। ऐसे में यह शुल्क गीता प्रेस के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है।

पुस्तक लेकर नेपाल जाने वाले किसी एक वाहन पर पहले एकमुश्त 565 रुपये शुल्क लगता था। अब वाहन पर लदी कुल पुस्तकों की कीमत का 10 फीसद शुल्क देना होगा। सामान्य तौर पर एक वाहन पर सात-आठ लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें भेजी जाती हैं। इस तरह अब 70-80 हजार रुपये देने होंगे। गीताप्रेस लागत मूल्य से कम दर पर पुस्तकें उपलब्ध कराता है।

प्रिंट मूल्य से अधिक दाम पर नेपाल में पुस्तकें बेचना गीताप्रेस के नियम के विरुद्ध होगा। दूसरी तरफ गीताप्रेस अपनी पुस्तकों पर दुकानदारों को वैसे भी 22 फीसद की छूट देता है। इसमें 18 फीसद सामान्य छूट और चार फीसद कैश डिस्काउंट होता है। नेपाल में गीताप्रेस की लगभग एक करोड़ रुपये की पुस्तकें प्रतिवर्ष नेपाल में बिकती हैं।

करीब एक माह पहले नेपाल सरकार ने अचानक आयात शुल्क बढ़ा दिया। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, उन्होंने नेपाल के राजदूत से इस संबंध में बात की है। शायद कोई रास्ता निकल आए।
– लालमणि तिवारी, उत्पाद प्रबंधक, गीताप्रेस

काठमांडू केंद्र के सामने बड़ा संकट खड़ा है। गीताप्रेस केंद्र संचालन के लिए जो 10 फीसद देता है, उससे दुकान का ही खर्च नहीं निकल पाता है। अब नया 10 फीसद आयात शुल्क पुस्तकों की बिक्री पर असर डालेगा।
–जयकिशन सारडा, गीता प्रेस के काठमांडू के केंद्र व्यवस्थापक

उप्र के पूर्व मंत्री गायत्री से ईडी आज करेगा पूछताछ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : खनन घोटाले के मामले में सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब गुरुवार को उप्र के फतेहपुर में हुए खनन घोटाले के मामले में गायत्री से नए सिरे से पूछताछ करेगा। ईडी ने कोर्ट से पूछताछ के लिए दो दिनों की अनुमति हासिल की है। ईडी की टीम किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती गायत्री से सवाल-जवाब करेगी। बेटों पर भी शिकंजा कस सकता है।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने हमीरपुर के अलावा शामली, फतेहपुर, कौशांबी व देवरिया में हुए खनन घोटाले के मामलों में भी मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है। सीबीआइ ने बीते दिनों फतेहपुर में हुए खनन घोटाले के मामले में गायत्री व फतेहपुर के तत्कालीन डीएम अभय सिंह समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी इसी मामले में पूर्व मंत्री से पूछताछ की तैयारी में है। इससे पूर्व ईडी ने हमीरपुर खनन घोटाले में कोर्ट की अनुमति पर गायत्री से चार दिन लंबी पूछताछ की थी। दरअसल, हमीरपुर खनन घोटाले में आरोपित आइएएस अधिकारी बी. चंद्रकला समेत अन्य से पूछताछ में गायत्री प्रसाद की भूमिका सामने आई थी।

आरोपित बिशप के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली नन बर्खास्त

कोच्चि, प्रेट्र : केरल में दुष्कर्म में आरोपित जालंधर क्षेत्र के बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल नन लूसी कलप्पुरा को 'फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट कांग्रेगैशन (एफसीसी) यानी धर्मसभा ने निष्कासित कर दिया है। कलप्पुरा पर एफसीसी के नियमों के विपरीत कार खरीदने, कविताओं की किताब प्रकाशित कराने, कर्ज लेने व प्रतिकूल जीवनशैली अपनाने के भी आरोप हैं।

▶ एफसीसी ने नियम के विपरीत कार खरीदने व किताब प्रकाशित कराने का भी लगाया आरोप

रोमन कैथोलिक चर्च के अंतर्गत आने वाली धर्मसभा ने कहा कि नन को धर्मोचित चेतावनी दी गई थी। धर्मसभा की प्रमुख एन. जोसफ की ओर से पांच अगस्त को आरोपित नन कलप्पुरा को पत्र जारी किया गया है। इसके मुताबिक, 'वह एफसीसी के नियमों का उल्लंघन करने वाली जीवनशैली अपनाने के मामले में संतोषजनक जवाब देने में विफल रहीं। इसलिए, उन्हें धर्मसभा से बर्खास्त किया जाता है।' हालांकि, नन दस दिनों के भीतर इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकती हैं। पत्र में लिखा गया कि नन को उचित समय पर चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई पछतावा व्यक्त नहीं किया। इसलिए, 11 मई को धर्मसभा की आम परिषद की बैठक में कलप्पुरा को सर्वसम्मति से बर्खास्त करने का फैसला किया गया। जनवरी में जारी नोटिस में कलप्पुरा पर नियमों के विपरीत ड्राइविंग लाइसेंस लेने, कार खरीदने, कर्ज लेने, किताब प्रकाशित करने और वरिष्ठों की जानकारी के बिना धन खर्च करने समेत 14 आरोप लगाए गए थे।

प्रदर्शन के बाद से थी निशाने पर : आइएएनएस के अनुसार, दुष्कर्म के आरोपित बिशप की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद से ही नन कलप्पुरा चर्च के अधिकारियों के निशाने पर आ गई थीं। उन्हें चर्च से नोटिस आने शुरू हो गए थे। मीडिया से बातचीत में नन कलप्पुरा ने धर्मसभा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, 'मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने जो भी किया वह प्रदर्शन कर रहीं लाचार नन के समर्थन में किया। मेरा कार खरीदना व किताब लिखना गुनाह कैसे है? अब मैं अपने शुभचिंतकों की मदद से कानूनी कार्रवाई करूंगी।'

पंजाब से बंगाल के बीच मालगाड़ियों पर प्रयागराज से नियंत्रण

प्रमोद यादव, प्रयागराज : पंजाब के लुधियाना से बंगाल के दानकुनी तक चलने वाली मालगाड़ियों पर नियंत्रण प्रयागराज से होगा। इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय के निकट देश का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो गया है।

लुधियाना से दानकुनी तक (1839 किमी) मालगाड़ियों के संचालन के लिए डीएफसी (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर) बन रहा है। इस कॉरीडोर पर ट्रेनों के संचालन के लिए प्रयागराज में आधुनिक तकनीक से युक्त कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें बड़ी स्क्रीन के अलावा सौ से अधिक कंप्यूटर लगाए हैं। यह कॉरीडोर पंजाब से शुरू होकर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल तक जाएगा। इस कार्य को चार चरणों में पूरा किया जाएगा। कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। अभी ट्रायल का काम चल रहा है। डीएफसी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सुशील कुमार मौर्य ने बताया कि अगले साल तक कानपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक डीएफसी का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नए आधुनिक कंट्रोल रूम से केवल रेल ट्रैक ही नहीं, ओवरहेड इलेक्ट्रिक की भी निगरानी होगी।

28 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना तय हुआ है अफगानिस्तान में। लेकिन तालिबान ने अफगान नागरिकों को चुनावी रैलियों में भाग नहीं लेने की चेतावनी दी है। इससे पहले अफगास्तिान में दो बार चुनाव टाले जा चुके हैं।

न्यूज गैलरी

देश छोड़कर भागा दुष्कर्म का आरोपित पाकिस्तानी विधायक

इस्लामाबाद : गिरफ्तारी के डर से दुष्कर्म का आरोपित पाकिस्तान का एक विधायक सोमवार रात देश छोड़कर दुबई भाग गया। अताउर रहमान नाम का यह विधायक प्रांतीय विधानसभा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) का सदस्य है। उस पर विश्वविद्यालय की छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप है। विधायक ने आरोप वापस लेने के लिए पीड़िता को सात करोड़ रुपये देने का प्रलोभन भी दिया था। (एएनआइ)

इराक और सीरिया में आइएस के 18 हजार आतंकी : अमेरिका

वाशिंगटन : अमेरिका ने कहा है कि सीरिया और इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के करीब 14 से 18 हजार तक आतंकी सक्रिय हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह रहस्योद्घाटन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर में सीरिया में आइएस को हराने की घोषणा करते हुए वहां से अमेरिकी सेनाओं को हटाने की घोषणा की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इराक और सीरिया में मौजूद आतंकियों में तीन हजार विदेशी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आतंकियों की संख्या का यह अनुमान विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट पर आधारित है, जिनमें काफी अंतर है। पिछले हफ्ते ही सीरिया मामलों पर अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जेम्स जेफरी ने कहा था कि सीरिया और इराक में करीब 15 हजार सक्रिय आइएस आतंकी हैं। (एएनआइ)

हाफिज आतंकी फंडिंग का दोषी करार

कार्रवाई ▶ आतंक रोधी विभाग ने अदालत में दाखिल की चार्जशीट, सईद को किया शिफ्ट

17 जुलाई से गुजरांवाला जेल में था मुंबई हमलों का मास्टरमांइड

लाहौर, प्रेट्र/एएनआइ : पाकिस्तान के आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग का दोषी करार दिया है। वह 17 जुलाई से जेल में है। उसका मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला से गुजरात की आतंक रोधी अदालत में भेज दिया गया है।

सीटीडी के एक अधिकारी के अनुसार, सईद को बुधवार को लाहौर से करीब 80 किमी दूर गुजरांवाला की आतंक रोधी अदालत (एटीसी) में पेश किया गया। अदालत में दाखिल किए गए आरोपपत्र में उसे आतंकी फंडिंग का दोषी बताया गया है। उन्होंने कहा, 'यह मामला पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए अभियोजक ने मामले को लाहौर से 200 किमी दूर गुजरात की एटीसी अदालत भेजने का आग्रह किया। इस आग्रह पर एटीसी गुजरांवाला ने मामला एटीसी गुजरात स्थानांतरित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई की तारीख एटीसी गुजरात तय करेगी।' आतंक रोधी अदालत ने सीटीडी को बुधवार को सईद के खिलाफ पूर्ण चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था।

सईद पर 23 मामले दर्ज : पंजाब प्रांत की पुलिस के सीटीडी ने गत तीन जुलाई को सूबे के कई शहरों में सईद और उसके 12 साथियों के खिलाफ आतंकी फंडिंग के 23 मामले दर्ज किए थे।

हाफिज सईद। फाइल

अग्रिम जमानत लेने जाते वक्त हुई गिरफ्तारी : आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और जमात-उद-दावा के प्रमुख सईद को 17 जुलाई को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह अग्रिम जमानत लेने लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था। उसे लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में रखा गया है।

सईद पर 70 करोड़ का इनाम : वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। अमेरिका ने 2012 से उस पर एक करोड़ डॉलर (करीब 70 करोड़ रुपये) का इनाम रखा है। इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी।

कार्रवाई करने से ही एफएटीएफ सूची से बाहर हो पाएगा पाक : अमेरिका

इस्लामाबाद, आइएएनएस : अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की नसीहत दी है। अमेरिका ने कहा है कि आतंकी संगठनों और उनके सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस और संतोषजनक कदम उठाने के बाद ही दुनिया के ज्यादातर देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की निगरानी सूची से बाहर निकलने में पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं।

अमेरिका के इस बयान से एक दिन पहले ही इस्लामाबाद में तैनात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की प्रतिनिधि टेरीजा सांचेज ने कहा था कि अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट यानी निगरानी सूची से बाहर नहीं निकला तो हाल में स्वीकृत लोन खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान जून, 2018 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ की ग्रे सूची में है। डॉन अखबार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, गत जून में फ्लोरिडा में एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को जिन बिंदुओं पर काम करने को

प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की नसीहत दी

पेरिस में होगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक

पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा गया था। एफएटीएफ की 13 से 18 अक्टूबर तक पेरिस में होने वाली बैठक में इस बात पर गौर किया जाएगा कि पाकिस्तान इन बिंदुओं का पालन करने में खरा उतरा है या नहीं।

कहा गया था, उसकी प्रगति का स्वतंत्र आकलन करने के लिए अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल इस समय पाकिस्तान के दौरे पर है। दक्षिण और मध्य एशियाई मामले देखने वालीं कार्यवाहक उप विदेश सचिव एलिस जी वेल्स के नेतृत्व में आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री इमरान खान के वित्त मामलों के सलाहकार डॉ अब्दुल हफीज शेख से मुलाकात की।

जिहादियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा पाक

यूरोपीय शोधकर्ता ने खोली पोल कहा- जिहादी तत्वों को भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ कर रहा इस्तेमाल

ब्रसेल्स, एएनआइ : ऐसे में जब पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हाथ-पैर मार रहा है, तब यूरोप के एक शोधकर्ता ने उसकी कलई खोलकर रख दी है। शोधकर्ता डॉ. सेगफ्रेड ओ वॉल्फ ने कहा है कि पाकिस्तान अभी भी जिहादी तत्वों को भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।

डॉ. वॉल्फ साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के शोधकर्ता हैं। उन्होंने ब्रसेल्स में कहा, पाकिस्तान प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ अभी भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार आतंकी संगठनों के खिलाफ कुछ करना भी चाहे तो सेना के उच्च पदों और खुफिया संगठन आइएसआइ उसके प्रयासों को कमजोर कर देते हैं। डॉ. वॉल्फ के अनुसार जिहादी तत्वों का इतने प्रभावशाली हैं कि उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई पाकिस्तानी नेतृत्व के लिए खतरा बन सकती है। जिहादी चीन-पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरीडोर समेत कई बड़ी परियोजनाओं पर हमला कर सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।

हाल के वर्षों में आतंकी संगठनों ने अपना प्रभाव बढ़ाते हुए पाकिस्तानी राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिश की। लश्कर-ए-तैयबा ने अपना नाम बदलकर पार्टी बनाई और चुनाव में उम्मीदवार भी खड़े किए। लेकिन जनता ने

बड़ी परियोजनाओं के लिए भी खतरा बने रहे हैं जिहादी। प्रतीकात्मक

उन्हें खारिज कर दिया। आतंकी संगठनों का यह मंसूबा वास्तव में खतरनाक है। आने वाले दशकों में अगर वे सफल हो गए तो देश की बागडोर जिहादी तत्वों में हाथों में जाने का अंदेशा है। वे देश में कट्टरपंथी इस्लामी तौर-तरीके लागू कर सकते हैं। पाकिस्तान में धार्मिक अराजकता पैदा हो सकती है। तब जिहादी लोकतंत्र और सहमति के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर अराजक स्थिति पैदा कर सकते हैं।

पाक में बढ़े पोलियो के मामले पांच और मरीज सामने आए

मुल्क में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या, अब तक 53 केस मिल चुके हैं

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पांच और बच्चों में पोलियो वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। इनमें से एक तो महज 22 माह का है। स्थानीय अधिकारियों ने इसके लिए उन अभिभावकों को कसूरवार ठहराया है जो अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने से मना कर देते हैं।

पोलियो उन्मूलन अभियान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के केंद्रीय प्रतिनिधि बाबर बिन अट्टा ने बताया कि जो बच्चे पोलियो के शिकार हुए हैं उनमें से किसी ने भी पोलियो अभियान के दौरान वेक्सीन नहीं ली थी और ना ही उनका सामान्य टीकाकरण हुआ था। पिछले वर्षों के मुकाबले पाकिस्तान में इस साल पोलियो के मामलों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। मुल्क में इस साल अभी तक 53 मामले मिल चुके हैं, जबकि 2017 में आठ और 2018 में 12 मामले सामने आए थे। एशिया में पाकिस्तान के अलावा केवल अफगानिस्तान में ही पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में पोलियो के चार और मामले सामने आने आए थे। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है जो पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुख्य रूप से अपना निशाना बनाती है। इसका वायरस तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है जिससे लकवा मार सकता है या मौत भी हो सकती है। पोलियो का कोई इलाज नहीं है हालांकि बच्चों को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है। हर बार जब पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे को टीका लगाया जाता है, तो वायरस के खिलाफ उनकी सुरक्षा बढ़ जाती है। बार-बार के प्रतिरक्षण ने लाखों बच्चों को पोलियो से बचाया है, जिससे दुनिया के लगभग सभी देश पोलियो मुक्त हो गए हैं।

गोलीबारी की अफवाह से अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में मची भगदड़, कई घायल

न्यूयॉर्क, आइएएनएस/एपी : अमेरिका में गोलीबारी की दो बड़ी वारदातों के चलते दहशत का माहौल है। मंगलवार रात न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर इलाके में एक तेज आवाज सुनकर लोगों में भगदड़ मच गई। गोलीबारी की आशंका में लोग इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान कई महिलाएं गिर गईं और कुछ बच्चे घायल हो गए। कुछ डर से कांपने लगे। सूचना पाकर पुलिस और एंबुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। बाद में पता चला कि तेज आवाज किसी धमाके या गोलीबारी की नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल की थी।

न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने एक ट्वीट में कहा, 'टाइम्स स्क्वायर में कोई सक्रिय शूटर नहीं है। मोटरसाइकिल की तेज आवाज ऐसी थी, जैसे गोलियां चल रही हों। लोगों से अपील है कि घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम्स स्क्वायर का इलाका बेहद सुरक्षित है।' टाइम्स स्क्वायर इलाके में इस वाकये के वक्त बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग इधर-उधर भागने लगे। गोलीबारी की आशंका में कई लोग पास की दुकानों, रेस्तरां और होटलों में घुस गए। बीते सप्ताहांत टेक्सास के अल पासो और ओहायो के डेटन में गोलीबारी की घटनाओं में 31 लोगों की मौत हो गई थी।

पड़ोसी का आत्मघाती कदम

हताशा से भरा व्यक्ति कोई भी कदम उठा सकता है, चाहे उससे खुद का ही नुकसान क्यूं न हो जाए। पाकिस्तान भी इन दिनों इसी मन:स्थिति से जूझ रहा है। भारत ने जम्मू कश्मीर का जैसे विशेष दर्जा खत्म किया, पड़ोसी देश को मिर्ची लगने लगी। लिहाजा उसने अन्य कई कदमों के साथ भारत से कारोबारी रिश्ते भी खत्म कर लिए हैं। कुछ दिन पहले जिस कारोबारी रिश्तों की बढ़ावा देने की वह भारत से दुहाई दे रहा था, झल्लाहट और बौखलाहट में उसे खुद ही समाप्त कर दिया है। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, 'जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकी मति आगे हर लीन्हा।' अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पहले से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह कदम आत्मघाती साबित होगा। विभिन्न देशों और संस्थाओं से ऋण लेकर देश चला रहे पाकिस्तान की मति मारी गई है। कम से कम भारत से उसके व्यापार के आंकड़े तो यही कहानी कह रहे हैं।

स्रोत: भारतीय वाणिज्य मंत्रालय

पाकिस्तान से भारत के कारोबार की तस्वीर (लाख रुपये में)

विषय	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
निर्यात	135,211	1,428,653	1,222,235	1,239,710	1,442,651
वृद्धि (फीसद)	-	25.85	-14.45	1.43	16.37
भारत का कुल निर्यात	189,634,841	171,638,440	184,943,355	195,651,452	230,772,619
वृद्धि (फीसद)	-	-9.49	7.75	5.79	17.95
कुल निर्यात में हिस्सेदारी	0.60	0.83	0.66	0.63	0.63
आयात	304,066	288,450	304,877	315,030	347,648
वृद्धि (फीसद)	-	-5.14	5.69	3.33	10.35
भारत का कुल आयात	273,708,657	249,030,553	257,767,536	300,103,343	359,467,461
वृद्धि (फीसद)	-	-9.02	3.51	16.42	19.78
कुल आयात में हिस्सेदारी	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10
कुल कारोबार (% में)	1,439,278	1,717,103	1,527,112	1,554,740	1,790,299
वृद्धि (फीसद)	-	19.30	-11.06	1.81	15.15
भारत का कुल कारोबार	463,343,499	420,668,994	442,710,892	495,754,796	590,240,080
वृद्धि (फीसद में)	-	-9.21	5.24	11.98	19.06
हिस्सेदारी (फीसद में)	0.31	0.41	0.34	0.31	0.30
कारोबार संतुलन	831,144	1,140,203	917,358	924,680	1,095,003
भारत का कारोबार संतुलन	-84,073,816	-77,392,113	-72,824,181	-104,451,890	-128,694,841

अफगान पुलिस स्टेशन पर हमले में 14 की मौत

काबुल, रायटर : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक पुलिस स्टेशन पर बुधवार को विस्फोटकों से भरी कार से आत्मघाती हमला किया गया। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 145 घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है।

अफगानिस्तान के उप गृहमंत्री खोशाल सादात ने बताया कि हमले में मारे गए लोगों में चार पुलिसकर्मी और बाकी आम नागरिक थे। घायलों में 92 नागरिक हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी के अनुसार, धमाका उस समय किया गया जब विस्फोटकों से भरी एक कार पुलिस स्टेशन की जांच चौकी पर रोकी गई। धमाके के कारण आसमान में काले धुंए का गुबार छा गया। धमाके से पुलिस स्टेशन की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है और परिसर में खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी ने ट्विटर पर लिखा, 'तालिबान ने आत्मघाती हमले में फिर नागरिकों को निशाना बनाया। नतीजन कई निर्दोष मारे गए। उनके हमले से यह जाहिर होता है कि वे शांति के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं।'

तालिबान ने दी है हमलों की धमकी : तालिबान ने अफगानिस्तान में 28 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बहिष्कार की अपील की है। उसने एक दिन पहले यह धमकी भी दी थी कि वह चुनाव रैलियों पर हमले करेगा।

अमेरिका कर रहा शांति वार्ता : अफगानिस्तान में 18 साल से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता चल रही है। लेकिन इस वार्ता के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। दोनों पक्षों में इसी हफ्ते कतर की राजधानी दोहा में आठवें दौर की वार्ता शुरू हुई है।

अमेरिका से सुलझे मतभेद: इससे एक दिन पहले आतंकी संगठन तालिबान से जुड़े एक अधिकारी ने कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर चल रहे मतभेद सुलझा लिए गए हैं। तालिबान और अमेरिका के बीच अफगानिस्तान में शांति को लेकर खाड़ी देश कतर में आठवें दौर की वार्ता चल रही है। इस बीच शांति समझौते में रोड़ा बने सबसे अहम मसले पर सहमति बन जाने की खबर को अच्छा संकेत माना जा है। अमेरिका ने 18 साल से युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में शांति के लिए समझौता कराने की जिम्मेदारी अपने विशेष दूत जालमे खलीलजाद को दी है। पिछले एक साल में खलीलजाद ने तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ कई बार बातचीत की है। दोनों पक्ष अब तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। अमेरिका जहां अफगान सरकार को भी वार्ता में शामिल करने पर अड़ा है। वहीं, तालिबान पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर समझौता करना चाहता है।

काबुल में बुधवार को एक पुलिस स्टेशन पर विस्फोटकों से भरी कार से किए गए आत्मघाती हमले से इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। रायटर

वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिकी एनएसए पर लगाया जानलेवा हमला कराने का आरोप

ब्यूनस आयर्स, एएनआइ : वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। मादुरो ने दावा किया है कि पिछले साल उन पर हुए आत्मघाती हमले की साजिश बोल्टन ने ही रची थी। माना जा रहा है कि वेनेजुएला से जुड़ी सभी संपत्तियां फ्रीज करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के जवाब में मादुरो ने यह बयान दिया है।

सरकारी टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में मादुरो ने कहा, आत्मघाती हमले के एक साल बाद आज मेरे पास सुबूत हैं। जिनसे साबित होता है कि व्हाइट हाउस से बोल्टन के निर्देश पर ही यह हमला किया गया था। इसके पीछे आपराधिक सोच और हत्यारे का दिमाग रखने वाले बोल्टन ही हैं। मादुरो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बोल्टन की गतिविधियों की जांच करानी चाहिए। पिछले साल अगस्त में वेनेजुएला की राजधानी कराकस में एक सैनिक परेड के दौरान मादुरो पर हमले की कोशिश हुई थी। मादुरो जिस मंच से भाषण दे रहे थे, उसके पास ही कई ड्रोन में धमाके हुए थे। इस हमले में मादुरो को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा था लेकिन सात सैनिक घायल हो गए थे। तब मादुरो ने वेनेजुएला के दक्षिणपंथी विपक्ष, अमेरिका और कोलंबिया की सरकार पर इस हमले का आरोप लगाया था।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की फाइल फोटो। रायटर

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की फाइल फोटो। एएफपी

क्या है वेनेजुएला संकट : 2019 की शुरुआत में वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें पहले से सत्ताधारी निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए, लेकिन उन पर वोटों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा। चुनाव में मादुरो के सामने जुआन गुआदो थे। इससे पहले तक विश्व की राजनीति में उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वह खुद को राष्ट्रपति बताते हैं। चुनावी नतीजों के बाद मादुरो ने कुर्सी छोड़ने से इन्कार कर दिया, वहीं गुआदो का कहना है कि उनके पास अगला चुनाव न होने तक अंतरिम राष्ट्रपति बनने का संवैधानिक अधिकार है। गोआदो वही व्यक्ति हैं, पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के खिलाफ प्रदर्शन किया था। शावेज ने स्वयं मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था। वेनेजुएला आज जिस संकट से जूझ रहा है, उसमें मादुरो की विफल आर्थिक नीतियों का बड़ा हाथ है। अब एक तरफ मादुरो पर गद्दी छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मादुरो की सरकार नाजायज है और वह नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गुआदो को आधिकारिक रूप से वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं। अमेरिका मादुरो को पूर्व राष्ट्रपति बता रहा है और वेनेजुएला की सेना से भी गुआदो का समर्थन करने के लिए कह रहा है। ऐसे में मादुरो ने अमेरिका से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। 24 जनवरी को मादुरो ने वेनेजुएला में अमेरिका राजदूत को 72 घंटों के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा था।

स्टर्लिंग बायोटेक मामले में ईडी की याचिका खारिज

जासं, नई दिल्ली : गुजरात स्थित स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड से जुड़े 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक के मनी लांड्रिंग मामले में सह-आरोपित व उद्यमी की जमानत को रद करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

ईडी ने दिल्ली स्थित व्यवसायी गगन धवन और एक अन्य आरोपी रंजीत मलिक उर्फ जॉनी को जमानत देने वाले निचली अदालत के दो आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों को एजेंसी ने पहले राकेश चंद्रा के माध्यम से कथित तौर पर दिल्ली में एक कांग्रेस नेता के आवास पर 25 लाख रुपये भेजने के लिए गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति सुनील गौड़ की पीठ ने कहा कि अभियुक्तों को नियम व कानून के आधार पर ही जमानत मिली है और उन्हें राहत देने वाले आदेशों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।

सऊदी अरब ने पाकिस्तानी डॉक्टरों से देश छोड़ने को कहा

यूएई, कतर और बहरीन ने भी पाकिस्तानी डिग्री को किया अमान्य

पाकिस्तान में चल रही मेडिकल की पढ़ाई में प्रशिक्षण का नहीं है कोई प्रावधान

जेद्दा, प्रेट्र/आइएएनएस : पाकिस्तानी डॉक्टरों को सऊदी अरब की ओर से बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी डॉक्टरों की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (एमडी और एमएस) की मान्यता रद कर दी है और उनसे देश छोड़ने के लिए कह दिया है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें जबरन पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया जाएगा।

पाकिस्तान के डॉन अखबार के अनुसार सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान में चल रही मेडिकल की पढ़ाई में प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि डॉक्टरों के लिए प्रयोगात्मक प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। प्रशिक्षण के अभाव में डॉक्टर मरीजों के इलाज में अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं होते। सऊदी सरकार के इस फैसले से वहां कार्यरत सैकड़ों पाकिस्तानी डॉक्टर के प्रभावित होंगे। अखबार के अनुसार सऊदी अरब की सरकार के फैसले को स्वीकार करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर और बहरीन ने भी पाकिस्तान के मेडिकल डिग्रियों की मान्यता खत्म कर दी है। उल्लेखनीय है कि 2016 में सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इंटरव्यू के जरिये बड़ी संख्या में पाकिस्तानी डॉक्टरों की सऊदी अरब में काम करने के लिए भर्ती की थी। लेकिन उनकी डिग्री को अब अमान्य घोषित कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है।

एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी फिजीशियंस एंड सर्जंस पाकिस्तान के प्रवक्ता डॉ. असद नूर मिर्जा ने अरब देशों के फैसले को पाकिस्तानी डॉक्टरों के आघात बताया है। उन्होंने कहा कि सही स्थिति की जानकारी देने के लिए पाकिस्तान सरकार को जल्द ही उन देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए।

कैलास मानसरोवर यात्रियों को दिए गए वीजा : चीनी सूत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीन ने कैलास मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा दिए हैं। चीनी दूतावास के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ऐसी खबर थी कि चीन सरकार ने भारत द्वारा लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र बनाए जाने पर भारतीयों के एक समूह को वीजा देने में देरी की। चीनी दूतावास के एक सूत्र ने कहा, 'कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों को पहले की तरह चीनी वीजा दिया गया। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई।'

चीन के तिब्बत क्षेत्र में कैलास मानसरोवर की यात्रा को हिंदुओं में बड़ा पावन माना जाता है। हर साल सैंकड़ों भारतीय इस यात्रा पर जाते हैं। उन्हें दुर्गम रास्तों से ट्रैकिंग कर जाना होता है। मंगलवार को चीन ने लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के भारत के फैसले पर ऐतराज किया था और कहा था कि उसे कश्मीर की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता है। हालांकि, भारत ने चीन के ऐतराज को खारिज कर दिया है।

आतंकी ट्रेनिंग लेने जा रहे युवक से यूपी एटीएस कर रही पूछताछ

भारत-पाक के सीमावर्ती गांव के दो तस्करों ने आरोपित को दी थी शरण

सुरक्षा एजेंसियां कर रही तस्करों की तलाश

नवीन राजपूत/अमन देवगन, अजनाला/ अमृतसर : पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने जाते समय कंटीली तार के पास गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के शाहिल अली से पूछताछ करने के लिए उत्तर प्रदेश की एंटी टेरोरिस्ट स्क्वाड (एटीएस) बुधवार को अमृतसर पहुंच गई। अब एटीएस के साथ कई सुरक्षा एजेंसियां अमृतसर देहाती पुलिस के सीआइए स्टाफ में आरोपित से पूछताछ कर रही हैं।

देहाती पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि एटीएस के तीन अधिकारी बुधवार दोपहर सीआइए स्टाफ पहुंच चुके थे। वह आरोपित शाहिल अली के उत्तर प्रदेश स्थित गोंडा जिला के नारायणपुरा इदा गांव के परिवार की पूरी जानकारी क्रास चेक कर रहे हैं।

पता चला है कि शाहिल अली रविवार को ट्रेन से अमृतसर पहुंचा था। उसकी भारत-पाक सीमा से सटे गांव के दो तस्करों से लगातार बात चल रही थी। उन्हीं तस्करों ने शाहिल को कंटीली तार अवैध रूप से पार करवानी थी। पता लगाया जा रहा है कि दोनों भारतीय तस्कर पाकिस्तान में बैठे किन आतंकियों के संपर्क में हैं। पुलिस ने शाहिल अली से मिली डायरी और मोबाइल से कुछ नंबर बरामद किए हैं। उनमें पाकिस्तान व जम्मू-कश्मीर के लोगों के नाम भी शामिल हैं। बीएसएफ ने सोमवार रात घरिंडा थाना के अंतर्गत पड़ती बॉर्डर ऑब्जर्विंग पोस्ट (बीओपी) काहनगढ़ से शाहिल अली को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद बीएसएफ ने आरोपित को घरिंडा पुलिस के हवाले कर दिया। जब अमृतसर देहाती पुलिस के सीआइए स्टाफ ने आरोपित से पूछताछ की तो उसने कई जानकारियां दीं। जांच में सामने आया कि शाहिल के खालिस्तानी और जम्मू-कश्मीर के आतंकी संगठनों से संबंध हैं।

भारत-बांग्लादेश सीमा से फिर 307 मवेशी जब्त

जागरण संवाददाता, कोलकाता : पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा से बीएसएफ द्वारा पशुओं की जब्ती का सिलसिला लगातार जारी है। बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने मंगलवार मध्यरात्रि में अभियान चलाकर सीमावर्ती मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और नदिया जिले के विभिन्न स्थानों से बांग्लादेश में तस्करी किए जा रहे 307 मवेशियों को जब्त किया।

साउथ बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय की ओर से बुधवार को बताया गया कि मुर्शिदाबाद जिले के हारुडांगा सीमा चौकी पर तैनात जवानों ने तस्करों के एक समूह की संदिग्ध गतिविधि को देखा जो मवेशियों को गंगा नदी की धारा में गिराकर बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ पार्टी ने नावों की मदद से पीछा करते हुए गंगा नदी से 225 मवेशियों को जब्त किया। हालांकि तस्कर तैरकर भागने में सफल रहे। इसी तरह अन्य घटनाओं में जवानों ने पशु तस्करी के प्रयासों को विफल करते हुए 82 और मवेशियों को जब्त करने में सफलता हासिल की।

टी–20 की लय को वनडे में जारी रखने उतरेगी विराट सेना

नई शुरुआत ▶ वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज आज से

विश्व कप सेमीफाइनल में हार के बाद भारत का पहला वनडे मैच

प्रोविडेंस (गयाना), प्रेट्र : टी-20 सीरीज में वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करने के बाद भारत गुरुवार को यहां मेजबान टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में उतरेगा। भारतीय टीम की कोशिश टी-20 की सफलता को वनडे में भी जारी रखने की रहेगी। विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिल तोड़ने वाली हार के बाद यह भारत का इस प्रारूप में पहला मैच होगा।

धवन की वापसी : विश्व कप के दौरान चोटिल हुए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इस मैच के साथ वनडे प्रारूप में वापसी करेंगे। भारत की ओर से 130 मैचों में 17 शतक जड़ने वाले धवन एक बार फिर रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करते हुए दिखेंगे और ऐसे में लोकेश राहुल को चौथे नंबर पर उतरना पड़ सकता है। कप्तान विराट कोहली अपने पसंदीदा तीसरे नंबर पर उतरेंगे। केदार जाधव के पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने की उम्मीद है और यह इस पर निर्भर करेगा कि रिषभ पंत को किस क्रम पर उतारा जाता है। मध्य क्रम के एक अन्य स्थान के लिए दावेदारी मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर के बीच होगी। पांडे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए और समय आ गया है कि टीम प्रबंधन अय्यर को मौके देने पर विचार करे और देखे कि वह कैसा प्रदर्शन करते हैं।

वनडे में पदार्पण कर सकते हैं सैनी : वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज नवदीप सैनी वनडे में भी पदार्पण कर सकते हैं। एक सप्ताह के अंदर तीन टी-20 मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया जा सकता है। ऐसे में मुहम्मद शमी तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे, जबकि सैनी अपने वनडे करियर का पहला मैच खेल सकते हैं। विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिल तोड़ने वाली हार के बाद हालांकि विराट कोहली की टीम एकजुट होकर वापसी करने में सफल रही और हाल में संपन्न टी-20 सीरीज में वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया। विश्व कप 2019 में रिकॉर्ड पांच शतक जड़ने वाले रोहित 50 ओवर के प्रारूप में अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखने के इरादे से उतरेंगे। वेस्टइंडीज के सामने रोहित के सलामी जोड़ीदार धवन को रोकने की भी कड़ी चुनौती होगी, जो विश्व कप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ने के दौरान चोटिल होने के बाद इस प्रारूप में वापसी के लिए बेताब हैं।

कोहली देंगे जवाब : विश्व कप के दौरान अच्छी फॉर्म में रहे कोहली कुछ पूर्व खिलाड़ियों के उस समूह को जवाब देने के इरादे से उतरेंगे जिन्होंने सीमित ओवरों के प्रारूप में उनकी कप्तानी पर सवाल उठाए हैं। कोहली निराश हैं कि विश्व कप में दबदबा बनाने के बावजूद एक खराब मैच के कारण विश्व कप में टीम की उम्मीदें टूट गई। रिषभ पंत और क्रुणाल पांड्या जैसे युवा खिलाड़ियों के रनों और विकेटों ने कोहली को प्रभावित किया है। मेजबान टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में क्रुणाल को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था।

(बायें से) भारतीय खिलाड़ी नवदीप सैनी, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार व पंत। फाइल फोटो, प्रेट्र

टीमें इस प्रकार हैं

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्रा सिंह चहल, केदार जाधव, मुहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और नवदीप सैनी।

वेस्टइंडीज : जेसन होल्डर (कप्तान), क्रिस गेल, जॉन कैंपबेल, इविन लुइस, शाई होप, शिमरोन हेटमायर, निकोलस पूरन, रोस्टन चेज, फेबियान एलेन, कार्लोस ब्रेथवेट, कीमो पॉल, शेल्डन कॉटरेल, ओशाने थॉमस और केमार रोच।

मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी पर्याप्त नहीं था : पोलार्ड

प्रोविडेंस (गयाना), एएनआइ : वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने कहा कि भारत के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में उनकी पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकती थी। पोलार्ड ने मैच के बाद कहा, 'मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की, लेकिन मेरा प्रदर्शन भी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था।' पोलार्ड ने 45 गेंदों में 58 रन बनाए थे और उनकी पारी की मदद से टीम 146 के स्कोर तक पहुंच पाई थी। पोलार्ड का भारत के खिलाफ तीसरे टी-20 अर्धशतक सात साल बाद इस प्रारूप में अपनी टीम के लिए कोई अर्धशतक था। उन्होंने कहा, 'हमें कुछ जगहों पर काम करने की जरूरत है। हम लगातार स्ट्राइक नहीं बदल पाए। अगर आप दोनों टीमों की बाउंड्री को देखें तो उसमें हम आगे थे। आपको अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता होना चाहिए। हम कभी-कभी अपनी ताकत पर खेलते हैं और अपनी कमजोरी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ईमानदारी से कहूं तो हम 2020 विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं। हमें यहां आगामी सीरीज में कुछ मैच जीतने हैं।' जब टीम की कप्तानी का जिम्मा संभालने को लेकर पोलार्ड से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह चीज पूछने के लिए वह सही व्यक्ति नहीं है और वह मैदान पर सिर्फ अपना अच्छा करना चाहते हैं।'

दीपक चाहर से प्रभावित हुए कप्तान कोहली

▶ कहा, तेज गेंदबाज दीपक ने नई गेंद से शानदार स्विंग गेंदबाजी की

▶ विराट ने की दीपक के चचेरे भाई राहुल चाहर की भी तारीफ

प्रोविडेंस (गयाना), प्रेट्र : भारत के कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले चाहर बंधुओं की तारीफ करते हुए कहा कि दीपक चाहर ने नई गेंद से शानदार स्विंग गेंदबाजी का नमूना पेश किया, जबकि राहुल चाहर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

दीपक ने पहले स्पैल में तीन ओवर में चार रन देकर तीन विकेट लिए। वेस्टइंडीज की टीम ने छह विकेट पर 146 रन बनाए। राहुल ने 27 रन देकर एक विकेट लिया। कोहली ने कहा, 'हम कुछ खिलाड़ियों को आजमाना चाहते थे। हमने चाहर बंधुओं को मौका दिया। राहुल का यह पहला मैच था, जबकि दीपक ने वापसी की। राहुल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। पिच से गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही थी। आसमान में बादल थे, लेकिन दीपक ने स्विंग गेंदबाजी से तीन विकेट लेकर वेस्टइंडीज पर दबाव बनाया और वे बड़ा स्कोर नहीं बना सके।' कोहली ने भुवनेश्वर कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें कुशल गेंदबाज बताया, लेकिन कहा कि वह सबसे ज्यादा दीपक के प्रदर्शन से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, 'भुवनेश्वर ने शुरुआती दबाव बनाया। वह हमेशा पेशेवर प्रदर्शन करते हैं और काफी हुनरमंद गेंदबाज हैं। मैं हालांकि दीपक से काफी प्रभावित हुआ। हमारी टीम के लिए यह अच्छा दिन था।'

जीत के लिए 147 रन के लक्ष्य के जवाब में कोहली ने 45 गेंदों में 59 रन बनाए। कोहली ने अपनी पारी के बारे में कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत है। मैं अपना काम करता हूं। मैं अपने लिए नहीं खेलता। मैं इसी तरह पिछले 11 साल से खेल रहा हूं और मुझ पर कोई दबाव नहीं है।' भारतीय टीम विश्व कप में सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी। कोहली ने कहा कि 2023 विश्व कप में अभी समय है और उनकी टीम का लक्ष्य लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है। उन्होंने कहा, 'अभी 2023 में समय है। हमारी प्राथमिकता दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम बनना है। पिछले तीन चार साल में हम ऐसा कर सके हैं और दुनिया की दूसरे नंबर की टीम बने हैं। हम जल्दी ही नंबर एक भी बनेंगे।'

पंत को समय देना होगा : कोहली युवा विकेटकीपर पंत पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहते और उन्होंने कहा कि वह भविष्य के खिलाड़ी हैं जिसे अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए समय दिए जाने की जरूरत है। 21 वर्षीय पंत भविष्य में महेंद्र सिंह धौनी की जगह भारतीय टीम के विकेटकीपर होंगे। धौनी सीमित प्रारूप से संन्यास ले सकते हैं और भविष्य को देखते हुए पंत को तैयार किया जा रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दो टी-20 मैचों में उनके शॉट चयन की आलोचना हुई थी लेकिन तीसरे टी-20 में उन्होंने 42 गेंद में नाबाद 65 रन बनाए। कोहली ने कहा, 'हम पंत को भविष्य के रूप में देख रहे हैं। उनके पास क्षमता है और प्रतिभा भी है। उन पर दबाव बनाने की बजाय उन्हें समय देने की जरूरत है। वह जल्दी ही फिनिशर की भूमिका निभाने लगेंगे। उसके प्रदर्शन में काफी निखार आया है। इस तरह के मैचों को जिताना अहम है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दबाव को अलग तरह से लिया जाता है। यदि वह इस तरह नियमित रूप से खेलते रहे तो भारत के स्टार साबित होंगे।'

सीनियर खिलाड़ियों के समर्थन से मदद मिली : रिषभ पंत

प्रोविडेंस (गयाना) : विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत कभी-कभी रन नहीं बना पाने के कारण 'निराश' हो जाते हैं, लेकिन भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों के समर्थन से उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। पंत ने 'बीसीसीआइ.टीवी' के लिए उप कप्तान रोहित शर्मा से कहा, 'मैंने अपनी पारी के बारे में अच्छी चीजें सुनी। मैं रन नहीं बना पा रहा था और हताश हो रहा था। लेकिन, मैं अपनी प्रक्रिया पर कायम रहा और इससे अच्छे नतीजे मिले। कई बार ऐसा समय आया जब रन नहीं बना पाने के कारण मैं हताश हो गया।

इसके बाद मैंने सोचा कि प्रदर्शन करने के लिए मैं क्या अलग कर सकता हूं। ऐसा समय भी आया जब मैंने सही फैसले किए और तब भी प्रदर्शन नहीं कर पाया। क्रिकेट में ऐसा होता है और यह खेल का हिस्सा है। लेकिन, मैं हमेशा अपने बेसिक्स पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं, अपने अंदर की आवाज सुनता हूं और प्रक्रिया का पालन करता हूं।' कोहली के साथ 106 रन की साझेदारी के बारे में पूछे पर पंत ने कहा, 'जब मैं और विराट खेल रहे थे तो हम बड़ी साझेदारी के बारे में सोच रहे थे और फिर अंतिम सात-आठ ओवर में तेजी से रन बनाते।'

बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि वह अपेक्षाओं के दबाव में नहीं आते। उन्होंने कहा, 'मैं कभी-कभी दबाव महसूस करता हूं, कभी-कभी इसका लुत्फ उठाता हूं। लेकिन, पूरी टीम, विशेषकर सीनियर खिलाड़ियों का मुझ पर भरोसा है और इससे काफी मनोबल बढ़ता है। आपको पता है कि एक या दो पारियों में विफल होने के बावजूद टीम आपका साथ देगी। इससे मदद मिलती है।'

भगवान भारतीय क्रिकेट की मदद करे : सौरव गांगुली

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने राहुल द्रविड़ को हितों के टकराव के मुद्दे पर भेजे गए नोटिस पर बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की आलोचना की। बीसीसीआइ के लोकपाल और नैतिक अधिकारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) डीके जैन ने मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता की शिकायत पर द्रविड़ को नोटिस जारी किया था।

गांगुली ने ट्वीट किया, 'भारतीय क्रिकेट में नया फैशन है हितों का टकराव, खबरों में बने रहने का सबसे अच्छा तरीका है। भगवान भारतीय क्रिकेट की मदद करे। द्रविड़ को हितों के टकराव मामले में नोटिस मिला है।' वहीं, भ्हरभजन सिंह ने ट्वीट किया, 'वास्तव में मुझे पता नहीं यह कहां जा रहा है। आप भारतीय क्रिकेट में उनसे बेहतर व्यक्ति नहीं देख सकते। ऐसे महान खिलाड़ी को नोटिस भेजना उन्हें अपमानित करने जैसा है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। हां, भारतीय क्रिकेट को भगवान ही बचाए।' बीसीसीआइ के एक सीनियर अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की थी और कहा था कि गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि द्रविड़ जो हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट संचालन प्रमुख थे, वह इंडिया सीमेंट्स के उपाध्यक्ष भी हैं।

सौरव गांगुली। फाइल फोटो, प्रेट्र

राज्यों के मताधिकार के फैसले का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को : वकील

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने सोमवार को कहा था कि 26 राज्य संघ बीसीसीआइ के नए संविधान को पूरी तरह अपना चुके हैं और इन्होंने चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर लिए हैं। चार संघों ने हालांकि अभी चुनाव अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। राय ने यह भी कहा कि संविधान के किसी भी नियम का उल्लंघन राज्य संघों को चुनाव से अयोग्य कर देगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और राज्य संघों का कहना है कि यह निर्णय लेना सीओए का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है।

राज्य संघों के वकील अनमोल चिंताले ने साफ कर दिया कि जहां तक राज्य संघों की बात है तो यह निर्णय लेना कि किसी राज्य संघ ने नए संविधान के नियमों का पालन किया है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि सीओए के अधिकार क्षेत्र में। सीओए को यह काम दिया गया है कि वह कोर्ट को बताए कि कितने राज्य संघों ने बीसीसीआइ के संविधान का पालन किया है।

अनमोल ने कहा कि बीसीसीआइ के नए संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य संघों को अपने संविधान को बीसीसीआइ के संविधान के आधार पर ही बनाना होगा। वहीं, बीसीसीआइ के वकील गुंजन ऋषि ने कहा कि सीओए ने तमाम शंकाओं के बीच यह अर्थ लगा लिया कि राज्य संघ सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए गए संविधान के आधार पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है।

भाई के प्रदर्शन पर हार्दिक पांड्या ने कहा आप पर गर्व है

नई दिल्ली, जेएनएन : भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने बड़े भाई और टीम इंडिया के सदस्य क्रुणाल पांड्या को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। क्रुणाल अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर मैन ऑफ द सीरीज बने थे। हार्दिक ने ट्विटर पर लिखा, 'बधाई टीम इंडिया। शानदार प्रदर्शन और मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार के लिए बधाई क्रुणाल पांड्या। बिग ब्रो, आप पर बहुत गर्व है।' हार्दिक को इस सीरीज से आराम दिया गया है क्योंकि वह पिछले तीन महीनों से लगातार खेल रहे हैं। हालांकि उनका वनडे विश्व कप 2019 में प्रदर्शन खास नहीं रहा था और उनके दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में खेलने की उम्मीद है। वहीं, क्रुणाल ने बुधवार को ट्वीट किया, 'एक यादगार सीरीज। सभी का समर्थन के लिए शुक्रिया।'

वेस्टइंडीज की तुलना में भारत ने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया

वीवीएस लक्ष्मण
वेरी-वेरी स्पेशल

ज्यादातर क्रिकेट प्रेमियों की तरह मैंने भी टी-20 में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद जताई थी, लेकिन यह काफी हद तक एकतरफा रहा, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में भारत ने राज किया। भारत ने वेस्टइंडीज की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया, जिन्हें हाल के दिनों में परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजना को पूरा करना मुश्किल हुआ है।

तीनों मैचों के लिए पिचें बिलकुल सपाट नहीं थीं और शॉट खेलने के लिए अनुकूल थीं। इसका मतलब था कि कैरेबियाई टीम को अपने प्राकृतिक स्वभाव पर लगाम लगाना पड़ा। भारत से ठीक विपरीत उसके पास विवेक का अभाव था, जिसकी व्यापक पुष्टि 3-0 की स्कोर लाइन करती है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी भारत के युवा, कम अनुभवी खिलाड़ियों की सफलता, विशेषकर गेंदबाजी विभाग को देखकर हुई। मैन ऑफ द मैच पुरस्कार नवदीप सैनी, क्रुणाल पांड्या और दीपक चाहर को दिए गए, जो भारतीय प्रणाली के लिए वसीयत की तरह है जिससे खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की कड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। सबसे खुशी की बात यह है कि इन खिलाड़ियों ने खुद पर विश्वास किया और अपनी ताकत से खेले। सैनी एक तेज गति के गेंदबाज हैं और ठीक उसी तरह से उन्होंने गेंदबाजी की।

दीपक चाहर स्विंग के माहिर गेंदबाज हैं और तीसरे मैच में उनकी सफलता स्विंग की वजह से ही देखने को मिली। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मौजूदा दौर के चालाक गेंदबाज हैं, जो अपने बल-बूते मैच को पक्ष में करने के बारे में सोचने में सक्षम हैं। मैं उन्हें 50 ओवरों की क्रिकेट में और अधिक अवसर मिलते देखना चाहूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि वह छठे क्रम पर सही विकल्प साबित हो सकते हैं और 10 ओवरों का कोटा भी पूरा कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह या भुवनेश्वर कुमार पर हर समय भरोसा करना उचित या बुद्धिमानी नहीं है। इस सीरीज ने यह साबित कर दिया है कि भारत के पास गेंदबाजी में कई अन्य हथियार हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों को अधिक खेल खेलने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी भूमिकाओं को समझ सकें और सहज बन सकें।

अन्य युवा खिलाड़ियों में रिषभ पंत भी हैं जो शाबाशी के हकदार हैं। आप उम्मीद करते हैं कि रोहित और विराट रन बनाएंगे, लेकिन पंत ने अपनी पहले की गलतियों से सीख ली और अंतिम मुकाबले में बहुत ही परिपक्वता दिखाई। हालांकि उन्होंने फिर भी अपना बेधड़क खेल दिखाया लेकिन उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और अपने मजबूत आयाम पर भरोसा करते हुए जोखिम को कम किया। सीखने की इच्छा, बेहतर करने की इच्छा और प्रदर्शन करने की भूख, ये वह चीजें हैं जो आप युवाओं में देखना चाहते हैं। भारतीय क्रिकेट के लिए ये बेहतरीन बदलाव हैं क्योंकि धीरे-धीरे ऑस्ट्रेलिया में अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोच आर्थर का करार नहीं बढ़ाएगा

लाहौर, प्रेट्र : विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बुधवार को कहा कि मुख्य कोच मिकी आर्थर और उनके सहयोगी स्टाफ का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। पीसीबी ने आर्थर, बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर, गेंदबाजी कोच अजहर महमूद और ट्रेनर ग्रांट लुडेन के अनुबंध नहीं बढ़ाने का फैसला लेते हुए कहा कि बेहतर प्रक्रिया से नियुक्तियां की जाएंगी। पीसीबी की क्रिकेट समिति की हुई बैठक में यह फैसले लिए गए। पाकिस्तान विश्व कप में नॉकआउट चरण में भी नहीं पहुंच सका था। बोर्ड ने कहा, 'पीसीबी अब चारों पदों के लिए विज्ञापन देगा और उच्च स्तर पर आवेदन मंगवाएगा।' पीसीबी अध्यक्ष अहसान मनी ने कहा, 'समिति ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है और उसका मानना है कि अब नए सिरे से आगाज करना होगा। हम उन सभी को हटा देंगे। पीसीबी की ओर से मैं आर्थर, ग्रांट फ्लावर, ग्रांट लुडेन और अजहर महमूद को धन्यवाद देता हूं। उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं।'

क्रिकेट डायरी

अकमल ने मैच फिक्सिंग को लेकर मंसूर पर आरोप लगाया

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान के विवादास्पद बल्लेबाज उमर अकमल ने पूर्व टेस्ट खिलाड़ी मंसूर अख्तर पर ग्लोबल टी-20 कनाडा लीग के दौरान भ्रष्ट कार्यों में लिप्त होने की पेशकश करने का आरोप लगाया और इस मामले की जानकारी पीसीबी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई को दी। पीसीबी के सूत्रों के अनुसार, कुछ दिन पहले उमर ने इस मामले की रिपोर्ट आयोजकों और पीसीबी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई को कर दी थी। वह ग्लोबल टी-20 कनाडा लीग में विनिपेग हॉक्स फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। अकमल ने कहा कि अख्तर विनिपेग हॉक्स प्रबंधन का हिस्सा थे और उन्होंने लीग के कुछ मैचों को फिक्स करने में भूमिका निभाने के लिए पूछा था। अख्तर 1980 और 1990 के बीच 19 टेस्ट और 41 वनडे खेल चुके हैं।

फोर्ब्स की सूची में पीवी सिंधू सर्वाधिक कमाई वाली इकलौती भारतीय महिला

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में इकलौती भारतीय हैं। इस सूची में अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स शीर्ष पर हैं। सिंधू 5.5 मिलियन डॉलर (करीब 39 करोड़ रुपये) की कुल कमाई के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की 2019 की सूची में संयुक्त रूप से 13वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक, सिंधू भारत की कमाई करने वाली अग्रणी खिलाड़ी बनी हुई हैं। 2018 में वह बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं।

सेरेना 29.2 मिलियन (करीब दो अरब सात करोड़ रुपये) की कमाई के साथ 15 खिलाड़ियों की सूची में सबसे आगे हैं। फोर्ब्स ने कहा कि 37 वर्षीय विलियम्स ने कम से कम अगले साल तक खेलने की योजना बना रखी है, लेकिन वह पहले ही एस बाय सेरेना के नाम से कपड़ों के बाजार में उतर चुकी हैं और 2020 तक वह जूलरी और सौंदर्य उत्पादों को भी लांच करेंगी।

इस फेहरिस्त में जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने सेरेना को हराकर 2018 के यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया था। ओसाका की कुल कमाई 24.3 मिलियन डॉलर (करीब एक अरब 72 करोड़ रुपये है। फोर्ब्स ने कहा कि खिलाड़ियों की जून 2018 से 2019 तक की कमाई में उनकी इनामी राशि, सैलरी, विज्ञापन और उपस्थिति शुल्क शामिल हैं। इस सूची में उन महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनकी कमाई कम से कम पांच मिलियन डॉलर है। अगर इतनी कमाई के लिहाज से पुरुष खिलाड़ियों पर नजर डालें, तो पांच मिलियन डॉलर की कमाई करने के आंकड़े तक इस साल 1300 से ज्यादा पुरुष खिलाड़ी पहुंच जाएंगे।

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शीर्ष 15 महिला खिलाड़ियों की तुलना करें तो पिछले साल के 130 मिलियन डॉलर (नौ अरब 23 करोड़ रुपये) के मुकाबले यह आंकड़ा इस साल 146 मिलियन डॉलर (करीब 10 अरब 37 करोड़ रुपये) पहुंच गया। महिला खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में सेरेना और ओसाका की कुल कमाई तीसरे स्थान पर काबिज एंजिलिक कर्बर से दोगुनी से ज्यादा है। टेनिस स्टार कर्बर ने 11.8 मिलियन डॉलर (83 करोड़ 80 लाख) कमाई की।

पीवी सिंधू। फाइल फोटो, प्रेट्र

फुटबॉल डायरी

ईपीएल के नए सत्र की शुरुआत शुक्रवार से, मौजूदा चैंपियन सिटी और यूरोपियन चैंपियन होंगे खिताबी दौड़ में आगे

सिटी और लिवरपूल खिताबी रोमांच में गोता लगाने को तैयार

लंदन, एएफपी : इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) का रोमांच इस सप्ताह के अंत से शुरू होने जा रहा है, जहां पिछले दो बार के चैंपियन मैनचेस्टर सिटी अपने ईपीएल खिताब की रक्षा के लिए तैयार है। हालांकि, लिवरपूल फुटबॉल क्लब की खिताबी जीत की ज्वलंत इच्छा इस खिताबी रोमांच की आग में तेल डालने का काम करेगी।

पिछले सत्र में तीन घरेलू खिताब जीतने वाली सिटी की टीम जबर्दस्त फॉर्म में है और यह क्लब फिलहाल अपने दबदबे का उसी तरह लुत्फ उठा रहा है जैसा मैनचेस्टर युनाइटेड ने 2007 से 2009 के बीच उठाया था। उधर, यूरोपियन चैंपियन लिवरपूल 1990 के बाद पहला ईपीएल खिताब जीतने की कोशिश में जुटा हुआ है जिसे पिछले सत्र में मैनेजर पेप गॉर्डियोला की सिटी ने सत्र के आखिरी दिन तक चले खिताबी रोमांच में महज एक अंक से पछाड़ा था। इस सप्ताह शुक्रवार को ईपीएल के पहले मुकाबले में जुर्जेन क्लॉप की लिवरपूल का सामना प्रमोट हुए नॉर्विक से एनफील्ड में होगा। वहीं सिटी की टीम शनिवार को वेस्टहम के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

सिटी और लिवरपूल के बीच प्रतिद्वंद्वता की एक झलक रविवार को कम्यूनिटी शील्ड के दौरान देखने को मिली, जहां निर्धारित समय तक दोनों टीमों के 1-1 से बराबर रहने के बाद सिटी ने पेनाल्टी शूटआउट में बाजी मारी। सिटी ने अब तक कभी भी चैंपियंस लीग खिताब नहीं जीता है, जबकि उसके मैनेजर गॉर्डियोला ने पिछली बार 2011 में बार्सिलोना के साथ यूरोपियन चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। हालांकि, गॉर्डियोला ने कहा कि शरीर को स्वस्थ्य रखने और टीम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारे लिए सबसे अहम चीज प्रीमियर लीग खिताब ही है।

युनाइटेड पर होंगी निगाहें : मैनेजर ओले गनर सोल्सकजेर की मैनचेस्टर युनाइटेड की टीम पर भी निगाहें होंगी, जिसने दुनिया के सबसे महंगे डिफेंडर के तौर पर हैरी मैग्यूरे से करार किया है। हालांकि, इस सत्र में टॉटनहम ने उसके मैनेजर मॉरिसियो पोचेटिनो को प्रसन्न करने के लिए नए खिलाड़ियों पर कुछ खास खर्च नहीं किया है। उधर, ईडन हैजार्ड के जाने के बाद अब चेल्सी पर अपने नए मैनेजर फ्रैंक लैंपार्ड के मार्गदर्शन में ट्रांसफर प्रतिबंध के बीच अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा।

लिवरपूल के मैनेजर जुर्जेन क्लोप और मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गॉर्डियोला। फाइल फोटो, एएफपी

फिर हुई बेल की अनदेखी

मैड्रिड, एएफपी : रीयल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी गेरेथ बेल की एकबार फिर स्पेनिश क्लब के मैनेजर जिनेदिन जिदान ने अनदेखी की और उन्हें बुधवार को रेड बुल सल्जबर्ग के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए अपनी टीम से बाहर रखा। बेल अब तक पांच प्री सीजन मुकाबलों में से केवल दो में उतर पाए हैं। इस दौरान वह आर्सेनल और एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ स्थानापन्न के तौर पर उतरे, लेकिन उसके बाद उन्हें लगातार तीसरे मैच में पूरी तरह से टीम से बाहर रखा गया। बेल के क्लब को छोड़ने की खबरें काफी समय से चल रही हैं और जिदान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह उनकी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। ऑस्ट्रिया में होने वाले इस मैच से रॉड्रिगेज और मैरियानो को भी रीयल की टीम से बाहर रखा गया। इन दोनों के क्लब को छोड़ने की संभावना जताई जा रही है।

साथ काम करें आइ लीग क्लब –एआइएफएफ : फीफा

नई दिल्ली, प्रेट्र : विश्व फुटबॉल की शीर्ष संस्थान फीफा ने भारतीय फुटबॉल के विकास के लिए आइ लीग क्लबों को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है। आइएसएल को भारत की शीर्ष लीग बनाने के मुद्दे पर महासंघ और आइ क्लबों के बीच में लंबे सयम से विवाद चल रहा है जिसको सुलझाने को लेकर आइ लीग चैंपियन मिनर्वा पंजाब सहित छह क्लबों ने फीफा से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। फीफा के कार्यवाहक उपमहासचिव मैटियास ग्रैफस्ट्रॉम ने मिनर्वा पंजाब के निदेशक रंजीत बजाज को पत्र लिखा है और अन्य आइ लीग क्लबों को भी महासंघ के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा। ग्रैफस्ट्रॉम ने लिखा, 2018 में की गई समीक्षा ने कई जटिल मुद्दों को उजागर किया, जिन्हें सुलझाने के लिए सभी हितधारकों को साथ लेकर चलते हुए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। सिफारिशों के कई पहलू हैं जिन्हें लागू करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है।

सविता बोलीं, टीम के डिफेंस को करना होगा अच्छा प्रदर्शन

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान सविता ने बुधवार को कहा कि टोक्यो में 17 से 21 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक टेस्ट इवेंट में ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों को हराने के लिए उन्हें डिफेंस में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

एफआइएच रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज भारतीय महिला टीम को दुनिया की दूसरे नंबर की टीम और तीन बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, 11वीं रैंकिंग वाली चीन और 14वीं रैंकिंग पर काबिज मेजबान जापान से खेलना होगा। सविता ने कहा, 'हम पिछले साल गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। हम एक गोल से हार गए थे और वह टूर्नामेंट का सेमीफाइनल था। हमें हालांकि, अपने प्रदर्शन पर गर्व है। इस बार हमें एक इकाई के रूप में डिफेंस में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मुझे लगता है कि डिफेंस ही जीत की कुंजी साबित होगा।' भारत के लिए 193 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली सविता ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी काफी समय से साथ खेल रहे हैं और उनका आपसी तालमेल अच्छा है।

दिल्ली में दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसेलर की सूची जारी

सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ कार्यक्रम का आगाज, कथा, कथेतर, कविता और अनुवाद समेत चार श्रेणियों में जारी हुई सूची

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसेलर के तीसरे साल की पहली तिमाही की सूची बुधवार को यहां जारी हो गई। लेखक व स्तंभकार प्रो. पुष्पेश पंत व दैनिक जागरण के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ब्रांड एंड स्ट्रेटजी बसंत राठौर ने सूची का अनावरण किया।

रविंद्र भवन स्थित साहित्य अकादमी सभागार में दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसेलर की सूची जारी करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई।

इसके बाद भारतीय भाषा और अनुवाद विषय पर परिचर्चा हुई। इसमें लेखक पुष्पेश पंत, प्रकाशक नीता गुप्ता और कथाकार एवं अनुवादक प्रभात रंजन शामिल हुए। प्रभात रंजन ने नमिता गोखले की किताब के हिंदी अनुवाद राग पहाड़ी के लिए पंत को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें किताब बेहतरीन लगी। उन्होंने नीता गुप्ता से पूछा कि वे नमिता गोखले और पुष्पेश पंत की किताबों को किस नजरिये से देखती हैं? क्या अंतर पाती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी कि किताब है वह नमिता की है, जो हिंदी की है वह पुष्पेश पंत की है। पुष्पेश पंत ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस पर और समय देना चाहिए था। उन्होंने अनुवादक का संपादकीय टीम के जुड़ने पर अनुवाद के और सजीव होने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब भारतीय भाषाओं में लिखी किताबों का हिंदी अनुवाद पढ़ने को मिलेगा और वो बेस्टसेलर की सूची में शामिल होगा। अंग्रेजी किताबों को बेस्टसेलर बनाने के लिए बड़े जोर शोर से विज्ञापन द्वारा माहौल बनाया जाता है हिंदी के लिए वही माहौल दैनिक जागरण बड़ी संजीदगी से बिना शोर-शराबे के बना रहा है। इस पहल के लिए दैनिक जागरण बधाई का पात्र है। यह जागरण के बेस्टसेलर सूची जारी करने का ही परिणाम है कि अब हिंदी की बेस्टसेलर किताबें एयरपोर्ट समेत अन्य जगहों पर भी दिखाई देती हैं।

परिचर्चा के दौरान यह भी सवाल उठा कि क्यों उन्हीं किताबों का हिंदी अनुवाद के लिए चयन किया जाता है जिनकी अंग्रेजी में चर्चा ज्यादा होती है। इस पर प्रकाशक नीता गुप्ता ने कहा कि ये एक तरह से सेफ प्लेस होता है। चूंकि इन किताबों की पहले ही चर्चा हो चुकी होती है। इससे एक बड़ा मार्केट मिल जाता है। उन्होंने कहा कि हमने विदेशी भाषाओं के कई नामीगिरामी लेखकों की किताबों का हिंदी में अनुवाद कराया। इनकी चर्चा तो हुई, लेकिन अपेक्षित खरीदार नहीं मिले। बाद में जब हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया गया तो हमें पता चला कि मार्केट है।

पुष्पेश पंत ने कहा कि जागरण अकेले ही बेस्टसेलर माहौल बना रहा है। अखबारों में किताबों की सूची, उनके बारे में आर्टिकल आदि से पाठक पढ़ने का मन बनाता है। उन्होंने इस पहल के लिए दैनिक जागरण की सराहना की।

साहित्य अकादमी सभागार में दैनिक जागरण के हिंदी बेस्टसेलर के तीसरे साल की पहली तिमाही की सूचियों की घोषणा करते लेखक प्रो पुष्पेश पंत व दैनिक जागरण के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (ब्रांड एंड स्ट्रेटेजी) बसंत राठौर ● जागरण

दैनिक जागरण के हिंदी बेस्टसेलर की सूचियों की घोषणा के अवसर पर आयोजित परिचर्चा में भारतीय भाषा व अनुवाद विषय पर बात करते लेखक प्रो पुष्पेश पंत (दाएं), अनुवादक प्रभात रंजन व प्रकाशक नीता गुप्ता ● जागरण

1 द गर्ल इन रूम नंबर 105

लेखक : चेतन भगत
अनुवाद : सुशोभित सक्तावत
प्रकाशक : वेस्टलैंड बुक्स
केशव और जारा की प्रेम कहानी है जिसमें ब्रेकअप होता है, चार साल तक अलगाव चलता है। बाद में अपने जन्मदिन से पहले जारा केशव को बुलाती है। फिर बदल जाती है उसकी जिंदगी।

2 मेरी जीवन यात्रा

लेखक : एपी जे अब्दुल कलाम,
अनुवाद : सुरेश साहिल,
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन
रामेश्वर में पैदा होने से लेकर देश के ग्यारहवें राष्ट्रपति बनने तक डॉ कलाम का जीवन असाधारण संकल्प शक्ति, साहस, लगन और श्रेष्ठता की चाह की प्रेरणादायक कहानी है।

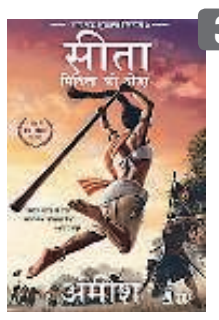

3 सीता-मिथिला की योद्धा

लेखक : अमीश त्रिपाठी
अनुवाद : उर्मिला गुप्ता
प्रकाशक : वेस्टलैंड बुक्स
राम से स्वयंवर के पहले और फिर रावण के साथ युद्ध के पहले सीता के साथ राम का संवाद, बेहद दिलचस्प है। सीता को एक योद्धा के तौर पर पेश करने के क्रम में अमीश ने उत्तर आधुनिक भाषा का प्रयोग किया है।

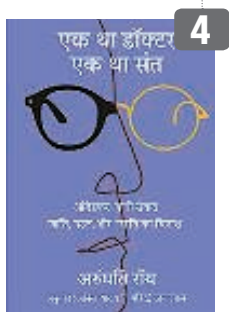

4 एक था डॉक्टर, एक था संत

लेखिका : अरुंधति राय
अनुवाद : अनिल यादव 'जय हिंद'
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन
किताब गांधी और आंबेडकर पर केंद्रित है। उनका मानना है कि समकालीन भारत में असमानता को समझने के लिए और उससे निपटने के लिए राजनीतिक विकास और गांधी के प्रभाव को समझना होगा।

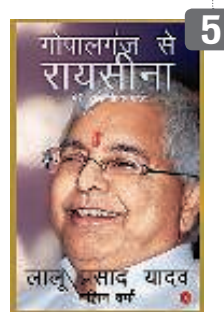

5 गोपालगंज से रायसीना

लेखक : लालू प्रसाद यादव,
अनुवाद : लालू प्रसाद यादव
प्रकाशक : रूपा पब्लिकेशंस
लालू यादव भारतीय राजनीति में अपनी तरह के अकेले राजनेता हैं। अपनी इस किताब में उन्होंने अपने जन्मस्थान से लेकर दिल्ली आने की कहानी दिलचस्प तरीके से कही है।

6 इक्ष्वाकु के वंशज

लेखक : अमीश त्रिपाठी
अनुवाद : उर्मिला गुप्ता
प्रकाशक : वेस्टलैंड बुक्स
क्या राम अपने पर लग रहे लांक्षणों से उबर पाएंगें, क्या विष्णु की नियति पर खरे उतर पाएंगे, क्या सीता के प्रति उनका प्यार संघर्षों के दौरान उनको थाम लेगा। इस किताब में लेखक इन्हीं सवालों के उत्तर ढूंढते हैं।

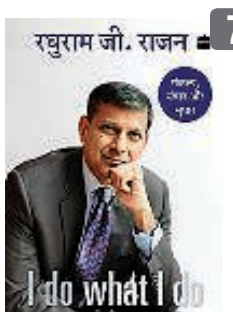

7 आई डू व्हाट आई डू

लेखक : रघुराम जी राजन
अनुवाद : प्रभात रंजन
प्रकाशक : हार्पर कोलिंस पब्लि.
रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने अपनी पुस्तक में बेहद सहज और सरल तरीके से अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या की है। आर्थिक विकास के फॉर्मूले को भी पेश किया गया है।

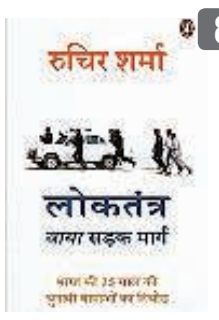

8 लोकतंत्र वाया सड़क मार्ग

लेखक : रुचिर शर्मा
अनुवाद : राजेश्वर वशिष्ठ
प्रकाशक : पेंग्विन रैंडम हाउस
लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये पुस्तक आई थी, इसकी जमकर चर्चा भी हुई थी। भारत की 25 साल की चुनावी यात्रा के निचोड़ का दावा करने वाली इस किताब में भारतीय लोकतंत्र के विभिन्न तंत्रों को परखा गया है।

9 मेरी गीता

लेखक : देवदत्त पटनायक
अनुवाद : सुमन परमार
प्रकाशक : रूपा पब्लिकेशंस
इस पुस्तक में देवदत्त ने गीता को अपने तरीके से अनूदित और व्याख्यायित किया है। इसमें गीता की मूल कहानी को बचाते हुए उसको आधुनिकता के संदर्भों के साथ पेश किया गया है।

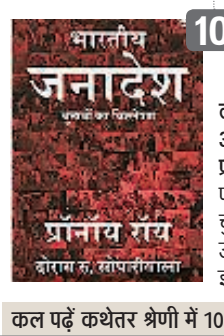

10 भारतीय जनादेश, चुनावों का विश्लेषण

लेखक : प्रॉनॉय रॉय, दोराब रु. सोपारीवाला
अनुवाद : मनजीत ठाकुर
प्रकाशक : पेंग्विन रैंडम हाउस
पहले आम चुनाव से लेकर देश में चुनाव किस तरह से होते रहे और उनमें क्या बदलाव आए, इस पुस्तक में इसका विश्लेषण है।

कल पढ़ें कथेतर श्रेणी में 10 बेस्ट सेलर किताबों के बारे में

यह दोनों देश के काम आए तो दुख नहीं गर्व होगा...

वतन के वीर ▶ शहीद औरंगजेब की मां के जज्बे को सलाम कर रहा है पूरा देश

गगन कोहली, राजौरी

कश्मीर में फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है। शौर्य चक्र विजेता शहीद औरंगजेब के पुंछ स्थित सलानी गांव में भी कर्फ्यू है। लेकिन यह गांव कश्मीर के दूसरे गांवों से जुदा है। देश के लिए जज्बा रखने वाले सिपाहियों, सैनिकों और वतन पर कुर्बान हो जाने वाले शहीदों का गांव। यह औरंगजेब जैसे बेटे और राज बेगम जैसी मां का गांव है। ऐसी मां जिसने एक बेटे की शहादत के बाद दो और बेटों को देश सेवा में समर्पित कर दिया। वह दो छोटे बेटों को भी सैनिक बनाना चाहती हैं। कुछ दिन पहले जब दैनिक जागरण की टीम सलानी पहुंची तो यहां के हर घर में ऐसा जज्बा देखने को मिला।

इस इलाके के 100 से अधिक युवक सेना में शामिल हो चुके हैं। इन्हीं में राज बेगम के तीन बेटे भी शामिल हैं, जबकि एक बेटा (राइफलमैन औरंगजेब) शहीद हो चुका है। पांचवां बेटा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। गत वर्ष औरंगजेब की शहादत हुई थी। आतंकियों ने धोखे से अगवा कर उन्हें मार डाला था। हालही औरंगजेब की मां राज बेगम की वह तस्वीर लोगों के दिलों में उतर गई, जिसमें वह अपने दो बेटों को सेना में भर्ती होने के बाद माथा चूमते हुए आशीष दे रही हैं।

इस ममतामयी और साहसी मां ने दैनिक जागरण से कहा, ऐसा करते हुए न कोई डर था और न शिकन, बस था तो फख्र। मैंने बेटों से कहा कि मेरे दूध की लाज रखना...। भावुक कर देने वाला दृश्य था वह। मां का जज्बा देख पूरा देश एक सुर में कह रहा था कि अगर हर मां ऐसी हो तो देश का दुश्मन आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाएगा। बेटों को सेना की वर्दी में देख पिता का सीना भी गर्व से चौड़ा था।

- एक लाड़ला देश पर गंवाया तो मां ने वतन के नाम कर दिए दो और बेटे
- शौर्य चक्र विजेता शहीद औरंगजेब के गांव सलानी से प्रेरक रिपोर्ट

शौर्य चक्र विजेता शहीद औरंगजेब का फाइल फोटो। जागरण आर्काइव

हाल ही सेना में भर्ती हुए शहीद औरंगजेब के दोनों भाई तारिक और शब्बीर को प्यार और आशीर्वाद देतीं उनकी मां राज बेगम। जागरण

औरंगजेब की ही तरह तारिक और शब्बीर में भी देशप्रेम कूट-कूट कर भरा हुआ है। यह इन युवाओं के जज्बे के कारण ही है कि जहां पहले कभी आतंकवाद की तूती बोलती थी, आज हमारे गांव की तरफ आतंकवादी आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं कर पाते हैं।

- मुहम्मद खालिक चौहान, सरपंच, सलानी गांव

शहीद औरंगजेब के पिता व दादा भी सेना में थे। माता पिता ने अपने दो और बेटों की सेना में भेजकर आतंक के पैरोकारों को संदेश दिया है कि उनके दिन लद चुके।

- ब्रिगेडियर (रिटा.) अनिल गुप्ता

14 जून 2018 को कश्मीर में आतंकवादियों ने सेना के राइफलमैन औरंगजेब का तब धोखे से अपहरण कर लिया था जब वह ईद मनाने अपने घर जा रहे थे। आतंकियों की आंखों में आखें डालकर और बिना डरे, बिना सिर झुकाए वह शहीद हो गए। उनकी इस निडरता को देख मरणोपरांत उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक साल भर बाद जुलाई, 2019 में औरंगजेब के दो छोटे भाई सेना में भर्ती हो गए। शहीद की मां राज बेगम ने दोनों लाड़लों तारिक और शब्बीर का माथा चूम मानो उन्हें देश के नाम करने का एलान कर दिया। राज बेगम कहती हैं, मैंने अपना बेटा खोया पर मुझे उसकी वीरता और देश के लिए उसके जज्बे पर गर्व है। उसकी मां होने पर मैं फख्र महसूस करती हूं। अब मैंने अपने दो और बेटे देश के नाम कर दिए हैं। अगर यह दोनों भी देश के काम आ गए तो मुझे गम नहीं गर्व होगा। मैं दो छोटे बेटों को भी सैनिक बनाऊंगी। तारिक और शब्बीर के पिता जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के पूर्व सिपाही मुहम्मद हनीफ ने कहा, मेरे बेटे ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मेरे बाकी बेटे भी देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। हम आतंक का अंत चाहते हैं। बड़ा बेटा मुहम्मद कासिम 12 साल से सेना में सेवाएं दे रहा है। अब दो और बेटे सेना में शामिल हो गए हैं।

पुंछ जिले का सलानी गांव आज देशप्रेम की मिसाल बन गया है। खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे गांव के 55 युवा नौकरी छोड़ कर आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए अपने गांव लौट आए। तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी सलानी गांव पहुंचे थे और लोगों के जज्बे को सलाम किया था।

एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए तैयार किए 'रेजा' से बने खास परिधान

ओपी वशिष्ठ, रोहतक

इस विशेष फैब्रिक 'रेजा' से बने कपड़ों की खूबी यह है कि इनसे किसी तरह की एलर्जी नहीं हो सकती है। गर्मी और बारिश के मौसम में यह शरीर के तापमान को 5 डिग्री तक कम रखता है। एक खूबी यह भी कि यह परिधान एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए भी माकूल है। दरअसल, एसिड अटैक पीड़िताओं को सामान्य कपड़ों से एलर्जी हो जाती है। खासकर सिंथेटिक कपड़ों से, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है। अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर ललिता चौधरी ने रेजा फैब्रिक के जरिये इसका समाधान ढूंढ निकाला है।

इस फैब्रिक से बने परिधान त्वचा को एलर्जी और जलन से तो बचाएंगे ही, गर्मी के मौसम में ठंडक भी प्रदान करेंगे। गत दिनों रोहतक, हरियाणा में आयोजित कार्यक्रम में एसिड अटैक पीड़िताओं ने रेजा फैब्रिक से निर्मित परिधानों में कैटवॉक किया, जिसकी हर किसी ने सराहना की। ललिता बताती हैं कि रेजा हथकरघा कला का ही प्राचीन फैब्रिक है, जो 150 वर्ष पहले भारत में बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन यह कला धीरे-धीरे लुप्त होने लगी। रेजा फैब्रिक ऑर्गेनिक कॉटन है। एंटी बैक्टीरियल और त्वचा के लिए मुफीद होने के कारण उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनको कपड़ों से एलर्जी होती है, खासकर एसिड अटैक पीड़िताएं। पिछले दिनों मेरी मुलाकात एसिड अटैक पीड़ित युवतियों से हुई, जो आगरा में कैफे भी चलाती हैं।

इन पीड़िताओं ने बताया कि बाजार में मिलने वाले सामान्य परिधान उनकी तकलीफ को बढ़ाते हैं। एलर्जी हो जाती है। जलन होती रहती है। उनकी समस्या सुनने के बाद मैंने रेजा फैब्रिक से बने परिधान पहनने की सलाह दी।

स्वस्थ समाज

रेजा की यह है खासियत

- जीरो कार्बन वाला कपड़ा।
- गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहने वाला फैब्रिक।
- एंटी बैक्टीरियल और स्किन-फ्रेंडली।
- अल्ट्रावॉयलेट किरणों से बचाता है।
- पूरी तरह हैंडमेड, फैलाव बेहतर।
- इस्तेमाल और रखरखाव में आसानी।

पीड़िताओं के साथ फैशन डिजाइनर ललिता चौधरी (मध्य में)। जागरण

प्रयोग के तौर पर कुछ ड्रेस बनाई भीं, जिनसे उनको काफी आराम महसूस हुआ।

ललिता चौधरी ने बताया कि एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए वह रेजा फेब्रिक से तैयार ड्रेस पर कोई मुनाफा नहीं कमाएंगी। केवल धागे की कीमत ही उनसे वसूल की जाएगी। क्योंकि धागा गांव में विशेष रूप से तैयार करवाया जाता है। यह बाजार में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने लखनऊ, आगरा और रोहतक की एसिड अटैक पीड़िताओं को कुछ परिधान उपहार के तौर पर भेंट किए। एसिड अटैक पीड़िता रीतू सैनी ने कहा कि रेजा फैब्रिक से बने परिधान उनके लिए बड़ी राहत पहुंचाने वाले साबित हुए हैं।

केरल सरकार ने किया अनुबंध : रेजा फेब्रिक के फायदों को देखते हुए केरल सरकार ने रोहतक की फैशन डिजाइनर ललिता चौधरी के साथ अनुबंध किया है। केरल सरकार के अनुसूचित जाति व जनजाति विभाग के साथ हुए इस अनुबंध के तहत ललिता स्थानीय युवतियों को रेजा कला का प्रशिक्षण देंगी। इससे आर्गेनिक कॉटन को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को कुटीर उद्योग।

पीएम मोदी की भी पसंद : बता दें कि ललिता चौधरी द्वारा रेजा से तैयार किए गए परिधान न्यूयॉर्क फैशन वीक में भी अपना जलवा बिखेर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, दुबई, आबू धाबी में भी रेजा फैब्रिक की खासी मांग शुरू हो गई है। रेजा स्टोल के कायल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। पिछले दिनों जापान के प्रधानमंत्री जब भारत दौरे पर आए तो मोदी ने भारत के रेजा फैब्रिक से तैयार स्टोल धारण किया था, जिसे ललिता चौधरी ने ही तैयार किया था।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

बीहड़ से खोज निकाले 'मातृवेदी' के बलिदानी

बचपन में सुना था कि प्रथम स्वाधीनता संघर्ष में पुरखे बस्ती के महुआ डाबर से विस्थापित होकर बगल के गांव नकहा में आ बसे थे। घर के बुजुर्गों से सुन रखा था कि दो अंग्रेज मारे गए तो गुस्साई सरकार ने गांव फूंक डाला था। क्रांति की कहानियों से जुड़ा बचपन का रिश्ता वक्त के साथ जवान होता गया। दिलचस्पी बढ़ी तो चंबल के गुमनाम क्रांतिकारी संगठन 'मातृवेदी' के बारे में पता चला। आजादी के गुमनाम दीवानों के बारे में जानने के लिए उत्साही युवा शाह आलम साइकिल से बीहड़ के सफर पर निकल पड़े। औरैया से लेकर कानपुर तक कई इलाकों में 2700 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर इस गुमनाम संगठन के क्रांतिकारियों की कई कहानियां ढूंढ निकालीं। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दैनिक जागरण इन क्रांतिवीरों की कहानियां आज से शृंखलावार आप तक पहुंचा रहा है...।

कहानी-1

आशुतोष मिश्र, लखनऊ

भाइयो आगे बढ़ो... फोर्ट विलियम छीन लो... जितने भी अंग्रेज सारे, एक-एक बीन लो...। 'मातृवेदी' का यह नारा संगठन की आक्रामकता और जज्बे का बोध कराने के लिए काफी है। 20वीं सदी के दूसरे दशक में चंबल के साथ यूनाइटेड प्रोविंस (उत्तर प्रदेश) के 40 से ज्यादा जिलों में मातृवेदी की ताकतवर उपस्थिति थी। 1918 में कई शहरों की दीवारों पर संगठन की ओर से रातों में पर्चे चिपकाए गए कि 'अंग्रेजों को मार डालो और आजाद रहो'। इन पर्चों से लोगों के मन में क्रांति की जो चिंगारी पनपी थी, उसे क्रांतिकारी साहित्य से शोला बनाने की कोशिश हुई तो अंग्रेजों की नींद उड़ गई।

'अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली' शीर्षक से लिखी गई यह पुस्तक चर्चा में आई तो अंग्रेजों ने 24 सितंबर, 1918 को आनन-फानन उत्तर प्रदेश में इसे बैन कर दिया। मातृवेदी का इतिहास टटोलने वाले लघु फिल्म निर्माता शाह आलम बताते हैं यह वही पुस्तक है जिसके बैक पेज पर पहली बार जगदंबा प्रसाद हितैषी के गीत शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले..., का प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक के प्रकाशन की कहानी बेहद रोचक है। प्रताप अखबार में चंपारण के किसानों की पीड़ा उकेरने वाले पत्रकार पीर मुहम्मद मुनिस ने इसे लिखा। क्रांतिकारी गंगा सिंह ने इस किताब के लिए कोटेशन जुटाए और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने छपवाने की जिम्मेदारी उठाई।

पुस्तक में सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजी शासन को देश से उखाड़ फेंकने की सीख नौजवानों को दी गई थी। इसका प्रकाशन कराने के लिए बिस्मिल जी ने अपनी मां मूलमती जी से व्यापार के बहाने 200 रुपये लिए थे। पुस्तक की बढ़ती लोकप्रियता की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंची तो इसे बैन कर दिया गया। जब यह पुस्तक उप्र में प्रतिबंधित हो गई तो मातृवेदी के साहित्य प्रचार विभाग ने इसे दिल्ली में होने जा रहे कांग्रेस के अधिवेशन में बेचने की योजना बनाई। मकसद पुस्तक से युवाओं को क्रांति के पथ पर लाना और संगठन के लिए धन जुटाना था। एटा जिले के नगला डरू गांव में 1898 को जन्मे संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर शिवचरण लाल शर्मा, रामप्रसाद बिस्मिल, देवनारायण, सोमदेव व शिवचरण के बड़े भाई कालापानी की सजा काटकर आए रामचरण लाल शर्मा इसके लिए दिल्ली आए। अधिवेशन में कांग्रेसी साहित्य के स्टॉल के बगल में इन्होंने स्टॉल लगाया। तीन अक्टूबर, 1918 को इस पुस्तक को दिल्ली में भी बैन कर दिया गया। तब स्टॉल पर पुलिस का छापा पड़ा था। बिस्मिल और कुछ अन्य साथियों को भगाकर शिवचरण लाल शर्मा ने गिरफ्तारी दी। सोमदेव व देवी दयाल भी गिरफ्तार हुए। बड़ी संख्या में किताब की प्रतियां जब्त कर ली गईं।

वो किताब जिसने उड़ा दी अंग्रेजों की नींद

- मां से व्यापार के नाम पर 200 रुपये लेकर रामप्रसाद बिस्मिल ने छपवाई पुस्तक
- 'अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली' किताब को कर दिया गया था बैन

मातृवेदी के बलिदानी

- 'आजाद हिंद सरकार' के समानांतर चंबल में मातृवेदी संगठन देश की आजादी के लिए लड़ रहा था
- इन गुमनाम क्रांतिवीरों के देशप्रेम को बयां करतीं हैरतअंगेज कहानियां, आज से शृंखलावार

राम प्रसाद बिस्मिल। जागरण आर्काइव

शाह आलम। जागरण

संगठन में 500 घुड़सवार, 2000 पैदल सिपाही

'मातृवेदी' का जिक्र प्रभा पत्रिका में छपे रामप्रसाद बिस्मिल के लेख में मिलता है। कमांडर इन चीफ गेंदालाल दीक्षित की अगुआई वाला यह संगठन कई विभागों में बंटा था। संगठन के पास 500 घुड़सवार, 2000 पैदल सिपाही और हथियारों का भारी जखीरा था। कोष में आठ लाख से अधिक संपत्ति थी। दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में गठित 'आजाद हिंद सरकार' के समानांतर चंबल में यह संगठन देश की आजादी के लिए लड़ रहा था।

जिस बाघिन की दहाड़ से दहल जाता था जंगल, अब है लाचार

संजय कुमार शर्मा, उमरिया : जिसकी दहाड़ से कभी जंगल दहल जाया करता था। दूसरे जंगली जानवरों के कदम ठिठक जाया करते थे। वह बाघिन महामन मां बुढ़ापे के चलते इतनी लाचार है कि अपनी गर्दन तक मुश्किल से उठा पा रही है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में महामन मां के नाम से प्रसिद्ध हुई बाघिन-23 ने प्रदेश के जंगलों के दूसरे बाघों के मुकाबले सबसे ज्यादा उम्र पाने का कीर्तिमान स्थापित तो कर लिया, लेकिन बुढ़ापे की मार ने उसे इतना असहाय बना दिया है कि अब वह खुद से कुछ भी खाने की स्थिति में भी नहीं है।

बाघिन महामन मां 17 साल की हो चुकी है और इसके सारे दांत और नाखून भी गिर गए हैं। पिछले दो सप्ताह से तो यह अपनी जगह से खिसक भी नहीं पा रही है। बड़ी मुश्किल से वह अपनी गर्दन उठा पाती है और सिर्फ आंख खोल कर आसपास देख लेती है। खाने-पीने में भी लाचार होने की वजह से उसको ऊर्जा व ताकत के लिए दवाएं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। महामन मां इतनी निस्तेज हो गई है कि अब इसके पास जाने के लिए इसे बेहोश भी नहीं किया जा रहा है। यानी इसके होश में रहते ही इसके पास जाकर आसानी से दवाएं दी जा रही हैं।

राजाजी और दो वन प्रभागों में तीनों गुलदारों की जहर देकर हुई थी हत्या

जागरण संवाददाता, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) : हरिद्वार वन प्रभाग, राजाजी टाइगर रिजर्व व लैंसडौन वन प्रभाग की लालढांग रेंज में तीन गुलदारों की मौत के मामले में लैंसडौन वन प्रभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले की जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि गुलदारों को जहर देकर मारा गया था। बताया जा रहा है कि मामले में लैंसडौन वन प्रभाग की एसओजी टीम ने लालढांग क्षेत्र से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। दो अगस्त को लैंसडौन वन प्रभाग की लालढांग रेंज, हरिद्वार वन प्रभाग की चिड़ियापुर रेंज और राजाजी टाइगर रिजर्व की रवासन रेंज में अलग-अलग स्थानों पर तीन गुलदार मृत पाए गए। एक साथ तीन गुलदारों के शव मिलने से महकमे में हड़कंप मच गया।

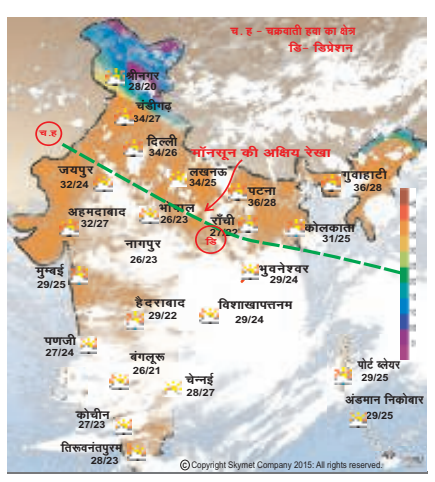

मौसम विशेष

दिल्ली, पंजाब व हरियाणा में उमस के साथ मौसम गर्म रहेगा। कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। राजस्थान के पूर्वी भागों में अनेक स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा जारी रहेगी। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	27/24/ए	अहमदाबाद	31/27/ए
कोलकाता	33/26/ए	बड़ौदा	30/26/ए
चेन्नई	38/29/ए	नागपुर	27/22/ए
हैदराबाद	31/23/ए	इन्दौर	28/24/ए
बंगलूरु	27/20/ए	रांची	34/26/ए
गुवाहाटी	31/28/ए	जमशेदपुर	36/28/आंवा
शिलांग	27/23/ए	पटना	34/28/ए
गंगटोक	18/09/ए	पुणे	23/22/आंवा

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

गुरुवार 8 अगस्त 2019

14

www.jagran.com

महात्मा गांधी ने शुरू किया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन

महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। यह आंदोलन देश भर में तेजी से बढ़ा। अंग्रेजों ने करीब 14 हजार भारतीयों को जेल में डाल दिया।

खाड़ी युद्ध की पृष्ठभूमि हुई तैयार

1990 में आज ही इराक के तत्कालीन तानाशाह सद्दाम हुसैन ने युद्ध में कुवैत को हराकर अपना 19वां प्रांत बना लिया। इराक को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की सेनाओं ने सद्दाम पर हमला बोला और कुवैत को आजादी दिलाई।

खयाल, ठुमरी और दादरा में प्रवीण थीं सिद्धेश्वरी देवी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज के ही दिन 1908 में सिद्धेश्वरी देवी का जन्म हुआ था। डेढ़ वर्ष की अवस्था में उनके मां-पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मौसी और मशहूर गायिका राजेश्वरी देवी ने लालन-पालन किया। उन्हें संगीत की प्राथमिक शिक्षा देवास के रज्जब अली और लाहौर के इनायत खान ने दी। लेकिन वह गुरु बड़े रामदास को मानती रहीं। गुरु रामदास ने ही उनका नाम सिद्धेश्वरी देवी रखा था। खयाल ठुमरी और दादरा, चैती कजरी गायन में उनका अंदाज जुदा था। वर्ष 1966 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनकी मृत्यु 18 मार्च 1977 को नई दिल्ली में हुई।

इधर-उधर की

कभी देखा-सुना है ऐसा अनोखा रक्तदाता

सिडनी, एजेंसी : ऑस्ट्रेलिया के जेम्स हैरीसन का नाम पूरा देश जानता है। वहां इन्हें 'मैन विद द गोल्डेन आर्म' कहा जाता है। यह ख्याति इनको 24 लाख शिशुओं की जान बचाने के लिए मिली है। दरअसल पिछले साठ साल से यह व्यक्ति हर हफ्ते लगातार रक्तदान कर रहे हैं। इनके खून में रोगों से लड़ने वाली विशिष्ट प्रतिरोधी क्षमता है। जिसके द्वारा वैज्ञानिकों ने रीसस रोग से लड़ने के लिए एंटी डी नामक टीका बनाया है। डॉक्टरों के अनुसार रीसस रोग में गर्भवती महिला के खून की एंटीबॉडी पेट में पल रहे बच्चे की रक्त कोशिकाओं को खत्म कर देती है। इस हालात में बच्चे के दिमाग पर गंभीर असर हो सकता है या किन्हीं मामलों में मौत भी हो सकती है। लिहाजा इस रोग से लड़ने के लिए हैरीसन का खून रामबाण साबित हो रहा है। डॉक्टर उनकी प्लाज्मा का इस्तेमाल करके टीका बनाते हैं।

शोध अनुसंधान

महिलाओं में अल्जाइमर का कारण बन सकता है तनाव

प्रौढ़ उम्र की महिलाओं में तनाव आगे चलकर अल्जाइमर का कारण बन सकता है। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। अब तक इसका कोई कारगर इलाज उपलब्ध नहीं है। ताजा शोध में पाया गया कि तनाव वाले हार्मोन दिमाग की सेहत पर असर डालते हैं। यह असर महिला और पुरुष में अलग-अलग होता है। नतीजों के मुताबिक, तनावग्रस्त छह में से एक महिला को 60 की उम्र के बाद अल्जाइमर का खतरा रहता है। वहीं, पुरुषों में यह दर 11 में एक की पाई गई। अध्ययन में 900 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। इनमें से 63 फीसद महिलाएं थीं। सभी की औसत आयु 47 साल थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि कभी अचानक किसी परिस्थिति में तनाव बढ़ने से प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि तनाव कम होने पर हार्मोन का स्तर सामान्य हो जाता है। लगातार तनाव और चिंता से ग्रस्त रहने वालों के लिए खतरा बढ़ जाता है। - आइएएनएस

स्तन कैंसर का खतरा कम कर सकते हैं पोल्ट्री उत्पाद

हालिया शोध में सामने आया है कि रेड मीट खाने से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जबकि पोल्ट्री उत्पाद इस खतरे को कम कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने 7.6 साल तक 42,012 महिलाओं पर अध्ययन किया। इसमें विभिन्न प्रकार के मांस और उनको पकाने के तरीके से सेहत पर पड़ने वाले असर को परखा गया। इस दौरान 1,536 महिलाओं में स्तन कैंसर पाया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि सबसे ज्यादा रेड मीट खाने वाली महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा सबसे कम रेड मीट खाने वाली महिलाओं की तुलना में 23 फीसद ज्यादा रहता है। वहीं पोल्ट्री उत्पादों के मामले में स्थिति विपरीत रही। ज्यादा पोल्ट्री उत्पाद खाने वाली महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा 15 फीसद तक कम पाया गया। पोल्ट्री उत्पादों का सेवन शुरू करने वाली महिलाओं में भी खतरा कम देखा गया। - एएनआइ

रोजाना कई साइबर हमलों का सामना करते हैं बैंकिंग संस्थान

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- चारों ओर से मंडराते हैकिंग के खतरों से बचना संस्थानों के लिए होता है बड़ी चुनौती
- छोटी-सी खामी के चलते हैकिंग का शिकार हो गया अमेरिका का कैपिटल वन बैंक

साइबर अपराध पूरे विश्व के लिए चुनौती है। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन : बढ़ते डिजिटलाइजेशन के साथ साइबर हमले दुनियाभर के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। बड़ी बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों को भी हर दिन हजारों साइबर हमले झेलने पड़ते हैं। इन हजारों कोशिशों में से कभी-कभार कोई हैकर सफल भी हो जाता है और डाटा में सेंध लगा देता है।

हाल ही में अमेरिका का कैपिटल वन बैंक साइबर हमले की चपेट में आया था। इसमें आरोपित ने बैंक के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की व्यक्तिगत सूचनाएं चुरा ली थीं। इस बैंक को अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में शुमार किया जाता है। ज्यादातर मामलों में हैकर साइबर हमले या तो किसी को व्यक्तिगत रूप से परेशान करने के लिए करते हैं या फिर खुफिया सूचनाओं को चुराकर उन्हें बड़े दामों पर बेच देते हैं। ऐसे में किसी भी देश के लिए अपने खुफिया तंत्र को बचाना एक बड़ी चुनौती है। किसी भी तंत्र को हैक करने के लिए हैकरों को उसकी सबसे कमजोर कड़ी का पता लगाने की जरूरत होती है और कुछ मामलों में वह उसका पता लगा लेते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में इस वर्ष अब तक वित्तीय संस्थानों पर 3,494 साइबर हमले हो चुके हैं।

अमेरिका के संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि सिएटल में अमेजन के लिए काम करने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेज थॉमसन ने कैपिटल वन के डाटा में सेंध लगाई थी। उसने यह पता लगा लिया था कि कैपिटल वन अपने कंप्यूटर नेटवर्क के लिए किस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। इसके बाद थॉमसन ने क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन समेत हजारों उपभोक्ताओं की सूचनाओं को डाउनलोड कर लिया था।

छोटी सी गलती भी पड़ती है भारी : साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करने वाली संस्था एफएआइआर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष जैक जोंस ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक छोटी सी गलती भी बड़ी बन जाती है। लेकिन सच यह भी है कि कई बार बड़े मामलों में छोटी गलतियां हो भी जाती हैं। हर बड़े संस्थान पर कई ओर से खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। इसी उधेड़बुन में कहीं-कहीं किसी मोर्चे पर खामी रह जाती है। उदाहरण के लिए पेमेंट सेवा देने वाली कंपनी मास्टरकार्ड की सुरक्षा को भेदने के लिए हैकर दिन में करीब चार लाख 60 हजार बार प्रयास करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते। कैपिटल वन बैंक पर हुआ साइबर हमला बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए चेतावनी है। इससे सीख लेकर संस्थान भविष्य में ऐसे खतरों से बच सकते हैं।

कई रास्ते हैं हैंकिंग के : कुछ मामलों में हैकर संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों के कमजोर पासवर्ड का लाभ उठाकर नेटवर्क को हैक कर लेते हैं। कभी-कभी ईमेल भेजकर भी नेटवर्क में सेंध लगाई जाती है। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होना भी हैकर्स का रास्ता आसान कर देता है। कभी-कभी कुछ घंटे की मेहनत में ही हैकर सेंध लगा देते हैं, तो कभी इसमें महीनों का वक्त लग जाता है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है कि संस्थान छोटी-बड़ी हर बात पर ध्यान दें।

अच्छे कारोबारी बनना चाहते हैं तो लें पर्याप्त नींद

- बिजनेस वेंचरिंग में प्रकाशित हुआ शोध, अच्छी नींद से आते कारोबार के लिए अच्छे विचार

स्वास्थ्य के लिए जरूरी है नींद। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, एएनआइ : एक नए अध्ययन के मुताबिक, अच्छी नींद से न केवल कारोबार के लिए अच्छे विचार मन में आते हैं बल्कि उनके मूल्यांकन और उनकी व्यवहार्यता का पता लगाने में आसानी रहती है। असिस्टेंट बिजनेस प्रोफेसर जेफ गिश ने कहा कि जो उद्यमी नींद को कम तवज्जो देते हैं और सोचते हैं कि अपने काम में सफल होने के बाद ही उन्हें अच्छी नींद आती है। शायद वे गलत होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए पहले पूरी नींद जरूरी होती है, नहीं तो हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए 24 घंटे काम करने वाले उद्यमियों के लिए जरूरी है कि वह रात में अच्छी नींद लें। यह अध्ययन बिजनेस वेंचरिंग में प्रकाशित हुआ है।

पिछले कई अध्ययनों में नींद और नौकरी के प्रदर्शन के बीच एक संबंध पाया गया है। लेकिन नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने नींद और संज्ञानात्मक कौशल (कॉनिटिव स्किल) के बीच एक कड़ी खोजी है, जो उद्यमियों के विचारों का बेहतर मूल्यांकन करने में सहायक हो सकते हैं।

ज्यादातर उद्यमी अपने व्यवसाय की सफलता का मूल्यांकन अपने अनुभव और व्यावसायिक ज्ञान के आधार पर करते हैं, लेकिन नींद भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो किसी भी व्यवसाय की सफलता या असफलता तय कर सकती है। इस अध्ययन के लिए दुनियाभर के 700 उद्यमियों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों से उनके सोने के तरीके, समय आदि से जुड़े सवाल पूछे।

जेफ गिश ने कहा कि अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि जिन प्रतिभागियों ने रात में कम से कम सात घंटे की नींद ली थी, वह अन्य की अपेक्षाकृत ज्यादा स्वस्थ्य थे और उनका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। लेकिन जिन लोगों ने कम नींद ली उनके स्वास्थ्य पर तो इसका असर साफ देखा जा सकता था और ऐसे लोग हमेशा बेचैन ही रहते हैं। जिसका असर उनके व्यवसाय पर भी पड़ता है। गिश ने कहा कि अच्छी नींद से न केवल स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि हमारे काम पर भी इसका असर देखा जा सकता है।

आविष्कार ▶ आइआइटी भिलाई के प्रोफेसर ने विकसित किया नया फॉर्मूला

हजार डिग्री ताप पर भी नहीं फटेगी बैट्री

फ्लोरोपॉलीमर्स और टेफलॉन के मिश्रण से तैयार किया लिक्विड

दीपक अवस्थी, रायपुर

रायपुर : आइआइटी भिलाई के प्रो संजीब बनर्जी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आइआइटी) भिलाई के प्रो. संजीब बनर्जी ने ऐसा फॉर्मूला विकसित किया है, जिससे तैयार बैट्री अधिक तापमान में भी काम करेगी। वह अधिक तापमान में भी नहीं फटेगी। इस तकनीक का उपयोग मोबाइल बैट्री में करने पर मोबाइल को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।

नई तकनीक से बैट्री में डाले जाने वाले केमिकल को इतना शक्तिशाली बना दिया गया है कि वह आसानी से एक हजार डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी काम करेगी। यह फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए भी क्रांति से कम नहीं है। यह मोबाइल और वाहन की बैट्री के चार्जिंग समय को भी कम कर देगा। अभी इनकी बैट्री को फुल चार्ज करने में एक से दो घंटे का समय लगता है, जबकि नई तकनीक के इस्तेमाल के बाद केवल आधे घंटे में ही शक्तिशाली लिक्विड बैट्री को चार्ज कर देगा। प्रो. बैनर्जी ने इस लिक्विड को फ्लोरोपॉलीमर्स और टेफलॉन से तैयार किया है, जो अधिक से अधिक तापमान को आसानी से सहन कर लेता है।

कुकर को देख किया ईजाद : डॉ. बैनर्जी ने बताया-रिसर्च की शुरुआत अंतरिक्ष अभियान के लिए लिक्विड बनाने से हुई थी। हमें अंतरिक्ष के लिए ऐसा लिक्विड तैयार करना था, जो एक हजार डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर सके। उसी दौरान मैंने देखा कि कुकर 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आसानी से सहन कर लेता है। कारण होता है कि उसमें टेफलॉन की मामूली परत चढ़ाई जाती है। उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर फ्लोरोपॉलीमर्स और टेफलॉन को मिलाकर लिक्विड तैयार किया। फिर प्रयोग किया तो एक हजार डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का लिक्विड पर कोई असर नहीं हुआ। उसी दौरान देखा कि उक्त लिक्विड से बैट्री भी बनाई जा सकती है, जो आसानी से चार्ज हो जाएगी।

50 सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान में फट जाती है बैट्री : मोबाइल की बैट्री 20 से 30 और इलेक्ट्रिकल वाहन की बैट्री 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर पाती है। हालांकि, यह एक आदर्श स्थिति में होता है। अलबत्ता, मोबाइल में अभी जिन बैट्रियों का उपयोग हो रहा है, वह आसानी से पचास डिग्री तक तापमान सहन कर लेती हैं। और इसी तरह वाहन में उपयोग होने वाली बैट्रियां करीब 70 डिग्री तक। इसके ऊपर तापमान होने पर बैट्री फट जाती हैं।

ये है चुनौती : डॉ. बैनर्जी ने बताया कि लिक्विड को जिस कंपोनेंट (बॉक्स) में डाला वह 260 सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान सहन नहीं कर पाता। अब ऐसे कंपोनेंट बनाने की तैयारी चल रही है, जो एक हजार सेंटीग्रेड का तापमान आसानी से सहन कर सके।

ये होंगे फायदे, इनसे मिलेगी मुक्ति

- अभी तक देश में 80 प्रतिशत बैट्री ताइवान और चीन से मंगवाई जाती हैं
- चीन और ताइवान की बैट्री में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, जो पृथ्वी के लिए हानिकारक है
- देश में बैट्री का 80 प्रतिशत कारोबार स्थापित हो जाएगा
- इलेक्ट्रोलाइट की अपेक्षा फ्लोरोपॉलीमर्स, टेफलॉन पृथ्वी को कम करता है नुकसान
- देश में इलेक्ट्रिकल वाहन के मूल्य में होगी कमी
- इलेक्ट्रिकल वाहन में आधी कीमत की लगेगी बैट्री

(नोट : जैसा डॉ. संजीब बैनर्जी ने दावा किया)

सारडीन के इलाकों की पहचान के लिए तैयार किया जाएगा नया मॉडल

विशेषज्ञ सीएमएफआरआइ में एकत्र हुए थे।

कोच्चि, प्रेट्र : सारडीन मछलियों के व्यापार में गिरावट दर्ज किए जाने के बाद वैज्ञानिक अब इस मछली के व्यापार को बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। बीते दिनों सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआइ) में हुए एक आयोजन में वैज्ञानिकों ने कहा कि जल्द ही एक ऐसा मॉडल विकसित किया जाएगा जो बताएगा कि समुद्र में किन स्थानों पर सारडीन मछलियों की प्रचुरता है। सारडीन हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये मछलियां मछुआरों के लिए आमदनी का सबसे अच्छा जरिया हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इसके व्यापार पर असर पड़ रहा है। इसके कारणों की जांच के लिए मंगलवार को देश के विभिन्न शोध संस्थानों के सीएमएफआरआइ के वैज्ञानिक ईएम अब्दुस्समद ने कहा कि हाल के अध्ययनों में इस बात की ओर इशारा करते हैं जलवायु परिवर्तन और विशेष रूप से अलनीनो के कारण का भी आयल सारडीन पर प्रभाव पड़ता है। अलनीनो के अलावा समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि, समुद्र की उत्पादकता में वृद्धि और उतार-चढ़ाव जैसे विभिन्न समुद्री घटनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जो सारडीन को प्रभावित करती है।

प्रेम का उत्सव है किक्सी

चीन में बुधवार को नौजवानों ने किक्सी उत्सव मनाया गया। इस समारोह को यहां वैलेंटाइन-डे का दर्जा प्राप्त है। इस दौरान नवयुवक खास तौर से हान-वंश की वेशभूषा में सजकर अपने साथी से प्रेम का इजहार करते हैं। जिनु और निलुंग नाम के दो प्रेमियों की याद में यह दिन चीनी कलेंडर के मुताबिक वर्ष के सातवें महीने के सातवें दिन मनाया जाता है। रायटर

स्क्रीन शॉट

'छिछोरे' में ताहिर का किरदार नितेश के सीनियर से प्रेरित

'दंगल' फेम नितेश तिवारी की फिल्म 'छिछोरे' में ताहिर राज भसीन खिलाड़ी की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें शुरुआत में इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका किरदार डेरेक नितेश की असल जिंदगी में उनके इंजीनियरिंग कॉलेज के सीनियर से प्रेरित है। नितेश ने वर्ष 1996 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे (आइआइटी-बी) से मेटलर्जी ऐंड मैटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। 'छिछोरे' इंजीनियरिंग कॉलेज में उनकी यादों से प्रेरित है। नितेश के मन-मस्तिष्क पर डेरेक का बड़ा प्रभाव था। डेरेक जिस खेल में भी शामिल होते, उसमें हमेशा उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते थे। अपने खेल से उन्होंने छात्रावास और कॉलेज को गौरवान्वित किया था। नितेश चाहते थे कि उनकी फिल्म में यह किरदार हो, क्योंकि इससे उनका गहरा जुड़ाव रहा है। ताहिर बताते हैं कि यह सच है 'छिछोरे' में मेरा किरदार इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे निर्देशक के वास्तविक जीवन के सीनियर पर आधारित है। मुझे आइआइटी (बॉम्बे) ले जाने से पहले तक इसकी भनक नहीं थी। मूल डेरेक विद्रोही और स्पोर्ट्स चैंपियन के साथ ही करिश्माई भी थे। डेरेक की शैली आज भी हॉस्टल के गलियारों में किंवदंती है। कैंपस में डेरेक का नाम सभी कैफेटेरिया और गलियारों में स्पोर्ट्स अचीवर्स बोर्ड में दर्ज है। डेरेक का व्यक्तित्व और स्वैग के बारे में उन्होंने मुझे जो भी जानकारी दी, वह इस भूमिका के लिए मेरे लिए हथियार की तरह था। उम्मीद है कि असली डेरेक और उस समय के उनके बैचमेट्स को पर्दे पर मेरे द्वारा निभाई गई भूमिका से गर्व महसूस होगा।

शाह रुख की बेटी शॉर्ट फिल्म से करेंगी डेब्यू

बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान की बेटी सुहाना खान ने अभिनय की दुनिया की ओर कदम बढ़ा दिया है। वह जल्द ही अंग्रेजी शॉर्ट फिल्म 'द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू' में अभिनय करती नजर आएंगी। यह जानकारी फिल्म के निर्देशक और उनके सहपाठी थ्योडोर जिमीनो ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर जारी करते हुए दी है। सुहाना ने हाल में ही लंदन के एक कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली है और फिलहाल न्यूयॉर्क में एक्टिंग का कोर्स कर रही हैं। साथ ही अक्सर वह सोशल मीडिया पर अपने फोटो के जरिए भी चर्चा में रहती हैं। शाह रुख के बेटे आर्यन ने बीते दिनों रिलीज हॉलीवुड फिल्म 'द लायन किंग' में अपने पिता के साथ डबिंग की थी। हाल में दिए साक्षात्कार में शाह रुख ने इस बात का जिक्र किया था कि अच्छा कलाकार बनने के लिए सही प्रशिक्षण कितना जरूरी होता है। शायद यही वजह है कि पिता की सलाह पर अमल करते हुए सुहाना कड़ी मेहनत कर रही हैं।

यूरोप के सफर पर शाहिद

शाहिद कपूर अभिनीत फिल्म 'कबीर सिंह' बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है। लगता है कि फिल्म की सफलता का जश्न वह इन दिनों अपने भाई ईशान खट्टर, कुणाल खेमू और दो सहयोगियों के साथ यूरोप में मना रहे हैं। दरअसल, कुणाल खेमू ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर साझा की है। उसमें स्विट्जरलैंड के हिमालयी क्षेत्र से बाइक पर अपनी यात्रा शुरू करके इटली के डोलामाइट्स तक के सफर को उन्होंने शानदार अनुभव बताया है।

होगी सुविधा

भारतीय वैज्ञानिक के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने की तैयार, लोगों को संतुलित रूप से चलने में करेगी मदद

रोबोटिक छड़ी बन सकती है बुजुर्गों का सहारा

- आइईईई रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ अध्ययन

रोबोटिक छड़ी पारंपरिक छड़ी की जरूरत को कम कर सकती है। प्रतीकात्मक

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : जिन लोगों को चलने में परेशानी होती है या चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है उनके लिए एक भारतीय वैज्ञानिक के नेतृत्व शोधकर्ताओं की टीम ने एक विशेष डिवाइस तैयार की है। शोधकर्ताओं ने पारंपरिक छड़ी को रोबोटिक डिवाइस का रूप दिया है। अब बुजुर्ग और खास विकार वाले लोग इस डिवाइस को केवल छूने भर से आसानी से चल-फिर सकेंगे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के प्रोफेसर सुनील अग्रवाल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने पहली बार एक ऐसी रोबोटिक डिवाइस बनाई जो छड़ी का काम करेगी, जिसे स्पर्श करने मात्र से वह व्यक्ति से साथ-साथ चल पड़ती है।

आइईईई रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, चलने-फिरने में संतुलन बनाए रखने के लिए यह डिवाइस किसी साथी या छड़ी का जैसा आभास कराएगी। प्रोफेसर अग्रवाल, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में डाटा साइंस इंस्टीट्यूट के सदस्य भी हैं, ने कहा कि रोबोटिक छड़ी खासतौर पर बुजुर्गों के लिए फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि इसे न तो छड़ी की तरह उठाने की जरूरत है न ही किसी भी तरह से इसके उपयोग में हमारी ऊर्जा खत्म होती है। उन्होंने कहा कि इसे बनाने के लिए हमने एक केन (छड़ी) को घूमने वाले रोबोट से जोड़ा है, जो व्यक्ति के साथ-साथ आगे बढ़ती जाती है। अग्रवाल ने कहा कि इस पर एक सेंसर लगा होता है, जो व्यक्ति की लंबाई और उसके चलने के तरीके को भांप कर स्वयं भी उसी लय और गति के साथ आगे बढ़ता जाता है। शोधकर्ताओं ने इस रोबोटिक केन को 'कैनिन' नाम दिया है।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोएल स्टीन ने कहा कि यह लोगों को चलने में सहायता करने का एक नया तरीका है। खासतौर पर यह ऐसे लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है जो किसी विकार के कारण चलने-फिरने में असमर्थ हो गए हैं।

शोधकर्ताओं ने इस डिवाइस के परीक्षण के लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट तैयार किया और लोगों को रोबोटिक केन के सहारे विभिन्न प्रकार के वातारवरण में चलाया। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि विपरीत परिस्थिति में भी डिवाइस ने लोगों को सहारा दिया और उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के प्रोफेसर सुनील अग्रवाल ने दावा किया है 'हम अपने पहले परीक्षण में सफल हुए हैं। अब जल्द ही दूसरे चरण का परीक्षण भी किया जाएगा, जिसमें बुजुर्गों और खास विकारों वाले लोगों को इसकी मदद से चलाया जाएगा।' उन्होंने उम्मीद जताई है कि रोबिटिक छड़ी दूसरे चरण के परीक्षण में भी सफल रहेगी और आने वाले समय में जरूरत मंद लोग इसका प्रयोग कर पाएंगे।

'साहो' में जैकी श्रॉफ का निगेटिव किरदार

प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'साहो' के सभी किरदार एक-एक करके सामने आने शुरू हो गए हैं। अभी दो दिन पहले ही नील नितिन मुकेश की तस्वीर सामने आई थी और अब जैकी श्रॉफ दिलचस्प तस्वीर के साथ सामने आ गए हैं। बॉलीवुड के वरिष्ठ कलाकार जैकी श्रॉफ ने इस बहुभाषी फिल्म में निगेटिव किरदार निभाया है और जो तस्वीर सामने आई है, उसमें उनका लुक भी वैसा ही दिख रहा है। इस तस्वीर के साथ अभिनेता का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, 'इस एक्शन फिल्म में बेहतरीन किरदार निभाकर खुश हूं। इसमें मैं विलेन के किरदार में हूं, इसलिए मुझे न तो गाने की जरूरत पड़ी और न ही डांस की।' जैकी ने बताया, 'मेरा पहला प्रोजेक्ट 1982 में स्वामी दादा था, जिसमें मेरे साथ शक्ति कपूर थे। मैं हमेशा से फिल्मों में मजबूत किरदार करना चाहता था, जो प्रभावपूर्ण हो। यह हीरो का भी हो सकता है और निगेटिव भी।' उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म 'मिशन कश्मीर' को लोग अभी तक नहीं भूले होंगे, जिसमें मैंने विलेन का किरदार किया था। साथ ही, उन्होंने प्रभास के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने को भी खुद के लिए अनूठा लम्हा बताया। गौरतलब है कि जैकी श्रॉफ अपने जीवन में सभी का सम्मान करते हैं, चाहे वह स्पॉट ब्वॉय ही क्यों न हो। इसी वजह से बॉलीवुड में उन्हें 'डालिंग' के उपनाम से पुकारा जाता है।